EXAM GENIUS

Presents

MONTHLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

MAY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM Genius

UPSC SSC BANK RAILWAY STATE EXAMS

Ques: Mission SAKSHAM launched by RBI is primarily aimed at which sector?
प्रश्न: RBI द्वारा लॉन्च किया गया मिशन सक्षम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है?

A) Commercial Banks / वाणिज्यिक बैंक

B) Rural Banks / ग्रामीण बैंक

C) Urban Co-operative Banks / शहरी सहकारी बैंक

D) NBFCs / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

E) Payment Banks / पेमेंट बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra launched Mission SAKSHAM on April 28, 2026.

• RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 28 अप्रैल 2026 को मिशन सक्षम लॉन्च किया।

• Mission SAKSHAM (Sahkari Bank Kshamta Nirman) is a nationwide capacity-building initiative for Urban Co-operative Banks (UCBs).

• मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण पहल है।

• RBI will conduct training programmes (in-person and e-learning) covering around 1.40 lakh participants including board members, senior management, and IT staff.

• RBI लगभग 1.40 लाख प्रतिभागियों (बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन, IT कर्मचारी आदि) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

• The programmes will also be delivered in regional languages to ensure wider accessibility.

• कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे, जिससे अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

• The mission was designed in consultation with UCB umbrella organisations and cooperative federations.

• यह मिशन UCB के अम्ब्रेला संगठनों और सहकारी महासंघों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है।

• It was first announced in the Monetary Policy Statement on February 6, 2026.

• इसे पहली बार 6 फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति में घोषित किया गया था।

• The aim is to improve governance, compliance culture, and institutional strength in the UCB sector.

• इसका उद्देश्य UCB क्षेत्र में शासन, अनुपालन संस्कृति और संस्थागत मजबूती को बढ़ाना है।

• There are over 1,400 UCBs in India serving urban and semi-urban populations and promoting financial inclusion.

• भारत में 1,400 से अधिक UCBs कार्यरत हैं, जो शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Mission — SAKSHAM (Sahkari Bank Kshamta Nirman)

• मिशन — सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण)

• Meaning — "To make capable/competent"

• अर्थ — "सक्षम बनाना"

• Launch Date — April 28, 2026

• लॉन्च तिथि — 28 अप्रैल 2026

• Target Sector — Urban Co-operative Banks (UCBs)

• लक्ष्य क्षेत्र — शहरी सहकारी बैंक (UCBs)

• Total Participants — 1.40 lakh

• कुल प्रतिभागी — 1.40 लाख

• Training Mode — In-person + E-learning

• प्रशिक्षण मोड — प्रत्यक्ष + ई-लर्निंग

• Total UCBs — 1,400+

• कुल UCBs — 1,400+

Ques: Flipkart, Axis Bank, and PayU have introduced biometric authentication for card payments, replacing which traditional system?

प्रश्न: Flipkart, Axis Bank और PayU ने कार्ड पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, जो किस पारंपरिक प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है?

A) PIN / पिन

B) OTP (One-Time Password) / ओटीपी

C) CVV / सीवीवी

D) Net Banking Password / नेट बैंकिंग पासवर्ड

E) UPI PIN / यूपीआई पिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Flipkart, Axis Bank, and PayU have jointly introduced biometric authentication for card payments.

• Flipkart, Axis Bank और PayU ने मिलकर कार्ड पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया है।

• Axis Bank cardholders can now approve payments using fingerprint or Face ID.

• Axis Bank के कार्डधारक अब फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के माध्यम से भुगतान को स्वीकृत कर सकते हैं।

• This system replaces the traditional OTP (One-Time Password) method.

• यह प्रणाली पारंपरिक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) विधि को प्रतिस्थापित करती है।

• PayU manages the payment infrastructure for this system.

• इस प्रणाली के लिए PayU पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन करता है।

• Wibmo, a subsidiary of PayU, handles the authentication process.

• PayU की सहायक कंपनी Wibmo ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को संभालती है।

• This move enhances security and improves user convenience in digital payments.

• यह कदम डिजिटल भुगतान में सुरक्षा और उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ाता है।

Ques: RBI has set what time limit to classify a borrower as a wilful defaulter after NPA tagging?

प्रश्न: RBI ने NPA घोषित होने के बाद किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए कितनी समय सीमा तय की है?

A) 3 months / 3 महीने

B) 6 months / 6 महीने

C) 9 months / 9 महीने

D) 12 months / 12 महीने

E) 18 months / 18 महीने

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India (RBI) has introduced a timeline for classifying wilful defaulters.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए समयसीमा निर्धारित की है।

• Banks must complete the process within 6 months of an account being classified as NPA.

• बैंकों को खाते के NPA घोषित होने के 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

• The process begins if a wilful default is observed during internal preliminary screening.

• यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आंतरिक प्रारंभिक जांच में विलफुल डिफॉल्ट पाया जाता है।

• The rule ensures timely identification and action against wilful defaulters.

• यह नियम विलफुल डिफॉल्टर की समय पर पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

• The new guideline will come into effect from April 1, 2027.

• यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।

• It aims to strengthen credit discipline and banking transparency.

• इसका उद्देश्य क्रेडिट अनुशासन और बैंकिंग पारदर्शिता को मजबूत करना है।

Ques: India's factory output is measured by which index?
प्रश्न: भारत में फैक्ट्री उत्पादन किस सूचकांक द्वारा मापा जाता है?

A) Consumer Price Index (CPI) / उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
B) Wholesale Price Index (WPI) / थोक मूल्य सूचकांक
C) Purchasing Managers' Index (PMI) / परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
D) GDP Deflator / जीडीपी डिफ्लेटर
E) Index of Industrial Production (IIP) / औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• India's industrial output growth slowed to a five-month low of 4.1% in March 2026.
• मार्च 2026 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि घटकर 4.1% रह गई, जो पांच महीने का न्यूनतम स्तर है।
• Factory output in India is measured by the Index of Industrial Production (IIP).
• भारत में फैक्ट्री उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) द्वारा मापा जाता है।
• The growth for February 2026 was revised to 5.1% from the earlier estimate of 5.2%.
• फरवरी 2026 की वृद्धि दर को 5.2% से संशोधित कर 5.1% किया गया।
• The data is released by the National Statistics Office (NSO).
• यह आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए जाते हैं।

Ques: Which organization has been recognised as the PaRRVA agency by SEBI?
प्रश्न: SEBI द्वारा PaRRVA एजेंसी के रूप में किस संगठन को मान्यता दी गई है?

A) National Stock Exchange of India (NSE) / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया

B) Bombay Stock Exchange (BSE) / बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

C) CARE Ratings Limited / केयर रेटिंग्स लिमिटेड

D) CRISIL Limited / क्रिसिल लिमिटेड

E) ICRA Limited / आईसीआरए लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has operationalised PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency).

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency) को संचालन में ला दिया है।

• CARE Ratings Limited has been recognised as the PaRRVA agency.

• CARE Ratings Limited को PaRRVA एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है।

• National Stock Exchange of India (NSE) will function as the PaRRVA Data Centre (PDC).

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) PaRRVA डेटा सेंटर (PDC) के रूप में कार्य करेगा।

• The initiative aims to improve transparency, credibility, and investor protection in financial markets.

• इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निवेशक सुरक्षा बढ़ाना है।

• The pilot phase began in December 2025, and full operations start from 4 May 2026.

• इसका पायलट चरण दिसंबर 2025 में शुरू हुआ और नियमित संचालन 4 मई 2026 से शुरू होगा।

• It enables investment advisors, research analysts, and algo trading firms to display verified performance records.

• यह निवेश सलाहकारों, रिसर्च एनालिस्ट्स और एल्गो ट्रेडिंग सेवा प्रदाताओं को सत्यापित प्रदर्शन रिकॉर्ड दिखाने में मदद करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) – Regulator of securities market
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) – प्रतिभूति बाजार का नियामक
• Established – 1988
• स्थापना – 1988
• Statutory Status – 1992
• वैधानिक दर्जा – 1992
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• National Stock Exchange of India (NSE) – Established 1992
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) – स्थापना 1992

Ques: NITI Aayog's "Digital Public Infrastructure (DPI) @2047" roadmap primarily focuses on which immediate phase of India's digital transformation?

प्रश्न: नीति आयोग का "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047" रोडमैप भारत के डिजिटल परिवर्तन के किस तात्कालिक चरण पर मुख्य रूप से केंद्रित है?

A) DPI 1.0 (2015–2025)
B) DPI 2.0 (2025–2035)
C) DPI 3.0 (2035–2047)
D) AI 1.0 Phase
E) BharatNet Phase III

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• NITI Aayog launched the "Digital Public Infrastructure (DPI) @2047" roadmap to achieve the vision of Viksit Bharat 2047.
• नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047" रोडमैप लॉन्च किया।

• The roadmap was unveiled by Suman Bery and Ajay Kumar Sood.
• इस रोडमैप का अनावरण सुमन बेरी और अजय कुमार सूद द्वारा किया गया।
• India aims to become a $30 trillion economy with a per capita income of $18,000 by 2047 under the Viksit Bharat vision.
• विकसित भारत के तहत भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और $18,000 प्रति व्यक्ति आय हासिल करना है।
• DPI initiatives are already contributing nearly 1% to GDP and may reach 4% by 2030.
• DPI पहलें वर्तमान में GDP में लगभग 1% योगदान दे रही हैं और 2030 तक 4% तक पहुंच सकती हैं।
• The roadmap has been developed by NITI Frontier Tech Hub in partnership with EkStep Foundation and Deloitte.
• यह रोडमैप नीति फ्रंटियर टेक हब द्वारा एकस्टेप फाउंडेशन और डेलॉइट के सहयोग से विकसित किया गया है।

• **It outlines two phases:**

DPI 2.0 (2025–2035): Focused on livelihood-led growth at scale
DPI 3.0 (2035–2047): Focused on broad-based prosperity
• इसमें दो चरण शामिल हैं:
DPI 2.0 (2025–2035): बड़े पैमाने पर आजीविका-आधारित विकास
DPI 3.0 (2035–2047): व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना

• The immediate focus is on DPI 2.0, which includes eight sectoral transformations.
• वर्तमान में ध्यान DPI 2.0 पर है, जिसमें आठ क्षेत्रीय परिवर्तन शामिल हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• NITI Aayog Established – 2015
• नीति आयोग की स्थापना – 2015
• Chairperson – Prime Minister of India
• अध्यक्ष – भारत के प्रधानमंत्री
• Headquarters – New Delhi
• मुख्यालय – नई दिल्ली

• DPI Full Form – Digital Public Infrastructure
• DPI का पूर्ण रूप – डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

Ques: Under RBI's revised calamity loan framework, banks must invoke resolution plans within how many days of disaster declaration?
प्रश्न: RBI के संशोधित आपदा ऋण ढांचे के तहत बैंक को आपदा घोषणा के कितने दिनों के भीतर समाधान योजना शुरू करनी होगी?

A) 30 Days / 30 दिन
B) 45 Days / 45 दिन
C) 60 Days / 60 दिन
D) 90 Days / 90 दिन
E) 135 Days / 135 दिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has revised its loan restructuring framework for borrowers affected by natural disasters.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन ढांचे में संशोधन किया है।
• Under the new rules, banks must invoke the resolution plan within 45 days of disaster declaration.
• नए नियमों के अनुसार बैंकों को आपदा घोषणा के 45 दिनों के भीतर समाधान योजना शुरू करनी होगी।
• The implementation of the restructuring plan must be completed within 135 days.
• पुनर्गठन योजना को 135 दिनों के भीतर लागू करना आवश्यक है।
• Banks can now proactively initiate restructuring without waiting for borrower requests.

• अब बैंक उधारकर्ताओं के आवेदन का इंतजार किए बिना स्वतः पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

• Eligible borrowers must have standard accounts with no default exceeding 30 days at the time of disaster.

• पात्र उधारकर्ताओं के खाते स्टैंडर्ड होने चाहिए और आपदा के समय 30 दिन से अधिक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।

• Accounts turning NPA during the process can be upgraded back to standard after successful restructuring.

• इस अवधि में NPA बने खातों को सफल पुनर्गठन के बाद फिर से स्टैंडर्ड श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

• Banks may also waive fees and charges for up to one year in eligible cases.

• पात्र मामलों में बैंक एक वर्ष तक शुल्क और चार्ज माफ कर सकते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India (RBI) – Central Bank of India

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) – भारत का केंद्रीय बैंक

• Established – 1935

• स्थापना – 1935

• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• Governor – Sanjay Malhotra

• गवर्नर – संजय मल्होत्रा

• NPA Full Form – Non-Performing Asset

• NPA का पूरा नाम – नॉन-परफॉर्मिंग एसेट

Ques: EPFO's newly launched E-PRAAPTI portal is mainly designed for what purpose?

प्रश्न: EPFO द्वारा लॉन्च किया गया E-PRAAPTI पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है?

A) To open new PF accounts / नए PF खाते खोलने के लिए

B) To track and activate inoperative EPF accounts / निष्क्रिय EPF खातों को ट्रैक और सक्रिय करने के लिए

C) To issue pension cards / पेंशन कार्ड जारी करने के लिए

D) To provide loans / ऋण प्रदान करने के लिए

E) To issue debit cards / डेबिट कार्ड जारी करने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) is launching the E-PRAAPTI portal for members with old or inactive EPF accounts.

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पुराने या निष्क्रिय EPF खातों वाले सदस्यों के लिए E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च कर रहा है।

• The portal helps users identify, track, link UAN, and activate inoperative EPF accounts.

• यह पोर्टल पुराने EPF खातों की पहचान, ट्रैकिंग, UAN लिंकिंग और सक्रियण में मदद करता है।

• Members can access accounts through Aadhaar-based authentication, even without a UAN.

• सदस्य आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से बिना UAN के भी खातों तक पहुंच सकते हैं।

• An EPF account becomes inoperative if no contribution is made for 36 months (3 years).

• यदि 36 महीने (3 वर्ष) तक कोई योगदान नहीं होता है, तो EPF खाता निष्क्रिय हो जाता है।

• For members above 55 years, accounts become inoperative 3 years after retirement or age 55, whichever is later.

• 55 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों के लिए खाता सेवानिवृत्ति या 55 वर्ष की आयु (जो बाद में हो) के 3 वर्ष बाद निष्क्रिय हो जाता है।

• If a member is below 55 years, the account continues earning interest till 58 years even without contributions.

• यदि सदस्य 55 वर्ष से कम है, तो बिना योगदान के भी खाता 58 वर्ष की आयु तक ब्याज अर्जित करता रहता है।

• After 7 years, unclaimed balances are transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF).

• 7 वर्ष बाद दावा न की गई राशि Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) में ट्रांसफर कर दी जाती है।

• EPFO settled a record 8.31 crore claims in FY 2025–26.

• EPFO ने वित्त वर्ष 2025–26 में रिकॉर्ड 8.31 करोड़ दावों का निपटान किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) – Social security organisation

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) – सामाजिक सुरक्षा संगठन

• Established – 1952

• स्थापना – 1952

• Headquarters – New Delhi

• मुख्यालय – नई दिल्ली

• Parent Ministry – Ministry of Labour and Employment

• संबंधित मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

• UAN Full Form – Universal Account Number

• UAN का पूरा नाम – यूनिवर्सल अकाउंट नंबर

• Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) – Established 2016

• वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF) – स्थापना 2016

Ques: Under RBI's new Type-I NBFC framework, what is the maximum asset limit for exemption?

प्रश्न: RBI के नए Type-I NBFC फ्रेमवर्क के तहत छूट के लिए अधिकतम एसेट सीमा कितनी है?

A) ₹500 Crore / ₹500 करोड़

B) ₹750 Crore / ₹750 करोड़

C) ₹1,000 Crore / ₹1,000 करोड़

D) ₹1,500 Crore / ₹1,500 करोड़

E) ₹2,000 Crore / ₹2,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has introduced a new Type-I NBFC framework for small NBFCs.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छोटे NBFCs के लिए नया Type-I फ्रेमवर्क पेश किया है।

• Under this framework, NBFCs with total assets below ₹1,000 crore are eligible for exemption.

• इस फ्रेमवर्क के तहत ₹1,000 करोड़ से कम एसेट वाले NBFCs छूट के पात्र होंगे।

• Eligible NBFCs must not accept public funds and should have no direct customer interface.

• पात्र NBFCs पब्लिक फंड स्वीकार नहीं करेंगे और उनका ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए।

• Such entities will be exempted from registration and reserve fund requirements under the RBI Act, 1934.

• ऐसे संस्थानों को RBI अधिनियम, 1934 के तहत रजिस्ट्रेशन और रिजर्व फंड नियमों से छूट मिलेगी।

• Existing NBFCs can apply for deregistration through the PRAVAAH portal by 31 December 2026.

• पात्र NBFCs 31 दिसंबर 2026 तक PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से डी-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• The board must pass an annual resolution confirming compliance with the framework.

• प्रत्येक वर्ष बोर्ड को नियमों के पालन की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव पारित करना होगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India (RBI) – Central Bank of India

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) – भारत का केंद्रीय बैंक

• Established – 1935

• स्थापना – 1935
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• NBFC Full Form – Non-Banking Financial Company
• NBFC का पूरा नाम – नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
• RBI Act – 1934
• RBI अधिनियम – 1934

Ques: What is the new FDI limit notified by the Government of India in the insurance sector under the automatic route, and what is the FDI cap for LIC?
प्रश्न: भारत सरकार द्वारा स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र में अधिसूचित नई FDI सीमा क्या है और LIC के लिए FDI सीमा क्या है?

A. 74% insurance; 20% LIC (74% बीमा; 20% LIC)
B. 100% insurance; 49% LIC (100% बीमा; 49% LIC)
C. 100% insurance; 20% LIC (100% बीमा; 20% LIC)
D. 49% insurance; 20% LIC (49% बीमा; 20% LIC)
E. 100% insurance; 26% LIC (100% बीमा; 26% LIC)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has notified 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the insurance sector under the automatic route under Foreign Exchange Management Act (FEMA).
• भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र में 100% FDI अधिसूचित किया है।
• This eliminates the need for an Indian joint venture partner for foreign insurers operating in India.

• इससे भारत में काम करने वाले विदेशी बीमाकर्ताओं के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदार की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

• The 100% FDI limit also applies to insurance intermediaries such as brokers, reinsurance brokers, corporate agents, TPAs, surveyors, loss assessors, MGAs, and insurance repositories — subject to Insurance Regulatory and Development Authority of India norms.

• 100% FDI सीमा बीमा मध्यस्थों पर भी लागू होगी — भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों के अधीन।

• Foreign investment in Life Insurance Corporation of India will remain capped at 20% under a separate framework governed by the LIC Act, 1956 and Insurance Act, 1938.

• भारतीय जीवन बीमा निगम में विदेशी निवेश 20% तक सीमित रहेगा।

• Insurance companies with foreign investment must appoint at least one resident Indian citizen as Chairperson, MD or CEO, and comply with RBI pricing guidelines under FEMA.

• विदेशी निवेश वाली बीमा कंपनियों को कम से कम एक भारतीय निवासी को चेयरपर्सन/MD/CEO नियुक्त करना होगा और RBI के मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

• The policy aligns with the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, which increased the FDI limit from 74% to 100%.

• यह नीति सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुरूप है, जिसने FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Sector — Insurance / क्षेत्र — बीमा
• FDI Limit (New) — 100% (Automatic Route)
• नई FDI सीमा — 100% (स्वचालित मार्ग)
• Previous FDI Limit — 74%
• पिछली FDI सीमा — 74%
• Route — Automatic Route under FEMA
• मार्ग — FEMA के तहत स्वचालित मार्ग
• Regulatory Body — Insurance Regulatory and Development Authority of India
• नियामक संस्था — IRDAI

• LIC FDI Cap — 20% (separate framework)
• LIC FDI सीमा — 20%
• Amendment Act — Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025
• संशोधन अधिनियम — सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025

Ques: Who has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI)?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. Swaminathan Janakiraman / स्वामीनाथन जानकीरमण
B. Rohit Jain / रोहित जैन
C. Poonam Gupta / पूनम गुप्ता
D. Shirish Chandra Murmu / शिरीष चंद्र मुर्मू
E. T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India appointed Rohit Jain as Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of 3 years.
• भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिज़र्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया।
• His appointment is effective from May 3.
• उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी है।
• He was previously serving as an Executive Director at RBI.
• वे पहले RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे।
• He succeeds T. Rabi Sankar, who recently retired after completing his tenure.
• उन्होंने टी. रबी शंकर का स्थान लिया।
• After this appointment, RBI now has four Deputy Governors.

• इस नियुक्ति के बाद RBI में चार डिप्टी गवर्नर हैं।
• The four Deputy Governors are: Rohit Jain, Swaminathan Janakiraman, Poonam Gupta, Shirish Chandra Murmu.
• वर्तमान चार डिप्टी गवर्नर हैं: रोहित जैन, स्वामीनाथन जानकीरमण, डॉ. पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू।

Ques: Which UPI app became the first to cross 10 billion monthly transactions in March 2026?
प्रश्न: मार्च 2026 में कौन-सा UPI ऐप 10 बिलियन मासिक लेनदेन पार करने वाला पहला ऐप बना?

A) PhonePe / फोनपे
B) Paytm / पेटीएम
C) Google Pay / गूगल पे
D) Amazon Pay / अमेज़न पे
E) BHIM / भीम

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• PhonePe became the first UPI app to cross 10 billion monthly transactions, recording 10.50 billion transactions in March 2026.
• फोनपे मार्च 2026 में 10.50 बिलियन लेनदेन के साथ 10 बिलियन मासिक ट्रांजैक्शन पार करने वाला पहला UPI ऐप बना।
• This marks a major milestone in India's digital payments ecosystem.
• यह भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
• As per data from National Payments Corporation of India, PhonePe held a 46.4% share by volume and 49.1% share by value.
• NPCI के अनुसार, फोनपे का वॉल्यूम में 46.4% और वैल्यू में 49.1% हिस्सा रहा।
• It processed transactions worth ₹14.48 lakh crore during the period.

• इस अवधि में ₹14.48 लाख करोड़ के लेनदेन प्रोसेस किए गए।
• The platform showed consistent growth, processing 8 billion transactions in December and 9.9 billion in January.
• प्लेटफॉर्म ने लगातार वृद्धि दिखाई, दिसंबर में 8 बिलियन और जनवरी में 9.9 बिलियन लेनदेन प्रोसेस किए।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• PhonePe Founded – 2015
• फोनपे की स्थापना – 2015
• Headquarters – Bengaluru
• मुख्यालय – बेंगलुरु
• UPI Regulator – National Payments Corporation of India (NPCI)
• UPI नियामक – नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
• Milestone – First app to cross 10 billion monthly transactions
• उपलब्धि – 10 बिलियन मासिक ट्रांजैक्शन पार करने वाला पहला ऐप

Ques: MuleHunter.AI tool, recently in news, has been developed by which institution?

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा MuleHunter.AI टूल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है?

A) SEBI / सेबी
B) NABARD / नाबार्ड
C) Reserve Bank of India / आरबीआई
D) SIDBI / सिडबी
E) NPCI / एनपीसीआई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Ministry of Finance has instructed banks to adopt MuleHunter.AI, an AI-based tool developed by Reserve Bank of India.

• वित्त मंत्रालय ने बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित MuleHunter.AI टूल अपनाने का निर्देश दिया है।

• The tool is designed to identify and prevent mule accounts used in cyber-enabled financial frauds.

• यह टूल साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में उपयोग होने वाले म्यूल अकाउंट्स की पहचान और रोकथाम के लिए बनाया गया है।

• Financial Services Secretary M. Nagaraju advised banks to implement the tool at the earliest.

• वित्तीय सेवा सचिव M. Nagaraju ने बैंकों को इस टूल को जल्द से जल्द लागू करने की सलाह दी।

• State Level Bankers' Committees (SLBCs) have also been asked to coordinate with state police authorities for cyber fraud prevention.

• State Level Bankers' Committees (SLBCs) को साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करने को भी कहा गया है।

• The initiative aims to strengthen digital banking security and fraud detection systems.

• इस पहल का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India Established – 1935

• RBI की स्थापना – 1935

• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• Ministry of Finance Headquarters – New Delhi

• वित्त मंत्रालय का मुख्यालय – नई दिल्ली

• Mule Account – A bank account used to transfer illegally obtained money

• म्यूल अकाउंट – ऐसा बैंक खाता जिसका उपयोग अवैध धन ट्रांसफर के लिए किया जाता है

Ques: Which bank has launched a Self Help Group (SHG) Savings Account to promote financial inclusion among women-led SHGs?

प्रश्न: महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु किस बैंक ने SHG सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

C) India Post Payments Bank / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India Post Payments Bank has launched a Self Help Group (SHG) Savings Account.

• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने स्वयं सहायता समूह (SHG) सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है।

• The initiative aims to promote financial inclusion and empower women-led SHGs in rural areas.

• इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के SHGs को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

• **Key features of the account include:**

Zero balance account
No minimum balance requirement
Maximum balance limit of ₹2 lakh
No charges on deposits and withdrawals
Quarterly interest payments
One free account statement per month
No account closure charges

• **इस खाते की मुख्य विशेषताएं:**

जीरो बैलेंस खाता

न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं

अधिकतम बैलेंस ₹2 लाख

जमा और निकासी पर कोई शुल्क नहीं

तिमाही ब्याज भुगतान

प्रति माह एक मुफ्त स्टेटमेंट

खाता बंद करने पर कोई शुल्क नहीं

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• IPPB Launched – 1 September 2018
• IPPB लॉन्च – 1 सितंबर 2018
• Ownership – 100% Government of India
• स्वामित्व – 100% भारत सरकार
• Parent Department – Department of Posts, Ministry of Communications
• संबंधित विभाग – डाक विभाग, संचार मंत्रालय
• Headquarters – New Delhi
• मुख्यालय – नई दिल्ली

Ques: Who among the following were recently appointed as full-time members of NITI Aayog?

प्रश्न: निम्नलिखित में से हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Joram Aniya and R. Balasubramaniam / जोराम अनिया और आर. बालसुब्रमण्यम

B) Sanjiv Khanna and Rajiv Gauba / संजीव खन्ना और राजीव गौबा

C) Ashok Lahiri and Amit Shah / अशोक लाहिड़ी और अमित शाह

D) M. Srinivas and Abhay Karandikar / एम. श्रीनिवास और अभय करंदीकर

E) Suman Bery and K.V. Raju / सुमन बेरी और के.वी. राजू

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has appointed Dr. Joram Aniya and Dr. R. Balasubramaniam as full-time members of NITI Aayog.

• भारत सरकार ने डॉ. जोराम अनिया और डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।

• The appointments were approved by Prime Minister Narendra Modi.

• इन नियुक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूरी दी गई।

• With these appointments, the total number of full-time members in NITI Aayog has increased to seven, along with one Vice-Chairperson.

• इन नियुक्तियों के बाद नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या सात हो गई है, साथ में एक उपाध्यक्ष भी हैं।

• Dr. R. Balasubramaniam has earlier served in the Capacity Building Commission and is known as a scholar, author, and public policy expert.

• डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम पहले कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में कार्य कर चुके हैं।

• Dr. Joram Aniya is an academician from Arunachal Pradesh with over 18 years of experience in teaching, research, and public policy.

• डॉ. जोराम अनिया अरुणाचल प्रदेश की शिक्षाविद हैं।

• She is regarded as the first woman from the Nyishi community to earn a PhD and the first doctorate holder in Hindi from Arunachal Pradesh.

• उन्हें न्यीशी समुदाय की पहली महिला पीएचडी धारक और अरुणाचल प्रदेश से हिंदी में पहली डॉक्टरेट धारक माना जाता है।

• This is part of the major revamp of NITI Aayog announced in April 2026.

• यह अप्रैल 2026 में घोषित नीति आयोग के बड़े पुनर्गठन का हिस्सा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• NITI Aayog Established – 1 January 2015

• नीति आयोग की स्थापना – 1 जनवरी 2015

• Headquarters – New Delhi

• मुख्यालय – नई दिल्ली

• Chairperson – Narendra Modi

• अध्यक्ष – नरेंद्र मोदी
• Vice-Chairperson – Ashok Lahiri
• उपाध्यक्ष – अशोक लाहिड़ी
• Replaced – Planning Commission
• किसका स्थान लिया – योजना आयोग

Ques: Federal Bank is acquiring a credit card portfolio of around 4.5 lakh cards from which bank?

प्रश्न: Federal Bank लगभग 4.5 लाख कार्ड का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो किस बैंक से अधिग्रहित कर रहा है?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
E) Citibank / सिटीबैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Federal Bank will acquire a selected India credit card portfolio from Standard Chartered Bank.
• Federal Bank भारत में Standard Chartered Bank के चयनित क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करेगा।
• The portfolio includes around 4.5 lakh (450,000) credit cards.
• इस पोर्टफोलियो में लगभग 4.5 लाख (450,000) क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
• The acquisition will help Federal Bank expand its customer base in major cities.
• यह अधिग्रहण फेडरल बैंक को बड़े शहरों में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में मदद करेगा।

• Federal Bank currently has around 8 lakh non co-branded cards and 13 lakh co-branded cards.

• फेडरल बैंक के पास वर्तमान में लगभग 8 लाख नॉन-को-ब्रांडेड कार्ड और 13 लाख को-ब्रांडेड कार्ड हैं।

• After this deal, Federal Bank's non co-branded credit card receivables are expected to increase by around 90%.

• इस डील के बाद फेडरल बैंक के नॉन-को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में लगभग 90% वृद्धि होने की उम्मीद है।

• The deal is expected to be completed within calendar year 2026.

• यह डील कैलेंडर वर्ष 2026 के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Federal Bank Established – 1931

• फेडरल बैंक की स्थापना – 1931

• Headquarters – Kochi, Kerala

• मुख्यालय – कोच्चि, केरल

• Standard Chartered Established – 1969

• स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्थापना – 1969

• Headquarters – London, United Kingdom

• मुख्यालय – लंदन, यूनाइटेड किंगडम

Ques: What is the key change in FDI norms announced by the Government of India in May 2026?

प्रश्न: मई 2026 में भारत सरकार द्वारा FDI नियमों में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है?

A) Ban on Chinese investments / चीनी निवेश पर प्रतिबंध

B) Allowing 10% Chinese stake firms via automatic route / 10% चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति

C) Increase in FDI limit to 100% / FDI सीमा को 100% करना

D) Removal of FEMA regulations / FEMA नियमों को हटाना

E) Mandatory approval for all foreign investments / सभी विदेशी निवेश के लिए अनिवार्य मंजूरी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has eased FDI norms under Foreign Exchange Management Act for companies with up to 10% Chinese shareholding.

• भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी है।

• Such companies can now invest in India through the automatic route, subject to sectoral conditions.

• ऐसी कंपनियां अब क्षेत्रीय शर्तों के तहत ऑटोमैटिक रूट से निवेश कर सकती हैं।

• The decision came into effect from May 1, 2026, as notified by the Ministry of Finance.

• यह निर्णय 1 मई 2026 से वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होकर लागू हुआ।

• The relaxation is based on amendments to Press Note 3 of 2020 approved by the Union Cabinet of India.

• यह ढील 2020 के प्रेस नोट 3 में संशोधन पर आधारित है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

• It aims to boost foreign investment in sectors like electronics and manufacturing.

• इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाना है।

• However, the relaxation does not apply to entities registered in China, Hong Kong, or countries sharing land borders with India.

• हालांकि यह ढील चीन, हांगकांग या भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।

• Higher or controlling Chinese stakes will still require government approval.

• अधिक या नियंत्रित हिस्सेदारी के लिए अभी भी सरकारी मंजूरी आवश्यक होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- FEMA Full Form – Foreign Exchange Management Act
- FEMA का पूर्ण रूप – विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
- Introduced – 1999
- लागू – 1999
- Nodal Ministry – Ministry of Finance
- संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
- DPIIT Full Form – Department for Promotion of Industry and Internal Trade
- DPIIT का पूर्ण रूप – उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
- Press Note 3 Year – 2020
- प्रेस नोट 3 वर्ष – 2020

Ques: Under RBI's revised loan restructuring guidelines for disaster-hit areas, what is the mandatory provisioning requirement for banks and NBFCs?
प्रश्न: आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए RBI के संशोधित लोन पुनर्गठन दिशानिर्देशों के तहत बैंकों और NBFCs के लिए अनिवार्य प्रावधान (Provisioning) कितना है?

A) 2%
B) 3%
C) 5%
D) 7%
E) 10%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India has introduced revised guidelines for loan restructuring in disaster-hit areas, providing greater flexibility to banks and NBFCs.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन पुनर्गठन के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे बैंकों और NBFCs को अधिक लचीलापन मिलेगा।
- The new framework will come into effect from 1 July 2026.

• यह नया ढांचा 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
• It allows lenders to proactively restructure loans without waiting for borrower requests.
• इसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही ऋण पुनर्गठन कर सकते हैं।
• A key feature is the mandatory 5% provisioning requirement, where lenders must set aside 5% of the outstanding loan value.
• इसका प्रमुख प्रावधान 5% अनिवार्य प्रावधान है, जिसमें ऋणदाताओं को बकाया ऋण का 5% अलग रखना होगा।
• Borrowers have a 135-day opt-out window from the date of disaster declaration.
• उधारकर्ताओं को आपदा घोषणा की तिथि से 135 दिनों का ऑप्ट-आउट विकल्प मिलेगा।
• RBI rejected requests to reduce provisioning to 2%, citing the need for better risk coverage in uncertain recovery scenarios.
• RBI ने प्रावधान को 2% करने के अनुरोध को अस्वीकार किया, यह कहते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में जोखिम कवर जरूरी है।

Eligibility conditions include:

- Only standard accounts are eligible
- Loans should not be overdue by more than 30 days at the time of disaster
- Also the requests to extend eligibility up to 89 days overdue were rejected to ensure that the relief targets genuine disaster-affected borrowers.

पात्रता शर्तें:

- केवल स्टैंडर्ड खाते पात्र होंगे
- आपदा के समय ऋण 30 दिनों से अधिक ओवरड्यू नहीं होना चाहिए
- साथ ही, बकाया ऋण के लिए पात्रता को 89 दिनों तक बढ़ाने के अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राहत का लाभ आपदा से वास्तविक रूप से प्रभावित उधारकर्ताओं को ही मिले।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Effective Date – 1 July 2026
- प्रभावी तिथि – 1 जुलाई 2026
- Provisioning Requirement – 5%
- प्रावधान आवश्यकता – 5%
- Opt-out Window – 135 days
- ऑप्ट-आउट अवधि – 135 दिन
- Eligibility – Standard Accounts (≤30 days overdue)
- पात्रता – स्टैंडर्ड खाते (30 दिन से कम ओवरड्यू)

Ques: The Asian Development Bank (ADB) announced a $70 billion plan for which sectors in the Asia-Pacific region?

प्रश्न: एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर की योजना किन क्षेत्रों के लिए घोषित की?

A) Agriculture & Health / कृषि एवं स्वास्थ्य

B) Education & Tourism / शिक्षा एवं पर्यटन

C) Energy & Digital Infrastructure / ऊर्जा एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

D) Defence & Space / रक्षा एवं अंतरिक्ष

E) Banking & Finance / बैंकिंग एवं वित्त

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank announced a $70 billion programme for energy and digital infrastructure.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70 बिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की।
- The announcement was made during the 59th Annual Meeting held in Samarkand, Uzbekistan.

• यह घोषणा समरकंद, उज़्बेकिस्तान में की गई।
• The plan aims to expand energy connectivity and digital networks across the Asia-Pacific region by 2035.
• इस योजना का उद्देश्य 2035 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार करना है।
• It includes $50 billion for Pan-Asia Power Grid Initiative and $20 billion for digital connectivity.
• इसमें 50 बिलियन डॉलर पावर ग्रिड और 20 बिलियन डॉलर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हैं।
• It will strengthen cross-border electricity trade and broadband access.
• यह सीमा-पार बिजली व्यापार और ब्रॉडबैंड पहुंच को मजबूत करेगा।
• ADB President Masato Kanda emphasized long-term economic growth.
• एडीबी अध्यक्ष Masato Kanda ने दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Asian Development Bank Established – 1966
• एडीबी की स्थापना – 1966
• Headquarters – Manila, Philippines
• मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस
• President – Masato Kanda (2026)
• अध्यक्ष – Masato Kanda (2026)
• Members – 69 Countries
• सदस्य – 69 देश
• Objective – Promote economic development and regional cooperation
• उद्देश्य – आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

Ques: National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), often referred to as India's "Bad Bank", was established in which year?
प्रश्न: नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), जिसे भारत का "बैड बैंक" कहा जाता है, किस वर्ष स्थापित की गई थी?

A) 2018
B) 2019
C) 2020
D) 2021
E) 2022

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) is known as India's "Bad Bank".

• नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को भारत का "बैड बैंक" कहा जाता है।

• It was established in the year 2021.

• इसकी स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी।

• A bad bank is a special institution created to deal with bad loans (NPAs) of banks.

• बैड बैंक एक विशेष संस्था होती है जो बैंकों के खराब ऋण (NPA) से निपटने के लिए बनाई जाती है।

• NARCL has accelerated its recovery efforts in FY 2025–26, recovering Rs. 4,364 crore during the year.

• NARCL ने वित्त वर्ष 2025–26 में अपनी रिकवरी प्रक्रिया तेज करते हुए 4,364 करोड़ रुपये की वसूली की।

• This accounts for nearly 70% of its total recoveries to date.

• यह अब तक की कुल वसूली का लगभग 70% है।

• Total cumulative recoveries by NARCL have reached Rs. 6,345 crore.

• NARCL द्वारा कुल संचयी वसूली 6,345 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

• The government-backed institution has acquired 33 borrower entities.

• सरकार समर्थित इस संस्था ने अब तक 33 उधारकर्ता संस्थाओं का अधिग्रहण किया है।

• These accounts have a total debt exposure of Rs. 1.65 lakh crore.

• इन खातों का कुल ऋण जोखिम 1.65 लाख करोड़ रुपये है।

Ques: Viability Plan 2.0 for RRBs focuses on how many key pillars?
प्रश्न: RRBs के लिए Viability Plan 2.0 कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित है?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Financial Services (DFS) has approved Viability Plan 2.0 for Regional Rural Banks (RRBs) for FY 2025–26 to 2027–28.
• वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने FY 2025–26 से 2027–28 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए Viability Plan 2.0 को मंजूरी दी है।
• The plan includes 30 performance parameters structured across four key pillars — operational excellence, asset quality, profitability, and growth.
• इस योजना में 30 प्रदर्शन मानक शामिल हैं, जो चार मुख्य स्तंभों—ऑपरेशनल उत्कृष्टता, एसेट क्वालिटी, लाभप्रदता और वृद्धि—पर आधारित हैं।
• It aims to improve financial sustainability, strengthen recovery mechanisms, and enhance digital adoption in RRBs.
• इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बढ़ाना, रिकवरी प्रणाली को मजबूत करना और RRBs में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देना है।
• The plan replaces the earlier Viability Plan (FY22–FY25) and targets better governance and efficiency across all 28 RRBs.
• यह योजना पूर्व Viability Plan (FY22–FY25) का स्थान लेती है और सभी 28 RRBs में बेहतर गवर्नेंस और दक्षता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
• This initiative supports financial inclusion and strengthens rural banking infrastructure in India.
• यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और भारत में ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मजबूत करती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RRBs Established – 1975
- RRBs की स्थापना – 1975
- Regulated By – Reserve Bank of India (RBI) & NABARD
- विनियामक – RBI एवं NABARD
- Objective – Financial Inclusion in Rural Areas
- उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन
- Total RRBs – 28
- कुल RRBs – 28

Ques: What was the total UPI transaction value in April after a slight dip from March highs?

प्रश्न: मार्च के उच्च स्तर से गिरावट के बाद अप्रैल में UPI लेनदेन का कुल मूल्य कितना रहा?

A) ₹28.50 trillion / ₹28.50 ट्रिलियन

B) ₹29.03 trillion / ₹29.03 ट्रिलियन

C) ₹29.53 trillion / ₹29.53 ट्रिलियन

D) ₹30.10 trillion / ₹30.10 ट्रिलियन

E) ₹27.90 trillion / ₹27.90 ट्रिलियन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- UPI transaction value dipped by 1.7% in April to ₹29.03 trillion.
- अप्रैल में UPI लेनदेन का मूल्य 1.7% घटकर ₹29.03 ट्रिलियन हो गया।
- In March, the transaction value was ₹29.53 trillion.
- मार्च में लेनदेन का मूल्य ₹29.53 ट्रिलियन था।
- UPI transaction volume declined by 1.3% to 22.35 billion in April.

• अप्रैल में UPI लेनदेन की मात्रा 1.3% घटकर 22.35 बिलियन हो गई।
• In March, the volume was 22.64 billion transactions.
• मार्च में लेनदेन की मात्रा 22.64 बिलियन थी।
• Year-on-year, April recorded a 25% rise in volume and a 21% increase in value.
• वर्ष-दर-वर्ष, अप्रैल में मात्रा में 25% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई।
• Despite the monthly dip, daily transaction volumes increased from 730 million in March to 745 million in April.
• मासिक गिरावट के बावजूद, दैनिक लेनदेन मात्रा मार्च के 730 मिलियन से बढ़कर अप्रैल में 745 मिलियन हो गई।
• The data is released by the National Payments Corporation of India (NPCI), which operates UPI.
• यह डेटा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किया जाता है, जो UPI का संचालन करता है।

Ques: What was India's net direct tax collection in the financial year 2025–26, as per CBDT data?

प्रश्न: CBDT के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Net Direct Tax) संग्रह कितना रहा?

A) Rs. 21,40,406 crore / 21,40,406 करोड़ रुपये
B) Rs. 22,50,000 crore / 22,50,000 करोड़ रुपये
C) Rs. 23,40,406 crore / 23,40,406 करोड़ रुपये
D) Rs. 24,10,000 crore / 24,10,000 करोड़ रुपये
E) Rs. 25,00,000 crore / 25,00,000 करोड़ रुपये

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's net direct tax collections grew by 5.12% year-on-year in FY 2025–26.

• वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष-दर-वर्ष 5.12% बढ़ा।
• The total net direct tax collection stood at Rs. 23,40,406 crore.
• कुल शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23,40,406 करोड़ रुपये रहा।
• Gross direct tax collections reached Rs. 28,11,936 crore, showing a growth of 4.03% over FY 2024–25.
• सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 28,11,936 करोड़ रुपये रहा, जो FY 2024–25 की तुलना में 4.03% अधिक है।
• Corporate tax collections increased to Rs. 13,81,606 crore.
• कॉर्पोरेट कर संग्रह बढ़कर 13,81,606 करोड़ रुपये हो गया।
• Non-corporate tax collections (including individuals, HUFs, firms, etc.) stood at Rs. 13,72,474 crore.
• गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह (व्यक्तियों, HUF, फर्म आदि) 13,72,474 करोड़ रुपये रहा।
• Securities Transaction Tax (STT) collections rose to Rs. 57,522 crore.
• सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) संग्रह बढ़कर 57,522 करोड़ रुपये हो गया।

Ques: What was the non-food credit growth rate recorded by SCBs in FY 2025-26?

प्रश्न: FY 2025-26 में SCBs द्वारा दर्ज गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर क्या थी?

A) 10.9%
B) 12.5%
C) 15.9%
D) 18.2%
E) 20%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Scheduled Commercial Banks (SCBs) recorded a strong 15.9% year-on-year non-food credit growth in FY 2025-26.
• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने FY 2025-26 में 15.9% की वार्षिक गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर्ज की।

• Total outstanding credit reached ₹212.9 lakh crore, increasing by ₹29.2 lakh crore over the previous year.

• कुल बकाया ऋण ₹212.9 लाख करोड़ पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹29.2 लाख करोड़ अधिक है।

• Growth was broad-based, led by services (19%), followed by personal loans (16.2%), industry (15%), and agriculture (15.7%).

• वृद्धि व्यापक रही, जिसमें सेवाएं (19%), पर्सनल लोन (16.2%), उद्योग (15%) और कृषि (15.7%) प्रमुख रहे।

• Strong credit growth reflects improving economic activity, rising demand, and increased lending across sectors.

• यह मजबूत क्रेडिट वृद्धि बेहतर आर्थिक गतिविधि, बढ़ती मांग और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण विस्तार को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Regulator of Banks – Reserve Bank of India

• बैंकों का नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

• RBI Established – 1 April 1935

• RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935

• RBI Headquarters – Mumbai

• RBI मुख्यालय – मुंबई

Ques: What was the total Goods and Services Tax (GST) collection of India in April 2026?

प्रश्न: अप्रैल 2026 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह कितना रहा?

A) Rs. 2.10 lakh crore / 2.10 लाख करोड़ रुपये

B) Rs. 2.25 lakh crore / 2.25 लाख करोड़ रुपये

C) Rs. 2.33 lakh crore / 2.33 लाख करोड़ रुपये

D) Rs. 2.42 lakh crore / 2.42 लाख करोड़ रुपये

E) Rs. 2.50 lakh crore / 2.50 लाख करोड़ रुपये

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's GST collections reached an all-time high of Rs. 2.42 lakh crore in April 2026.

• अप्रैल 2026 में भारत का GST संग्रह 2.42 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

• This is the highest-ever monthly GST collection recorded in India.

• यह भारत में अब तक का सबसे अधिक मासिक GST संग्रह है।

• In April 2025, GST collection was Rs. 2.33 lakh crore.

• अप्रैल 2025 में GST संग्रह 2.33 लाख करोड़ रुपये था।

• The Year-on-Year (YoY) growth in April 2026 is 8.7%.

• अप्रैल 2026 में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि 8.7% रही।

• The increase reflects strong economic activity and improved compliance.

• यह वृद्धि मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर अनुपालन को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• GST Implemented – 1 July 2017

• GST लागू – 1 जुलाई 2017

• GST is an indirect tax replacing multiple taxes like VAT, Service Tax, Excise Duty

• GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने VAT, सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसे कई करों को प्रतिस्थापित किया

• GST Council Chairman – Union Finance Minister

• GST परिषद के अध्यक्ष – केंद्रीय वित्त मंत्री

Ques: What are Electronic Gold Receipts (EGRs) launched by the National Stock Exchange (NSE)?

प्रश्न: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा लॉन्च किए गए Electronic Gold Receipts (EGRs) क्या हैं?

A) Digital currency backed by RBI / RBI द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा

B) Electronic records representing ownership of physical gold / भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

C) Gold mining licences / स्वर्ण खनन लाइसेंस

D) Cryptocurrency linked with gold / सोने से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी

E) Gold loan certificates / गोल्ड लोन प्रमाणपत्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• National Stock Exchange (NSE) has launched Electronic Gold Receipts (EGRs) as a new instrument for gold trading in India.

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने भारत में सोने के व्यापार के लिए Electronic Gold Receipts (EGRs) लॉन्च किए हैं।

• EGRs are electronic records representing ownership of physical gold stored in approved vaults.

• EGRs स्वीकृत वॉल्ट्स में रखे गए भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं।

• NSE demonstrated the dematerialisation of a 1000-gram gold bar into an Electronic Gold Receipt.

• NSE ने 1000 ग्राम सोने की बार को Electronic Gold Receipt में डिमैटेरियलाइज करने का प्रदर्शन किया।

• EGRs are dematerialised securities and are held electronically in demat accounts.

• EGRs डिमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज हैं और इन्हें डिमैट खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाता है।

• The gold backing EGRs is stored in SEBI-accredited vaults.

• EGRs के पीछे का सोना SEBI-मान्यता प्राप्त वॉल्ट्स में रखा जाता है।
• Each EGR is fully backed by real physical gold.
• प्रत्येक EGR पूरी तरह वास्तविक भौतिक सोने द्वारा समर्थित होता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• National Stock Exchange of India Limited Founded – 27 November 1992
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना – 27 नवंबर 1992
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• MD and CEO – Ashish Kumar Chauhan
• एमडी और सीईओ – आशीष कुमार चौहान

Ques: Under the RBI's updated regulatory framework, after how many days from the due date will a credit card account be marked as "past due"?
प्रश्न: RBI के नए नियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाते को देय तिथि के कितने दिनों बाद "पास्ट ड्यू" माना जाएगा?

A) 1 day / 1 दिन
B) 2 days / 2 दिन
C) 3 days / 3 दिन
D) 5 days / 5 दिन
E) 7 days / 7 दिन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has introduced a 3-day grace period for credit card payments.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए 3 दिन की ग्रेस अवधि शुरू की

है।

• A credit card account will be marked as “past due” only after 3 days from the due date.

• क्रेडिट कार्ड खाते को देय तिथि के 3 दिन बाद ही “पास्ट ड्यू” माना जाएगा।

• Earlier, accounts could be classified as overdue immediately after the due date.

• पहले खातों को देय तिथि के तुरंत बाद ओवरड्यू माना जा सकता था।

• Banks can impose late payment charges and report to credit bureaus only after the 3-day grace period.

• बैंक 3 दिन की ग्रेस अवधि के बाद ही लेट फीस लगा सकते हैं और क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट कर सकते हैं।

• The new rule will come into effect from 1 April 2027.

• यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।

• If payment is made within the grace period, there will be no immediate penalty or negative credit reporting impact.

• यदि भुगतान ग्रेस अवधि के भीतर कर दिया जाता है, तो कोई तत्काल जुर्माना या नकारात्मक क्रेडिट रिपोर्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा।

• Under revised norms, penalties will apply only on the outstanding amount and not on the total billed amount.

• संशोधित नियमों के तहत जुर्माना केवल बकाया राशि पर लगाया जाएगा, पूरे बिल की राशि पर नहीं।

Ques: S&P Global has reduced India’s GDP growth forecast for Financial Year 2026–27 to what percentage?

प्रश्न: S&P Global ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है?

A) 5.8%
B) 6.2%
C) 6.6%
D) 7.0%
E) 7.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• S&P Global lowered India's growth forecast for Financial Year 2026–27 by 50 basis points to 6.6 per cent.

• S&P Global ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया।

• The findings were published in a report titled "India Forward".

• यह जानकारी "India Forward" नामक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई।

• The report was jointly prepared by S&P Global and Crisil.

• यह रिपोर्ट S&P Global और Crisil द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई।

• According to the report, India is facing external economic shocks.

• रिपोर्ट के अनुसार भारत बाहरी आर्थिक झटकों का सामना कर रहा है।

• These challenges include energy supply disruptions, rising oil and gas prices, and currency volatility.

• इन चुनौतियों में ऊर्जा आपूर्ति में बाधा, तेल और गैस की बढ़ती कीमतें तथा मुद्रा विनिमय दर में अस्थिरता शामिल हैं।

• A basis point is one-hundredth of a percentage point.

• एक बेसिस पॉइंट, प्रतिशत के सौवें हिस्से के बराबर होता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• S&P Global Headquarters – New York, United States

• S&P Global का मुख्यालय – न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

• CRISIL Full Form – Credit Rating Information Services of India Limited

• CRISIL का पूर्ण रूप – क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड

• Crisil Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• Crisil का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

Ques: What percentage of the Reserve Bank of India's (RBI) total gold holdings is now stored within India as of March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कुल स्वर्ण भंडार का कितना प्रतिशत भारत में संग्रहीत है?

A) 65%
B) 70%
C) 77%
D) 82%
E) 85%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Around 77% of RBI's total gold holdings is now stored within India.
• RBI के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 77% अब भारत में संग्रहीत है।
• RBI moved 104.23 metric tonnes (MT) of gold reserves domestically in the six months ended March 2026.
• मार्च 2026 तक के छह महीनों में RBI ने 104.23 मीट्रिक टन सोना भारत में स्थानांतरित किया।
• The move reflects a continued shift toward domestic gold custody.
• यह कदम घरेलू स्वर्ण भंडारण की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
• RBI's total gold holdings increased slightly to 880.52 MT in March 2026.
• मार्च 2026 में RBI का कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गया।
• According to RBI data, 197.67 MT of gold is kept with the Bank of England and the Bank for International Settlements (BIS).
• RBI के अनुसार 197.67 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास रखा गया है।
• Another 2.80 MT is maintained as gold deposits.
• अतिरिक्त 2.80 मीट्रिक टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है।
• In FY 2025–26, RBI brought 168.06 MT of gold back to India.
• वित्त वर्ष 2025–26 में RBI ने 168.06 मीट्रिक टन सोना भारत वापस लाया।
• This is higher than 107.21 MT in 2023–24 and 103.68 MT in 2024–25.

• यह 2023–24 के 107.21 मीट्रिक टन और 2024–25 के 103.68 मीट्रिक टन से अधिक है।

Ques: Kotak Mahindra Bank has received RBI approval to acquire up to 9.99% stake in which two banks?

प्रश्न: Kotak Mahindra Bank को RBI से किन दो बैंकों में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है?

A) HDFC Bank and ICICI Bank / एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक
B) AU Small Finance Bank and Federal Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक
C) Punjab National Bank and Bank of Baroda / पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा
D) Axis Bank and IndusInd Bank / एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक
E) Canara Bank and Indian Bank / केनरा बैंक और इंडियन बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Kotak Mahindra Bank has received approval from the Reserve Bank of India to acquire up to 9.99% stake each in AU Small Finance Bank and Federal Bank.
• Kotak Mahindra Bank को Reserve Bank of India से AU Small Finance Bank और Federal Bank में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है।
• The approval includes acquisition of paid-up share capital or voting rights.
• यह मंजूरी paid-up share capital या voting rights खरीदने के लिए दी गई है।
• The investment can be made by Kotak Mahindra Bank along with its subsidiaries, mutual funds, or other group entities.
• यह निवेश Kotak Mahindra Bank अपनी subsidiaries, mutual funds या group entities के माध्यम से कर सकता है।
• Such investments help diversify portfolio holdings and strengthen strategic presence in the banking sector.
• इस प्रकार का निवेश बैंकिंग सेक्टर में रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने और

पोर्टफोलियो विविधता बढ़ाने में मदद करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Headquarters of Kotak Mahindra Bank – Mumbai
- Kotak Mahindra Bank का मुख्यालय – मुंबई
- Founder of Kotak Mahindra Bank – Uday Kotak
- Kotak Mahindra Bank के संस्थापक – उदय कोटक
- Headquarters of AU Small Finance Bank – Jaipur
- AU Small Finance Bank का मुख्यालय – जयपुर
- Headquarters of Federal Bank – Aluva, Kochi, Kerala
- Federal Bank का मुख्यालय – अलुवा, कोच्चि, केरल

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of City Union Bank (CUB)?

प्रश्न: City Union Bank (CUB) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) N. Kamakodi / एन. कामकोडी

B) R. Vijay Anandh / आर. विजय आनंद

C) Vishwavir Ahuja / विश्ववीर आहूजा

D) Chandra Shekhar Ghosh / चंद्र शेखर घोष

E) Rajesh Magow / राजेश मागो

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

· R. Vijay Anandh has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of City Union Bank (CUB).

· आर. विजय आनंद को City Union Bank (CUB) का प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।

· His term will be for three years.
· उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
· He replaced N. Kamakodi in the position.
· उन्होंने इस पद पर एन. कामकोडी का स्थान लिया है।
· Before joining City Union Bank, R. Vijay Anandh worked at RBL Bank.
· City Union Bank से पहले आर. विजय आनंद RBL Bank में कार्यरत थे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

· City Union Bank Founded – 1904
· सिटी यूनियन बैंक की स्थापना – 1904
· Headquarters – Kumbakonam, Tamil Nadu
· मुख्यालय – कुंभकोणम, तमिलनाडु

Ques: India will take a loan of 500 million U.S. dollars from which organisation to develop integrated urban economic regions?
प्रश्न: एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए भारत किस संगठन से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेगा?

A) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
B) International Monetary Fund / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
C) Asian Infrastructure Investment Bank / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
D) New Development Bank / न्यू डेवलपमेंट बैंक
E) World Bank / विश्व बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

· India will take a loan of 500 million U.S. dollars from the World Bank.
· भारत विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेगा।

· The loan will support the development of integrated urban economic regions.
· यह ऋण एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास में सहायता करेगा।
· The initiative aims to promote planned urbanisation.
· इस पहल का उद्देश्य नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना है।
· It will also support infrastructure expansion across cities.
· यह शहरों में बुनियादी ढांचे के विस्तार को भी समर्थन देगा।
· The project is expected to create economic growth hubs in urban areas.
· इस परियोजना से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास केंद्र विकसित होने की उम्मीद है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

· World Bank Established – 1944
· विश्व बैंक की स्थापना – 1944
· Headquarters – Washington, D.C., United States
· मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
· President of the World Bank – Ajay Banga
· विश्व बैंक के अध्यक्ष – अजय बंगा
· The World Bank provides financial and technical assistance for development projects
· विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है

Ques: What is the name of the new financing facility launched by the Asian Development Bank (ADB) to strengthen critical minerals supply chains?
प्रश्न: एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए शुरू की गई नई वित्तपोषण सुविधा का नाम क्या है?

A) Green Minerals Initiative / ग्रीन मिनरल्स इनिशिएटिव
B) Asia Mineral Security Facility / एशिया मिनरल सिक्योरिटी फैसिलिटी
C) Critical Minerals-to-Manufacturing Financing Partnership Facility / क्रिटिकल मिनरल्स-टू-मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी

D) Indo-Pacific Mining Fund / इंडो-पैसिफिक माइनिंग फंड

E) Sustainable Minerals Partnership / सस्टेनेबल मिनरल्स पार्टनरशिप

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

· Asian Development Bank (ADB) launched a new financing facility titled "Critical Minerals-to-Manufacturing Financing Partnership Facility".

· एशियाई विकास बैंक (ADB) ने "Critical Minerals-to-Manufacturing Financing Partnership Facility" नामक नई वित्तपोषण सुविधा शुरू की।

· The initiative aims to strengthen critical minerals supply chains across Asia and the Pacific region.

· इस पहल का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

· The facility was launched during ADB's 59th Annual Meeting of the Board of Governors in Samarkand, Uzbekistan.

· इस सुविधा की शुरुआत उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित ADB की 59वीं वार्षिक बैठक के दौरान की गई।

· The facility will function through two windows — Grant Window and Catalytic Finance Window.

· यह सुविधा दो विंडो — Grant Window और Catalytic Finance Window — के माध्यम से कार्य करेगी।

· The Grant Window will support feasibility studies, environmental and social assessments, technical assistance, and knowledge-sharing activities.

· Grant Window व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरणीय एवं सामाजिक मूल्यांकन, तकनीकी सहायता और ज्ञान-साझाकरण गतिविधियों को समर्थन देगा।

· Japan committed $20 million and the United Kingdom committed $1.6 million to the Grant Window.

· जापान ने Grant Window के लिए 20 मिलियन डॉलर और यूनाइटेड किंगडम ने 1.6 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की।

· The Catalytic Finance Window is designed to mobilise co-financing and risk-sharing support.

· Catalytic Finance Window का उद्देश्य सह-वित्तपोषण और जोखिम-साझाकरण सहायता जुटाना है।

· Korea Eximbank and K-SURE each signed a $500 million memorandum as the facility's first partners.

· Korea Eximbank और K-SURE ने इस सुविधा के पहले साझेदार के रूप में 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

· ADB Headquarters – Manila, Philippines
· ADB का मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस
· ADB Established – 1966
· ADB की स्थापना – 1966
· Member Countries – 69
· सदस्य देश – 69
· K-SURE Full Form – Korea Trade Insurance Corporation
· K-SURE का पूर्ण रूप – कोरिया ट्रेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन

Ques: Which bank recently received PFRDA approval to sponsor and set up its own pension fund?

प्रश्न: हाल ही में किस बैंक को अपना पेंशन फंड स्थापित करने हेतु PFRDA की मंजूरी मिली है?

A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
B) Canara Bank / केनरा बैंक
C) Bank of India / बैंक ऑफ इंडिया
D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda (BoB) has received a Letter of Appointment (LoA) from the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
• Bank of Baroda (BoB) को Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) से Letter of Appointment (LoA) प्राप्त हुआ है।
• This approval allows the bank to act as a Sponsor for a Pension Fund.
• यह मंजूरी बैंक को पेंशन फंड के स्पॉन्सर के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है।
• With this approval, Bank of Baroda can establish its own Pension Fund Management Company (PFMC), subject to other regulatory approvals.
• इस मंजूरी के बाद बैंक अन्य नियामकीय स्वीकृतियों के अधीन अपनी Pension Fund Management Company (PFMC) स्थापित कर सकेगा।
• The move will help BoB expand its presence in India's retirement and pension sector.
• यह कदम BoB को भारत के रिटायरमेंट और पेंशन सेक्टर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेगा।
• Pension funds mainly manage investments under the National Pension System (NPS).
• पेंशन फंड मुख्य रूप से National Pension System (NPS) के तहत निवेश प्रबंधन करते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Headquarters of Bank of Baroda – Vadodara, Gujarat
• Bank of Baroda का मुख्यालय – वडोदरा, गुजरात
• Established Year of Bank of Baroda – 1908
• Bank of Baroda की स्थापना – 1908
• Pension Fund Regulatory and Development Authority Established – 2003
• Pension Fund Regulatory and Development Authority की स्थापना – 2003
• Headquarters of PFRDA – New Delhi
• PFRDA का मुख्यालय – नई दिल्ली
• National Pension System (NPS) Regulator – PFRDA
• National Pension System (NPS) का नियामक – PFRDA

Ques: Jio Payments Bank has partnered with which fintech company to expand banking services in semi-urban and underserved areas?
प्रश्न: Jio Payments Bank ने अर्ध-शहरी और कम सेवा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के

विस्तार के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है?

A) Paytm / पेटीएम

B) BharatPe / भारतपे

C) MobiKwik / मोबिक्विक

D) Razorpay / रेजरपे

E) Ezeepay / ईज़ीपे

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

· Jio Payments Bank partnered with fintech company Ezeepay.

· Jio Payments Bank ने फिनटेक कंपनी Ezeepay के साथ साझेदारी की है।

· The partnership aims to provide essential banking services across more than 12,000 semi-urban and underserved PIN codes.

· इस साझेदारी का उद्देश्य 12,000 से अधिक अर्ध-शहरी और कम सेवा वाले पिन कोड क्षेत्रों में आवश्यक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है।

· The alliance uses Ezeepay's merchant network as Business Correspondents.

· यह साझेदारी Ezeepay के मर्चेंट नेटवर्क को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में उपयोग करेगी।

· The initiative is expected to improve financial inclusion in remote and underserved areas.

· यह पहल दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।

· Jio Payments Bank is currently a subsidiary of Jio Financial Services.

· Jio Payments Bank वर्तमान में Jio Financial Services की सहायक कंपनी है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

· Jio Payments Bank Founded – 3 April 2018

· Jio Payments Bank की स्थापना – 3 अप्रैल 2018

· Headquarters – Navi Mumbai, Maharashtra

· मुख्यालय – नवी मुंबई, महाराष्ट्र
· Parent Company – Jio Financial Services
· मूल कंपनी – जियो फाइनेंशियल सर्विसेज

Ques: According to the World Migration Report 2026 by IOM, which country remained the world's top remittance receiver in 2024 and what was the remittance amount received?
प्रश्न: IOM की World Migration Report 2026 के अनुसार 2024 में कौन-सा देश विश्व का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बना रहा और उसे कितना प्रेषण प्राप्त हुआ?

A) Mexico — $100 billion / मेक्सिको — $100 बिलियन
B) India — $137.67 billion / भारत — $137.67 बिलियन
C) Philippines — $83.15 billion / फिलीपींस — $83.15 बिलियन
D) France — $68.91 billion / फ्रांस — $68.91 बिलियन
E) USA — $137.67 billion / अमेरिका — $137.67 बिलियन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• According to the World Migration Report 2026 released by IOM, India received more than $137.67 billion in remittances in 2024.
• IOM द्वारा जारी World Migration Report 2026 के अनुसार, भारत ने 2024 में $137.67 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त किया।
• India remained the world's top remittance receiving country and became the only country to cross the $100 billion mark.
• भारत विश्व का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा और $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र देश बना।
• India has held the No.1 position since 2010, when remittance inflows were $53.48 billion.
• भारत 2010 से शीर्ष स्थान पर है, जब उसे $53.48 बिलियन प्रेषण प्राप्त हुआ था।
• India's remittance inflows increased from $68.91 billion in 2015 to $83.15 billion in 2020 and $137.67 billion in 2024.
• भारत का प्रेषण 2015 में $68.91 बिलियन, 2020 में $83.15 बिलियन और 2024 में $137.67 बिलियन तक पहुंच गया।

• The top remittance recipient countries in 2024 were India, Mexico, Philippines, and France.
• 2024 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत, मेक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस रहे।
• The United States remained the largest remittance-sending country globally.
• संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण भेजने वाला देश बना रहा।
• The India–UAE migration corridor ranked 5th globally, while the India–US corridor ranked 6th.
• भारत–UAE प्रवासन गलियारा विश्व में 5वें स्थान पर और भारत–US गलियारा 6वें स्थान पर रहा।
• South Asia recorded the highest estimated remittance growth in 2024 at 11.8%.
• दक्षिण एशिया ने 2024 में 11.8% की सर्वाधिक अनुमानित प्रेषण वृद्धि दर्ज की।
• The report also noted that Asia accounts for the largest share of global mobile students, with China and India as leading origin countries.
• रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मोबाइल छात्रों में एशिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें चीन और भारत प्रमुख मूल देश हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Report – World Migration Report 2026
• रिपोर्ट – World Migration Report 2026
• Released By – IOM (International Organization for Migration)
• जारीकर्ता – IOM (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन)
• IOM Headquarters – Geneva, Switzerland
• IOM मुख्यालय – जिनेवा, स्विट्जरलैंड
• IOM Founded – 1951
• IOM की स्थापना – 1951

Ques: What restriction has RBI removed while easing capital adequacy norms for banks effective May 8, 2026?

प्रश्न: RBI ने 8 मई 2026 से बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड आसान करते हुए कौन सी शर्त हटाई है?

A) Banks cannot include annual profits in CRAR / बैंक CRAR में वार्षिक लाभ

शामिल नहीं कर सकते

B) NPA provisioning must not deviate more than 25% from 4-quarter average / NPA प्रावधान 4-तिमाही औसत से 25% से अधिक विचलित नहीं होना चाहिए

C) Banks must maintain minimum CRAR of 12% / बैंकों को न्यूनतम 12% CRAR बनाए रखना होगा

D) Quarterly profits can only be included after annual audit / तिमाही लाभ केवल वार्षिक ऑडिट के बाद शामिल किए जा सकते हैं

E) NPA provisioning must not exceed 10% of total assets / NPA प्रावधान कुल संपत्ति के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• RBI eased capital adequacy norms effective May 8, 2026, allowing banks to include current-year profits in CRAR calculations on a quarterly basis.

• RBI ने 8 मई 2026 से पूंजी पर्याप्तता मानदंड आसान किए, जिससे बैंकों को तिमाही आधार पर CRAR गणना में चालू वर्ष के लाभ शामिल करने की अनुमति मिली।

• Earlier, banks could include quarterly net profits in CRAR only if NPA provisioning did not deviate by more than 25% from the four-quarter average.

• पहले बैंक CRAR में तिमाही शुद्ध लाभ तभी शामिल कर सकते थे जब NPA प्रावधान चार-तिमाही औसत से 25% से अधिक विचलित न हो।

• RBI has now completely removed this restrictive condition.

• RBI ने अब इस प्रतिबंधात्मक शर्त को पूरी तरह हटा दिया है।

• Banks can now more freely include current-year profits in CRAR calculations, provided financial statements are audited or reviewed.

• अब बैंक वित्तीय विवरणों के ऑडिटेड या समीक्षित होने की शर्त पर अधिक स्वतंत्र रूप से CRAR गणना में चालू वर्ष के लाभ शामिल कर सकते हैं।

• The move aligns with Basel III norms and will help banks better reflect their capital strength.

• यह कदम Basel III मानदंडों के अनुरूप है और बैंकों को अपनी पूंजी शक्ति का बेहतर प्रतिबिंब दिखाने में मदद करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Regulator — Reserve Bank of India (RBI)
- RBI Governor — Sanjay Malhotra | HQ — Mumbai
- Effective Date — May 8, 2026
- Change — Removal of 25% NPA deviation condition for CRAR profit inclusion
- CRAR Full Form — Capital to Risk-Weighted Assets Ratio
- Old Condition — NPA provisioning must not deviate >25% from 4-quarter average
- New Rule — Quarterly profits includable in CRAR without NPA condition
- Condition Retained — Financial statements must be audited/reviewed
- Framework — Basel III Capital Adequacy Framework
- Minimum CRAR (India) — 9% (vs Basel III requirement of 8%)
- Minimum Tier 1 Capital — 7%
- Capital Conservation Buffer — 2.5%

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) imposed a penalty of Rs. 31.80 lakh on which bank for non-compliance with KYC provisions?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC प्रावधानों का पालन न करने पर किस बैंक पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

C) YES Bank / यस बैंक

D) Axis Bank / एक्सिस बैंक

E) IndusInd Bank / इंडसइंड बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) imposed a penalty of Rs. 31.80 lakh on YES Bank.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने YES Bank पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

• The penalty was imposed for non-compliance with certain provisions related to "Know Your Customer" (KYC) norms.

• यह जुर्माना "Know Your Customer" (KYC) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण लगाया गया।

• RBI also imposed a penalty of Rs. 1.8 lakh on Hinduja Housing Finance Ltd.

• RBI ने Hinduja Housing Finance Ltd पर भी 1.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

• The penalty on Hinduja Housing Finance was related to non-compliance with RBI directions regarding governance.

• Hinduja Housing Finance पर लगाया गया जुर्माना शासन (Governance) से संबंधित RBI निर्देशों का पालन न करने के कारण था।

• RBI regulates banks and financial institutions in India to ensure compliance with banking and financial norms.

• RBI भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है ताकि बैंकिंग और वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Ques: What is the name of the task force constituted by SEBI to evaluate cybersecurity risks arising from advanced AI tools?

प्रश्न: उन्नत AI टूल्स से उत्पन्न साइबर सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए SEBI द्वारा गठित टास्क फोर्स का नाम क्या है?

A) Cyber Shield India / साइबर शील्ड इंडिया

B) AI Secure Task Force / एआई सिक्योर टास्क फोर्स

C) Secure Market Initiative / सिक्योर मार्केट इनिशिएटिव

D) Digital Defence Group / डिजिटल डिफेंस ग्रुप

E) Cyber-suraksha.ai / साइबर-सुरक्षा.एआई

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) constituted a dedicated task force named “Cyber-suraksha.ai”.

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने “Cyber-suraksha.ai” नामक एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया।

• The task force will evaluate cybersecurity risks arising from advanced Artificial Intelligence (AI) tools.

• यह टास्क फोर्स उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से उत्पन्न साइबर सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन करेगी।

• Its objective is to strengthen cyber resilience in the securities market ecosystem.

• इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार तंत्र में साइबर लचीलापन (Cyber Resilience) को मजबूत करना है।

• The group will examine cybersecurity risks linked to AI-based systems.

• यह समूह AI-आधारित प्रणालियों से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच करेगा।

• It will also develop uniform mitigation strategies and share threat intelligence.

• यह समान जोखिम-निवारण रणनीतियाँ विकसित करेगा और खतरे संबंधी जानकारी साझा करेगा।

• The task force will review vulnerabilities and cyber incidents across the securities market ecosystem.

• यह टास्क फोर्स प्रतिभूति बाजार तंत्र में कमजोरियों और साइबर घटनाओं की समीक्षा भी करेगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SEBI Established – 1988

• SEBI की स्थापना – 1988

• SEBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• SEBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• SEBI Chairman – Tuhin Kanta Pandey

• SEBI के अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय

Ques: What was the standalone net profit reported by SBI in Financial Year 2025–26?

प्रश्न: वित्त वर्ष 2025–26 में SBI द्वारा घोषित स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ कितना था?

A) Rs. 70,901 crore / 70,901 करोड़ रुपये

B) Rs. 75,450 crore / 75,450 करोड़ रुपये

C) Rs. 80,032 crore / 80,032 करोड़ रुपये

D) Rs. 82,500 crore / 82,500 करोड़ रुपये

E) Rs. 85,000 crore / 85,000 करोड़ रुपये

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• State Bank of India (SBI) reported a 13% year-on-year increase in standalone net profit in Financial Year 2025–26.

• भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2025–26 में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 13% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

• SBI's standalone net profit stood at Rs. 80,032 crore in FY 2025–26.

• वित्त वर्ष 2025–26 में SBI का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 80,032 करोड़ रुपये रहा।

• In Financial Year 2024–25, the standalone net profit was Rs. 70,901 crore.

• वित्त वर्ष 2024–25 में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 70,901 करोड़ रुपये था।

• In the fourth quarter of FY 2025–26, SBI reported a standalone net profit of Rs. 19,684 crore.

• वित्त वर्ष 2025–26 की चौथी तिमाही में SBI ने 19,684 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया।

• The net profit in the year-ago quarter was Rs. 18,643 crore.

• पिछले वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ 18,643 करोड़ रुपये था।

• The Q4 profit showed a modest 6% year-on-year increase.

• चौथी तिमाही का लाभ वर्ष-दर-वर्ष 6% की मामूली वृद्धि दर्शाता है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) signed an MoU on mutual cooperation in central banking with which institution?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्रीय बैंकिंग में पारस्परिक सहयोग हेतु किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

A) World Bank / विश्व बैंक

B) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक

C) Bank of England / बैंक ऑफ इंग्लैंड

D) International Monetary Fund / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

E) European Central Bank / यूरोपीय केंद्रीय बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) and the European Central Bank (ECB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on mutual cooperation in the field of central banking.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) ने केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• The MoU was signed by RBI Governor Sanjay Malhotra and ECB President Christine Lagarde.

• इस MoU पर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड ने हस्ताक्षर किए।

• The signing took place on the sidelines of the meetings of the Bank for International Settlements (BIS) in Basel.

• यह हस्ताक्षर Basel में आयोजित Bank for International Settlements (BIS) की बैठकों के दौरान किए गए।

• The new MoU updates the earlier agreement signed between RBI and ECB in

2015.

• यह नया MoU RBI और ECB के बीच 2015 में हुए पुराने समझौते का अद्यतन संस्करण है।

• The agreement aims to strengthen cooperation and exchange of information in central banking matters.

• इस समझौते का उद्देश्य केंद्रीय बैंकिंग मामलों में सहयोग और सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• European Central Bank (ECB) Established – 1 June 1998
• यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की स्थापना – 1 जून 1998
• ECB Headquarters – Frankfurt, Germany
• ECB का मुख्यालय – फ्रैंकफर्ट, जर्मनी
• ECB President – Christine Lagarde
• ECB की अध्यक्ष – क्रिस्टीन लगार्ड
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• RBI के गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• BIS Headquarters – Basel, Switzerland
• BIS का मुख्यालय – बेसल, स्विट्ज़रलैंड

Ques: Which state has the highest number of registered investors on the National Stock Exchange (NSE) as of April 2026?

प्रश्न: अप्रैल 2026 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सबसे अधिक पंजीकृत निवेशक किस राज्य के हैं?

A) Gujarat / गुजरात
B) Karnataka / कर्नाटक
C) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
D) Maharashtra / महाराष्ट्र
E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The National Stock Exchange of India (NSE) crossed 13 crore unique registered investors.

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 13 करोड़ यूनिक पंजीकृत निवेशकों का आंकड़ा पार कर लिया।

• The latest 1 crore investors were added in just 7 months since September 2025.

• सितंबर 2025 के बाद केवल 7 महीनों में 1 करोड़ नए निवेशक जुड़े।

• NSE took 14 years to reach its first 1 crore investors after commencement of operations.

• NSE को संचालन शुरू होने के बाद पहले 1 करोड़ निवेशकों तक पहुंचने में 14 वर्ष लगे।

• It took another 11 years to add the next 3 crore investors, reflecting rapid retail participation in recent years.

• अगले 3 करोड़ निवेशक जोड़ने में 11 वर्ष लगे, जो हाल के वर्षों में खुदरा निवेशकों की तेज भागीदारी को दर्शाता है।

• The total number of client codes reached 25.7 crore as of 25 April 2026.

• 25 अप्रैल 2026 तक कुल क्लाइंट कोड की संख्या 25.7 करोड़ तक पहुंच गई।

• Investor participation expanded to 99.85% of India's PIN codes, showing deep geographical penetration.

• निवेशकों की भागीदारी भारत के 99.85% पिन कोड तक पहुंच गई, जो व्यापक भौगोलिक पहुंच को दर्शाता है।

• Maharashtra leads with 2 crore investors, followed by Uttar Pradesh with 1.5 crore and Gujarat with 1.1 crore investors.

• महाराष्ट्र 2 करोड़ निवेशकों के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (1.5 करोड़) और गुजरात (1.1 करोड़) हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• NSE Full Form – National Stock Exchange

• NSE का पूर्ण रूप – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

• NSE Founded – 27 November 1992

• NSE की स्थापना – 27 नवंबर 1992
• NSE Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• NSE का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• NSE MD & CEO – Ashish Kumar Chauhan
• NSE के MD एवं CEO – आशीष कुमार चौहान

Ques: What is the annual premium for PMSBY and what is the maximum accidental death cover provided under the scheme?
प्रश्न: PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम क्या है और योजना के तहत अधिकतम दुर्घटना मृत्यु कवर कितना है?

A) ₹436/year — ₹4 lakh cover / ₹436 प्रति वर्ष — ₹4 लाख कवर
B) ₹20/year — ₹1 lakh cover / ₹20 प्रति year — ₹1 लाख कवर
C) ₹436/year — ₹2 lakh cover / ₹436 प्रति वर्ष — ₹2 लाख कवर
D) ₹20/year — ₹2 lakh cover / ₹20 प्रति वर्ष — ₹2 लाख कवर
E) ₹20/year — ₹4 lakh cover / ₹20 प्रति वर्ष — ₹4 लाख कवर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The three Jan Suraksha Schemes — PMJJBY, PMSBY and APY — completed 11 years on May 9, 2026.
• तीन जन सुरक्षा योजनाएं — PMJJBY, PMSBY और APY — 9 मई 2026 को 11 वर्ष पूर्ण कर गईं।
• These schemes were launched on May 9, 2015 by Prime Minister Narendra Modi to provide affordable financial security to vulnerable and underserved sections of society.
• इन योजनाओं को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था।
• PMJJBY recorded 27.43 crore cumulative enrolments as on 29 April 2026.

• PMJJBY में 29 अप्रैल 2026 तक 27.43 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए।
• Under PMJJBY, ₹21,512.50 crore was paid for 10,75,625 claims.
• PMJJBY के तहत 10,75,625 दावों के लिए ₹21,512.50 करोड़ का भुगतान किया गया।
• PMJJBY offers life insurance coverage for death due to any cause with a premium of ₹436 per year.
• PMJJBY किसी भी कारण से मृत्यु पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जिसका प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष है।
• The scheme covers individuals aged 18–50 years and provides a benefit of ₹2 lakh.
• यह योजना 18–50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कवर करती है और ₹2 लाख का लाभ प्रदान करती है।
• PMSBY recorded the highest enrolments among the three schemes with 58.09 crore cumulative enrolments.
• PMSBY में तीनों योजनाओं में सबसे अधिक 58.09 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए।
• PMSBY paid ₹3,667.52 crore for 1,84,662 claims.
• PMSBY के तहत 1,84,662 दावों के लिए ₹3,667.52 करोड़ का भुगतान किया गया।
• PMSBY provides accidental death and disability insurance with an annual premium of ₹20.
• PMSBY ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता बीमा प्रदान करती है।
• The scheme covers individuals aged 18–70 years and offers accidental death cover up to ₹2 lakh.
• यह योजना 18–70 वर्ष आयु वर्ग को कवर करती है और ₹2 लाख तक का दुर्घटना मृत्यु कवर प्रदान करती है।
• APY recorded 9.04 crore enrolments as on 30 April 2026.
• APY में 30 अप्रैल 2026 तक 9.04 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए।
• APY provides a guaranteed monthly pension ranging from ₹1,000 to ₹5,000 after the age of 60 years.
• APY 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन प्रदान करती है।
• APY is administered by PFRDA under the National Pension System (NPS).
• APY का संचालन PFRDA द्वारा National Pension System (NPS) के तहत किया जाता है।
• The schemes have significantly expanded financial inclusion and social

security coverage in India over the last 11 years.
• इन योजनाओं ने पिछले 11 वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को काफी बढ़ाया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Launch Date – 9 May 2015
• लॉन्च तिथि – 9 मई 2015
• 11th Anniversary – 9 May 2026
• 11वीं वर्षगांठ – 9 मई 2026
• Launched By – Prime Minister Narendra Modi
• लॉन्चकर्ता – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
• PMJJBY Full Form – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
• PMJJBY का पूर्ण रूप – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
• PMSBY Full Form – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
• PMSBY का पूर्ण रूप – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
• APY Full Form – Atal Pension Yojana
• APY का पूर्ण रूप – अटल पेंशन योजना
• PMJJBY Premium – ₹436 per year
• PMJJBY प्रीमियम – ₹436 प्रति वर्ष
• PMSBY Premium – ₹20 per year
• PMSBY प्रीमियम – ₹20 प्रति वर्ष
• PMJJBY Coverage – ₹2 lakh
• PMJJBY कवरेज – ₹2 लाख
• PMSBY Coverage – ₹2 lakh accidental death cover
• PMSBY कवरेज – ₹2 लाख दुर्घटना मृत्यु कवर
• APY Pension Range – ₹1,000 to ₹5,000 per month
• APY पेंशन सीमा – ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह
• Administered By APY – PFRDA under NPS
• APY का संचालन – PFRDA द्वारा NPS के तहत

Ques: Which Indian private sector bank recently signed a $500 million offshore loan with Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.?

प्रश्न: किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. के साथ 500 मिलियन डॉलर का ऑफशोर लोन समझौता किया?

A) Axis Bank / एक्सिस बैंक

B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

D) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

E) IndusInd Bank / इंडसइंड बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Axis Bank Ltd signed a $500 million offshore loan agreement with Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

• Axis Bank Ltd ने Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. के साथ 500 मिलियन डॉलर का ऑफशोर लोन समझौता किया।

• Axis Bank is India's third-largest private sector lender.

• Axis Bank भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक है।

• The offshore loan facility has a tenure of three years.

• इस ऑफशोर लोन सुविधा की अवधि तीन वर्ष है।

• The loan pricing will be based on SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

• इस ऋण की कीमत SOFR (Secured Overnight Financing Rate) के आधार पर तय की जाएगी।

• An offshore loan is borrowed from a bank or financial institution located outside the borrower's home country.

• ऑफशोर लोन वह ऋण होता है जो उधारकर्ता के देश के बाहर स्थित बैंक या वित्तीय संस्था से लिया जाता है।

• If an Indian bank or company takes a loan from a foreign bank located abroad, it is called an offshore loan.

• यदि कोई भारतीय बैंक या कंपनी विदेश में स्थित विदेशी बैंक से ऋण लेती है, तो उसे

ऑफशोर लोन कहा जाता है।

• SOFR is a benchmark interest rate used in global financial markets.

• SOFR वैश्विक वित्तीय बाजारों में उपयोग की जाने वाली एक मानक ब्याज दर है।

• It reflects the cost at which banks and financial institutions borrow money overnight.

• यह उस लागत को दर्शाता है जिस पर बैंक और वित्तीय संस्थान अल्पकालिक धन उधार लेते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Axis Bank Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• Axis Bank का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• Axis Bank Established – 1993

• Axis Bank की स्थापना – 1993

• SOFR Full Form – Secured Overnight Financing Rate

• SOFR का पूर्ण रूप – सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट

• Mitsubishi UFJ Financial Group Headquarters – Tokyo, Japan

• Mitsubishi UFJ Financial Group का मुख्यालय – टोक्यो, जापान

Ques: SBI Cards sold a stressed credit card receivables pool worth around how much to Integro Finserv?

प्रश्न: SBI Cards ने Integro Finserv को लगभग कितने मूल्य का stressed credit card receivables pool बेचा?

A) ₹500 crore / ₹500 करोड़

B) ₹1,000 crore / ₹1,000 करोड़

C) ₹1,800 crore / ₹1,800 करोड़

D) ₹2,500 crore / ₹2,500 करोड़

E) ₹5,000 crore / ₹5,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SBI Cards and Payment Services sold a stressed credit card receivables pool worth around ₹1,800 crore to Integro Finserv.

• SBI Cards and Payment Services ने लगभग ₹1,800 करोड़ का stressed credit card receivables pool Integro Finserv को बेचा।

• Integro Finserv is a Mumbai-based Non-Banking Financial Company (NBFC).

• Integro Finserv मुंबई स्थित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।

• SBI Cards had earlier executed a similar sale worth ₹200 crore in 2022.

• SBI Cards ने 2022 में भी ₹200 करोड़ का इसी प्रकार का सौदा किया था।

• The move reflects a growing trend of portfolio clean-up measures among financial institutions.

• यह कदम वित्तीय संस्थानों द्वारा पोर्टफोलियो क्लीन-अप उपायों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

• SBI Cards manages a credit card receivables book of around ₹60,000 crore.

• SBI Cards लगभग ₹60,000 करोड़ के credit card receivables book का प्रबंधन करता है।

• The company holds nearly 18% market share, making it one of the top three credit card issuers in India.

• कंपनी का लगभग 18% बाजार हिस्सा है, जिससे यह भारत के शीर्ष तीन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में शामिल है।

• SBI Cards has more than 20 million active credit cards.

• SBI Cards के पास 20 मिलियन से अधिक सक्रिय क्रेडिट कार्ड हैं।

• Retail NPA sales by banks increased sharply from ₹9,093 crore in September 2025 to ₹24,814 crore in December 2025.

• बैंकों द्वारा retail NPA बिक्री सितंबर 2025 के ₹9,093 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2025 में ₹24,814 करोड़ हो गई।

• Recovery rates remain low at around 15%, indicating continued stress in unsecured lending portfolios.

• रिकवरी दर लगभग 15% बनी हुई है, जो unsecured lending portfolios में लगातार दबाव को दर्शाती है।

Ques: Why did the Securities and Exchange Board of India (SEBI) discontinue the Investor Risk Reduction Access (IRRA) platform?

प्रश्न: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Investor Risk Reduction Access (IRRA) प्लेटफॉर्म को क्यों बंद किया?

A) Due to low internet connectivity / कम इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण

B) Because brokers opposed the platform / ब्रोकरों के विरोध के कारण

C) Due to redundancy after improvements in technological and cyber resilience systems / तकनीकी और साइबर सुरक्षा प्रणालियों में सुधार के बाद इसकी आवश्यकता समाप्त होने के कारण

D) Because the platform was merged with RBI systems / प्लेटफॉर्म को RBI सिस्टम में विलय करने के कारण

E) Due to lack of government approval / सरकारी स्वीकृति के अभाव में

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) discontinued the Investor Risk Reduction Access (IRRA) platform with immediate effect.

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Investor Risk Reduction Access (IRRA) प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया।

• The IRRA platform was launched on 1 October 2023.

• IRRA प्लेटफॉर्म को 1 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था।

• It was designed to provide stock brokers with an alternative trading access point during disruptions in trading services.

• इसे ट्रेडिंग सेवाओं में बाधा आने की स्थिति में स्टॉक ब्रोकरों को वैकल्पिक ट्रेडिंग एक्सेस प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था।

• SEBI stated that the platform became structurally redundant because of major improvements in business continuity systems and cyber resilience mechanisms.

• SEBI के अनुसार, बिजनेस कंटिन्यूटी सिस्टम और साइबर रेजिलिएंस तंत्र में बड़े सुधारों के कारण यह प्लेटफॉर्म संरचनात्मक रूप से अनावश्यक हो गया था।
• The securities market has also witnessed significant advancements in technological infrastructure.
• प्रतिभूति बाजार में तकनीकी अवसंरचना में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
• SEBI noted that no stock broker had used the IRRA platform since its launch.
• SEBI ने बताया कि लॉन्च के बाद से किसी भी स्टॉक ब्रोकर ने IRRA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया।
• Due to its non-usage and redundancy, SEBI decided to discontinue the facility.
• इसके उपयोग न होने और अनावश्यक हो जाने के कारण SEBI ने इस सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया।

Ques: Which international organisation approved a USD 500 million loan for the Bihar Urban Transformation Programme?
प्रश्न: बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने स्वीकृत किया?

A) World Bank / विश्व बैंक
B) International Monetary Fund / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
C) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
D) Asian Infrastructure Investment Bank / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
E) New Development Bank / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The World Bank approved a USD 500 million (approximately ₹4,750 crore) loan for Bihar.
• विश्व बैंक ने बिहार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4,750 करोड़) का

ऋण स्वीकृत किया।

• The financial assistance has been provided for the Bihar Urban Transformation Programme.

• यह वित्तीय सहायता बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए प्रदान की गई है।

• The programme aims to improve urban infrastructure and planned urban development in Bihar.

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार में शहरी अवसंरचना और योजनाबद्ध शहरी विकास को मजबूत करना है।

• The Cabinet also approved the transfer of 1.85 acres of land for developmental purposes related to the expansion of Patna airport.

• कैबिनेट ने पटना एयरपोर्ट के विस्तार से संबंधित विकास कार्यों हेतु 1.85 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी।

• Additionally, ₹15,967.03 crore was sanctioned for road monitoring and maintenance projects using Artificial Intelligence (AI)-based technologies.

• इसके अतिरिक्त, Artificial Intelligence (AI) आधारित तकनीकों से सड़क निगरानी और रखरखाव परियोजनाओं के लिए ₹15,967.03 करोड़ की मंजूरी दी गई।

• The AI-based system is expected to improve road quality monitoring and maintenance efficiency.

• AI आधारित प्रणाली से सड़क गुणवत्ता निगरानी और रखरखाव की दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• World Bank Established – 1944

• विश्व बैंक की स्थापना – 1944

• World Bank Headquarters – Washington, D.C., USA

• विश्व बैंक का मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका

• World Bank President – Ajay Banga

• विश्व बैंक के अध्यक्ष – अजय बंगा

• Bihar Capital – Patna

• बिहार की राजधानी – पटना

Ques: The Government has revised the release date of annual GDP and Q4 estimates to which date every year?

प्रश्न: सरकार ने वार्षिक GDP और Q4 अनुमानों की जारी तिथि हर वर्ष किस दिन निर्धारित की है?

A) 31 May / 31 मई

B) 1 June / 1 जून

C) 5 June / 5 जून

D) 7 June / 7 जून

E) 10 June / 10 जून

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has revised the release date of the Provisional Estimates of Annual GDP and Q4 GDP estimates.

• भारत सरकार ने वार्षिक GDP के प्रोविजनल अनुमान और Q4 GDP आंकड़ों की जारी तिथि में बदलाव किया है।

• The data will now be released on 7 June every year.

• अब ये आंकड़े हर वर्ष 7 जून को जारी किए जाएंगे।

• Earlier, the estimates were released on the last working day of May.

• पहले ये अनुमान मई के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किए जाते थे।

• If 7 June falls on a holiday, the data will be released on the previous working day.

• यदि 7 जून को अवकाश होगा, तो आंकड़े पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे।

• The revision aims to improve the accuracy and quality of GDP estimation.

• इस बदलाव का उद्देश्य GDP अनुमानों की सटीकता और गुणवत्ता में सुधार करना है।

• GDP data is released by the National Statistical Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).

• GDP आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए जाते हैं, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।

• The revised schedule is expected to improve the compilation and analysis process of economic data.
• संशोधित समय-सारणी से आर्थिक आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण प्रक्रिया में सुधार होने की उम्मीद है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• GDP Full Form – Gross Domestic Product
• GDP का पूर्ण रूप – ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
• NSO Full Form – National Statistical Office
• NSO का पूर्ण रूप – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
• MoSPI Full Form – Ministry of Statistics and Programme Implementation
• MoSPI का पूर्ण रूप – सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
• New GDP Release Date – 7 June
• नई GDP जारी तिथि – 7 जून

Ques: What was India's retail inflation rate in April 2026, according to the Ministry of Statistics and Programme Implementation?
प्रश्न: Ministry of Statistics and Programme Implementation के अनुसार अप्रैल 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) दर क्या थी?

A) 2.98%
B) 3.12%
C) 3.48%
D) 4.05%
E) 5.10%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's retail inflation increased to 3.48% in April 2026 on an annual basis.
• भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2026 में वार्षिक आधार पर बढ़कर 3.48% हो गई।

• The data was released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).

• यह आंकड़े Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) द्वारा जारी किए गए।

• This was the fourth consecutive monthly rise under the new inflation series.

• यह नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के तहत लगातार चौथा मासिक बढ़ोतरी का मामला था।

• Retail inflation in India is measured using the Consumer Price Index (CPI).

• भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को Consumer Price Index (CPI) के आधार पर मापा जाता है।

• Retail inflation reflects the increase in prices of goods and services commonly used by consumers.

• खुदरा मुद्रास्फीति उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है जिनका सामान्य उपभोक्ता उपयोग करता है।

Ques: Sarvodaya Co-operative Bank depositors will receive insurance claim up to how much amount from DICGC?

प्रश्न: सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को DICGC से अधिकतम कितनी बीमा राशि मिलेगी?

A) ₹1 Lakh / ₹1 लाख

B) ₹2 Lakh / ₹2 लाख

C) ₹3 Lakh / ₹3 लाख

D) ₹5 Lakh / ₹5 लाख

E) ₹10 Lakh / ₹10 लाख

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) cancelled the licence of Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Mumbai on 12 May 2026.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 मई 2026 को सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया।

• RBI cited inadequate capital, weak earning prospects, and non-compliance with provisions of the Banking Regulation Act, 1949 as the main reasons.

• आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी, कमजोर आय संभावनाएं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन को मुख्य कारण बताया।

• The bank ceased all banking operations from the close of business on 12 May 2026, including acceptance and repayment of deposits.

• बैंक ने 12 मई 2026 के कारोबार बंद होने के बाद सभी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दीं, जिसमें जमा स्वीकार करना और भुगतान करना शामिल है।

• RBI directed the Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra to initiate the winding-up process and appoint a liquidator.

• आरबीआई ने महाराष्ट्र के कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैंक के परिसमापन (winding-up) की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

• Depositors will get deposit insurance of up to ₹5 lakh from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).

• जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत ₹5 लाख तक का जमा बीमा मिलेगा।

• About 98.36% depositors are eligible to receive the full amount of their insured deposits.

• लगभग 98.36% जमाकर्ता अपनी पूरी बीमित राशि पाने के पात्र हैं।

• As of 31 March 2026, DICGC had already paid ₹26.72 crore toward insured deposits.

• 31 मार्च 2026 तक DICGC ने ₹26.72 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया था।

• The cancellation reflects RBI's focus on protecting depositors and maintaining stability in the banking sector.

• यह कार्रवाई जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के RBI के प्रयासों को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Establishment – 1 April 1935

- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई
- DICGC Establishment – 15 July 1978
- DICGC की स्थापना – 15 जुलाई 1978
- DICGC Headquarters – Mumbai
- DICGC मुख्यालय – मुंबई
- Deposit Insurance Limit – ₹5 Lakh
- जमा बीमा सीमा – ₹5 लाख

Ques: How much does the Export-Import Bank of India (EXIM Bank) plan to raise in fiscal year 2026–27 through domestic and overseas borrowing?

प्रश्न: Export-Import Bank of India (EXIM Bank) वित्त वर्ष 2026–27 में घरेलू और विदेशी उधारी के माध्यम से कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है?

A) ₹99,500 crore
B) ₹82,500 crore
C) ₹75,000 crore
D) ₹1,25,000 crore
E) ₹66,000 crore

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Export-Import Bank of India (EXIM Bank) plans to raise about ₹99,500 crore (995 billion rupees or USD 10.5 billion) during fiscal year 2026–27.
- Export-Import Bank of India (EXIM Bank) वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान लगभग ₹99,500 करोड़ (995 बिलियन रुपये या USD 10.5 बिलियन) जुटाने की योजना बना रहा है।
- Around ₹66,000 crore will be raised from the domestic market.

• लगभग ₹66,000 करोड़ घरेलू बाजार से जुटाए जाएंगे।
• Domestic borrowing sources include bonds, Certificates of Deposit (CDs), and loans.
• घरेलू उधारी के स्रोतों में बॉन्ड, Certificates of Deposit (CDs) और ऋण शामिल हैं।
• The bank also plans to raise around USD 3.5 billion from overseas markets.
• बैंक विदेशी बाजारों से लगभग USD 3.5 बिलियन जुटाने की भी योजना बना रहा है।
• Overseas borrowing will be done through bilateral loans and syndicated loans.
• विदेशी उधारी द्विपक्षीय ऋण और सिंडिकेटेड ऋण के माध्यम से की जाएगी।
• EXIM Bank plays an important role in supporting India's international trade and export financing.
• EXIM Bank भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात वित्तपोषण को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• EXIM Bank Full Form – Export-Import Bank of India
• EXIM Bank का पूर्ण रूप – एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया
• EXIM Bank Established – 1982
• EXIM Bank की स्थापना – 1982
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Fiscal Year Target Borrowing – ₹99,500 crore
• वित्त वर्ष लक्ष्य उधारी – ₹99,500 करोड़
• Domestic Borrowing Target – Around ₹66,000 crore
• घरेलू उधारी लक्ष्य – लगभग ₹66,000 करोड़
• Overseas Borrowing Target – Around USD 3.5 billion
• विदेशी उधारी लक्ष्य – लगभग USD 3.5 बिलियन

Ques: SBI plans to raise up to US$ 2 billion in FY27 through which financial instrument?

प्रश्न: SBI वित्त वर्ष 2026-27 में 2 अरब डॉलर तक किस वित्तीय साधन के माध्यम से जुटाएगा?

A) Equity Shares / इक्विटी शेयर

B) Mutual Funds / म्यूचुअल फंड

C) Foreign Currency Bonds / विदेशी मुद्रा बॉन्ड

D) Treasury Bills / ट्रेजरी बिल

E) Commercial Papers / कमर्शियल पेपर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• State Bank of India Executive Committee of the Central Board approved a proposal to raise up to US$ 2 Billion during FY 2026-27.

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने वित्त वर्ष 2026-27 में 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• The fund will be raised through long-term foreign currency bonds in one or more tranches.

• यह फंड लॉन्ग-टर्म विदेशी मुद्रा बॉन्ड्स के माध्यम से एक या अधिक चरणों में जुटाया जाएगा।

• The approximate value of this fundraising in Indian currency is around ₹16,700 crore.

• भारतीय मुद्रा में इस फंड जुटाने का अनुमानित मूल्य लगभग ₹16,700 करोड़ है।

• SBI may issue these bonds through public offer or private placement.

• SBI इन बॉन्ड्स को पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी कर सकता है।

• The bonds may be issued in US Dollars or other major foreign currencies.

• ये बॉन्ड अमेरिकी डॉलर या अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं में जारी किए जा सकते हैं।

• The bonds may carry either fixed interest rate or floating interest rate.

• इन बॉन्ड्स पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग ब्याज दर लागू हो सकती है।

• The move will help SBI strengthen its global funding base and long-term capital resources.

• यह कदम SBI को अपनी वैश्विक फंडिंग क्षमता और दीर्घकालिक पूंजी आधार मजबूत करने में मदद करेगा।

• The fundraising plan reflects SBI's strategy to expand its international

financial presence.

• यह फंड जुटाने की योजना SBI की वैश्विक वित्तीय उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SBI Establishment – 1 July 1955
• SBI की स्थापना – 1 जुलाई 1955
• SBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• SBI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Chairman of SBI – C. S. Setty
• SBI के चेयरमैन – सी. एस. सेटी
• Parent Institution – Reserve Bank of India (Initially)
• मूल संस्था – रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (प्रारंभिक)
• Tagline of SBI – "The Banker to Every Indian"
• SBI का टैगलाइन – "द बैंकर्स टू एवरी इंडियन"

Ques: Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) signed an MoU with which organisation to fight cyber frauds and stop mule accounts?

प्रश्न: Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने साइबर धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट रोकने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

A) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

B) Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) / रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

C) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

D) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक

E) National Informatics Centre (NIC) / राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) signed an MoU with Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) to combat cyber frauds and stop mule accounts in banking and digital payment systems.

• Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर धोखाधड़ी तथा म्यूल अकाउंट रोकने के लिए Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।

• A mule account is a bank account used to receive and transfer illegal money on behalf of others to hide the original source of funds.

• म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता होता है जिसका उपयोग अवैध धन को प्राप्त और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि धन के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके।

• Under the partnership, information related to suspicious accounts will be shared between the organisations.

• इस साझेदारी के तहत संदिग्ध खातों से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी।

• AI-based systems will be used to detect fraud quickly and identify hidden mule accounts.

• धोखाधड़ी का तेजी से पता लगाने और छिपे हुए म्यूल अकाउंट की पहचान करने के लिए AI-आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा।

• Hidden mule accounts will be blocked faster through the collaboration.

• इस सहयोग के माध्यम से छिपे हुए म्यूल अकाउंट को तेजी से ब्लॉक किया जाएगा।

• RBIH has developed platforms such as Unified Lending Interface (ULI), MuleHunter.AI, Digital Payments Intelligence Platform (DPIP), and RBI Fintech Repository.

• RBIH ने Unified Lending Interface (ULI), MuleHunter.AI, Digital Payments Intelligence Platform (DPIP) और RBI Fintech Repository जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं।

• I4C is a government initiative operating under the Ministry of Home Affairs to deal with cybercrime in India.

• I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने

वाली सरकारी पहल है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBIH Full Form – Reserve Bank Innovation Hub
- RBIH का पूर्ण रूप – रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
- RBIH Established – 2022
- RBIH की स्थापना – 2022
- RBIH Headquarters – Bengaluru, Karnataka
- RBIH मुख्यालय – बेंगलुरु, कर्नाटक
- I4C Full Form – Indian Cyber Crime Coordination Centre
- I4C का पूर्ण रूप – इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर
- I4C Launched – January 2018
- I4C की शुरुआत – जनवरी 2018
- I4C Ministry – Ministry of Home Affairs (MHA)
- I4C मंत्रालय – गृह मंत्रालय (MHA)
- I4C Location – New Delhi
- I4C स्थान – नई दिल्ली

Ques: ICICI Bank launched India's first dollar-denominated debit card in partnership with which company?

प्रश्न: ICICI Bank ने भारत का पहला डॉलर-डिनॉमिनेटेड डेबिट कार्ड किस कंपनी के साथ साझेदारी में लॉन्च किया?

A) Mastercard / मास्टरकार्ड

B) RuPay / रुपे

C) Visa / वीज़ा

D) American Express / अमेरिकन एक्सप्रेस

E) PayPal / पेपाल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• ICICI Bank, in partnership with Visa, launched India's first dollar-denominated debit card.

• ICICI Bank ने Visa के साथ साझेदारी में भारत का पहला डॉलर-डिनॉमिनेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया।

• The debit card has been launched from ICICI Bank's IFSC Banking Unit (IBU) at GIFT City.

• यह डेबिट कार्ड ICICI Bank की IFSC Banking Unit (IBU), GIFT City से लॉन्च किया गया है।

• The initiative aims to provide innovative global banking solutions to NRI customers.

• इस पहल का उद्देश्य NRI ग्राहकों को अभिनव वैश्विक बैंकिंग समाधान प्रदान करना है।

• Dollar-denominated cards help customers make international transactions directly in US dollars.

• डॉलर-डिनॉमिनेटेड कार्ड ग्राहकों को सीधे अमेरिकी डॉलर में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने में सहायता करते हैं।

• The card is specially designed to facilitate seamless overseas payments and banking convenience.

• यह कार्ड विदेशी भुगतान और वैश्विक बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।

• GIFT City serves as India's international financial services hub.

• GIFT City भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• ICICI Bank Founded – 1994

• ICICI Bank की स्थापना – 1994

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• MD & CEO – Sandeep Bakhshi

• एमडी एवं सीईओ – संदीप बख्शी
• Visa Headquarters – California, USA
• Visa मुख्यालय – कैलिफोर्निया, अमेरिका
• GIFT Full Form – Gujarat International Finance Tec-City
• GIFT का पूर्ण रूप – गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
• GIFT City Location – Gandhinagar, Gujarat
• GIFT City का स्थान – गांधीनगर, गुजरात

Ques: What was the all-time high net profit recorded by Public Sector Banks (PSBs) during Financial Year 2025–26?

प्रश्न: वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान Public Sector Banks (PSBs) द्वारा दर्ज किया गया सर्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ कितना था?

A) ₹1.25 lakh crore / ₹1.25 लाख करोड़
B) ₹1.50 lakh crore / ₹1.50 लाख करोड़
C) ₹1.75 lakh crore / ₹1.75 लाख करोड़
D) ₹1.98 lakh crore / ₹1.98 लाख करोड़
E) ₹2.25 lakh crore / ₹2.25 लाख करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to the Ministry of Finance, Public Sector Banks (PSBs) recorded an all-time high net profit of ₹1.98 lakh crore during Financial Year 2025–26.
• वित्त मंत्रालय के अनुसार, Public Sector Banks (PSBs) ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹1.98 लाख करोड़ का सर्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ दर्ज किया।
• This marked the fourth consecutive year of profitability for PSBs.
• यह PSBs के लगातार चौथे वर्ष के लाभ में रहने को दर्शाता है।
• Asset quality improved significantly, with Gross NPA ratio declining to 1.93% and Net NPA ratio dropping to 0.39% as of 31 March 2026.

• परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें Gross NPA अनुपात घटकर 1.93% और Net NPA अनुपात घटकर 0.39% हो गया।

• PSBs registered their lowest-ever NPA levels.

• PSBs ने अब तक का सबसे कम NPA स्तर दर्ज किया।

• Total business of PSBs reached ₹283.3 lakh crore in FY 2025–26, showing a robust year-on-year growth of 12.8%.

• FY 2025–26 में PSBs का कुल व्यवसाय ₹283.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 12.8% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

• Aggregate deposits increased by 10.6% year-on-year to ₹156.3 lakh crore.

• कुल जमा राशि 10.6% बढ़कर ₹156.3 लाख करोड़ हो गई।

• Gross advances grew by 15.7% to ₹127 lakh crore with strong performance in Retail, Agriculture and MSME sectors.

• सकल अग्रिम 15.7% बढ़कर ₹127 लाख करोड़ हो गया, जिसमें Retail, Agriculture और MSME क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

• Retail advances grew by 18.1%, Agriculture advances by 15.5%, and MSME advances by 18.2%.

• Retail अग्रिम 18.1%, Agriculture अग्रिम 15.5% और MSME अग्रिम 18.2% बढ़े।

• The aggregate Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) improved to 16.6%.

• कुल Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) बढ़कर 16.6% हो गया।

• PSBs raised ₹50,551 crore capital during FY 2025–26.

• PSBs ने FY 2025–26 के दौरान ₹50,551 करोड़ की पूंजी जुटाई।

• Operational efficiency also improved, with the cost-to-income ratio improving to 49.67%.

• परिचालन दक्षता में भी सुधार हुआ और cost-to-income ratio घटकर 49.67% हो गया।

• Aggregate operating profit reached ₹3.21 lakh crore.

• कुल परिचालन लाभ ₹3.21 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Sector – Public Sector Banks (PSBs)

• क्षेत्र – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)

• Net Profit (FY 2025–26) – ₹1.98 lakh crore

- शुद्ध लाभ (FY 2025–26) – ₹1.98 लाख करोड़
- Gross NPA Ratio – 1.93%
- सकल NPA अनुपात – 1.93%
- Net NPA Ratio – 0.39%
- शुद्ध NPA अनुपात – 0.39%
- Total Business – ₹283.3 lakh crore
- कुल व्यवसाय – ₹283.3 लाख करोड़
- Aggregate Deposits – ₹156.3 lakh crore
- कुल जमा – ₹156.3 लाख करोड़
- Gross Advances – ₹127 lakh crore
- सकल अग्रिम – ₹127 लाख करोड़
- CRAR – 16.6%
- CRAR – 16.6%
- Aggregate Operating Profit – ₹3.21 lakh crore
- कुल परिचालन लाभ – ₹3.21 लाख करोड़

Ques: What is the name of SEBI's proposed green-channel framework for fast-tracking AIF scheme approvals?

प्रश्न: AIF योजनाओं की त्वरित मंजूरी के लिए सेबी द्वारा प्रस्तावित ग्रीन-चैनल फ्रेमवर्क का नाम क्या है?

A) VAYU / वायु

B) GARUDA / गरुड़

C) PRAGATI / प्रगति

D) UDAAN / उड़ान

E) SHAKTI / शक्ति

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has proposed a new “green-channel” framework named GARUDA for quicker launch of AIF schemes.

• सेबी ने AIF योजनाओं की तेज शुरुआत के लिए GARUDA नामक नया “ग्रीन-चैनल” फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है।

• GARUDA stands for Green-Channel: AIF Rollout Upon Document Acknowledgement.

• GARUDA का पूर्ण रूप Green-Channel: AIF Rollout Upon Document Acknowledgement है।

• Under the new framework, AIF schemes can be launched within 10 working days after filing documents with SEBI.

• नए फ्रेमवर्क के तहत AIF योजनाएं सेबी में दस्तावेज जमा करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर शुरू की जा सकेंगी।

• Earlier, the approval timeline for launching such schemes was 30 days.

• पहले ऐसी योजनाओं की मंजूरी की समय-सीमा 30 दिन थी।

• The proposal aims to enable faster capital deployment and ease compliance requirements.

• इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूंजी की तेज तैनाती और अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाना है।

• SEBI also proposed a lighter compliance regime for accredited investor-only schemes and angel funds.

• सेबी ने मान्यता प्राप्त निवेशक योजनाओं और एंजेल फंड्स के लिए हल्के अनुपालन ढांचे का भी प्रस्ताव दिया है।

• Managers of such funds may directly file placement memorandums with SEBI without merchant bankers.

• ऐसे फंड्स के प्रबंधक मर्चेंट बैंकरों के बिना सीधे सेबी में प्लेसमेंट मेमोरेंडम दाखिल कर सकेंगे।

• The initiative is aimed at simplifying procedures and accelerating fund launches in India’s investment ecosystem.

• यह पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भारत के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में फंड लॉन्च को तेज करने के उद्देश्य से लाई गई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SEBI Establishment Year – 12 April 1988

• सेबी स्थापना वर्ष – 12 अप्रैल 1988
• SEBI Headquarters – Mumbai
• सेबी मुख्यालय – मुंबई
• SEBI Chairman – Tuhin Kanta Pandey
• सेबी अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय
• AIF Full Form – Alternative Investment Fund
• AIF का पूर्ण रूप – अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड
• Earlier Approval Timeline – 30 Days
• पूर्व मंजूरी समय-सीमा – 30 दिन
• New Proposed Timeline Under GARUDA – 10 Working Days
• GARUDA के तहत नई प्रस्तावित समय-सीमा – 10 कार्य दिवस

Ques: How much total financial commitment did the Asian Development Bank (ADB) make to India in 2025?

प्रश्न: Asian Development Bank (ADB) ने वर्ष 2025 में भारत के लिए कुल कितनी वित्तीय प्रतिबद्धता की?

A) USD 2 billion
B) USD 3.5 billion
C) USD 4 billion
D) More than USD 5 billion
E) USD 7 billion

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Asian Development Bank (ADB) strengthened its partnership with India in 2025 by committing more than USD 5 billion.
• Asian Development Bank (ADB) ने 2025 में भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धता की।
• The commitment included both sovereign financing and private sector financing.

• इस प्रतिबद्धता में sovereign financing और private sector financing दोनों शामिल थे।

• According to ADB, USD 4.238 billion was committed for sovereign lending operations.

• ADB के अनुसार, sovereign lending operations के लिए USD 4.238 billion की प्रतिबद्धता की गई।

• An additional USD 1.06 billion was committed for private sector operations.

• private sector operations के लिए अतिरिक्त USD 1.06 billion की प्रतिबद्धता की गई।

• The funding aims to support India's infrastructure, development and economic growth initiatives.

• यह वित्तीय सहायता भारत के बुनियादी ढांचे, विकास और आर्थिक वृद्धि से संबंधित पहलों को समर्थन देने के लिए है।

• India and ADB will complete 40 years of partnership in 2026.

• भारत और ADB वर्ष 2026 में अपनी साझेदारी के 40 वर्ष पूरे करेंगे।

Ques: What delay has RBI proposed for digital payments above ₹10,000 to curb fraud?

प्रश्न: धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI ने ₹10,000 से अधिक के डिजिटल भुगतान पर कितनी देरी का प्रस्ताव दिया है?

A) 15 Minutes / 15 मिनट

B) 30 Minutes / 30 मिनट

C) 1 Hour / 1 घंटा

D) 2 Hours / 2 घंटे

E) 24 Hours / 24 घंटे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Indian banks broadly supported RBI's proposal to introduce a one-hour delay for UPI/IMPS account-to-account transfers above ₹10,000 to reduce rising digital payment frauds.

• भारतीय बैंकों ने बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकने के लिए ₹10,000 से अधिक के UPI/IMPS ट्रांसफर पर 1 घंटे की देरी के RBI प्रस्ताव का व्यापक समर्थन किया।

• Banks have requested RBI to increase the threshold limit from ₹10,000 to ₹25,000 for smoother implementation and reduced operational burden.

• बैंकों ने आसान कार्यान्वयन और कम परिचालन बोझ के लिए सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का अनुरोध किया है।

• The proposal aims to provide customers a one-hour window to identify and cancel potentially fraudulent person-to-person (P2P) transactions.

• इस प्रस्ताव का उद्देश्य ग्राहकों को संभावित धोखाधड़ी वाले व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन को पहचानने और रद्द करने के लिए 1 घंटे का समय देना है।

• RBI's discussion paper also suggested stronger authentication checks and enhanced safeguards for high-risk transactions.

• RBI के चर्चा पत्र में उच्च-जोखिम वाले लेनदेन के लिए मजबूत प्रमाणीकरण और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का भी सुझाव दिया गया है।

• The proposal mainly targets UPI and IMPS-based account-to-account digital transfers.

• यह प्रस्ताव मुख्य रूप से UPI और IMPS आधारित अकाउंट-टू-अकाउंट डिजिटल ट्रांसफर पर केंद्रित है।

• The measure is aimed at improving customer protection and reducing cyber fraud risks in digital banking.

• यह कदम डिजिटल बैंकिंग में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

• Banks supported the proposal in principle but highlighted the need for practical operational flexibility.

• बैंकों ने सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन व्यावहारिक परिचालन लचीलापन की आवश्यकता पर जोर दिया।

• The delay mechanism is expected to help customers react quickly in case of suspicious or mistaken transfers.

• यह देरी प्रणाली संदिग्ध या गलत ट्रांसफर की स्थिति में ग्राहकों को तुरंत प्रतिक्रिया

देने में मदद करेगी।

Ques: How much amount was raised by the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) through 10-year bonds?

प्रश्न: National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) ने 10-वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाई?

A) ₹2,000 crore
B) ₹3,500 crore
C) ₹4,000 crore
D) ₹5,000 crore
E) ₹7,740 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) raised ₹4,000 crore through 10-year bonds.

• National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) ने 10-वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से ₹4,000 करोड़ जुटाए।

• The bonds were issued at a cutoff yield of 7.74%.

• ये बॉन्ड 7.74% की cutoff yield पर जारी किए गए।

• Bonds are debt instruments through which organisations borrow money from investors.

• बॉन्ड ऐसे debt instruments होते हैं जिनके माध्यम से संस्थाएं निवेशकों से धन उधार लेती हैं।

• When investors buy bonds, they lend money to the issuer and receive fixed interest in return.

• जब निवेशक बॉन्ड खरीदते हैं, तो वे जारीकर्ता को धन उधार देते हैं और बदले में निश्चित ब्याज प्राप्त करते हैं।

• NaBFID is a government-backed Development Finance Institution (DFI).

• NaBFID एक सरकार समर्थित Development Finance Institution (DFI) है।
• It focuses on financing infrastructure projects in India.
• यह भारत में infrastructure projects के वित्तपोषण पर केंद्रित है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Institution – National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID)
• संस्था – National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID)
• Amount Raised – ₹4,000 crore
• जुटाई गई राशि – ₹4,000 करोड़
• Bond Tenure – 10 years
• बॉन्ड अवधि – 10 वर्ष
• Cutoff Yield – 7.74%
• कटऑफ यील्ड – 7.74%

Ques: Which committee chaired by the RBI Governor reviewed global trade and financial stability developments in 2026?

प्रश्न: RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली किस समिति ने 2026 में वैश्विक व्यापार और वित्तीय स्थिरता से जुड़े विकासों की समीक्षा की?

A) Monetary Policy Committee (MPC) / मौद्रिक नीति समिति
B) Financial Stability and Development Council – Sub Committee (FSDC-SC) / फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल – उप समिति
C) Board for Financial Supervision (BFS) / वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
D) Central Board of RBI / RBI का केंद्रीय बोर्ड
E) Economic Advisory Council / आर्थिक सलाहकार परिषद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The 33rd meeting of the Financial Stability and Development Council – Sub Committee (FSDC-SC) was held in Mumbai.

• Financial Stability and Development Council – Sub Committee (FSDC-SC) की 33वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई।

• The meeting was chaired by RBI Governor Sanjay Malhotra.

• बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।

• The committee reviewed global and domestic macroeconomic and financial sector developments.

• समिति ने वैश्विक और घरेलू व्यापक आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास की समीक्षा की।

• Members discussed emerging risks affecting financial stability, including geopolitical tensions and global trade uncertainties.

• सदस्यों ने वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले उभरते जोखिमों, जैसे भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं, पर चर्चा की।

• The FSDC-SC decided to closely monitor evolving global trade conditions and their impact on India's financial system.

• FSDC-SC ने बदलती वैश्विक व्यापार परिस्थितियों और उनके भारत की वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव की करीबी निगरानी करने का निर्णय लिया।

• The meeting also reviewed progress in inter-regulatory coordination and simplification of KYC processes.

• बैठक में अंतर-नियामक समन्वय और KYC प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

• The committee emphasized strengthening financial sector resilience through better regulatory coordination.

• समिति ने बेहतर नियामकीय समन्वय के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की मजबूती पर जोर दिया।

• Senior officials from SEBI, IRDAI, PFRDA and IFSCA participated in the meeting.

• बैठक में SEBI, IRDAI, PFRDA और IFSCA के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

• The meeting highlighted concerns over supply-chain disruptions, commodity price volatility and global spillover risks.

• बैठक में सप्लाई-चेन व्यवधान, कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक प्रभावों

से जुड़े जोखिमों पर चिंता व्यक्त की गई।

• The discussion focused on maintaining financial stability amid uncertain international economic conditions.

• चर्चा का मुख्य उद्देश्य अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखना था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Full Form – Financial Stability and Development Council – Sub Committee (FSDC-SC)

• पूर्ण रूप – Financial Stability and Development Council – Sub Committee (FSDC-SC)

• Chairperson – RBI Governor Sanjay Malhotra

• अध्यक्ष – RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा

• Meeting Number – 33rd Meeting

• बैठक संख्या – 33वीं बैठक

• Venue – Mumbai

• स्थान – मुंबई

• Main Objective – Maintain financial stability and strengthen inter-regulatory coordination

• मुख्य उद्देश्य – वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और अंतर-नियामक समन्वय मजबूत करना

• Key Focus Areas – Global trade risks, macroeconomic conditions, KYC reforms, financial resilience

• प्रमुख फोकस क्षेत्र – वैश्विक व्यापार जोखिम, व्यापक आर्थिक स्थिति, KYC सुधार, वित्तीय मजबूती

• RBI Headquarters – Mumbai

• RBI मुख्यालय – मुंबई

• RBI Established – 1 April 1935

• RBI स्थापना – 1 अप्रैल 1935

Ques: Which credit card launched by AU Small Finance Bank is specially designed for first-time credit users?

प्रश्न: AU Small Finance Bank द्वारा लॉन्च किया गया कौन-सा क्रेडिट कार्ड पहली बार क्रेडिट उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है?

A) AU Ananta / एयू अनंता

B) AU Laksya / एयू लक्ष्य

C) AU Tejas / एयू तेजस

D) AU Prathama / एयू प्रथम

E) AU Aspire / एयू एस्पायर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• AU Small Finance Bank launched a new portfolio of four credit cards to strengthen its retail credit card business.

• AU Small Finance Bank ने अपने retail credit card business को मजबूत करने के लिए चार नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए।

• The four newly launched credit cards are AU Ananta, AU Laksya, AU Tejas and AU Prathama.

• लॉन्च किए गए चार नए क्रेडिट कार्ड हैं — AU Ananta, AU Laksya, AU Tejas और AU Prathama।

• AU Prathama is specially designed for first-time credit users.

• AU Prathama विशेष रूप से पहली बार क्रेडिट उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए बनाया गया है।

• It provides reward points, milestone incentives, fuel surcharge waivers and responsible credit usage benefits.

• यह reward points, milestone incentives, fuel surcharge waiver और responsible credit usage benefits प्रदान करता है।

• AU Ananta is targeted at affluent achievers and offers premium travel and lifestyle benefits.

• AU Ananta affluent achievers के लिए बनाया गया है और premium travel एवं

lifestyle benefits प्रदान करता है।

• AU Laksya is designed for Gen Z and mid-career professionals with grocery, food delivery and movie benefits.

• AU Laksya Gen Z और mid-career professionals के लिए बनाया गया है, जिसमें grocery, food delivery और movie benefits दिए जाते हैं।

• AU Tejas targets young salaried customers and offers cashback on daily spending categories.

• AU Tejas युवा salaried customers के लिए है और दैनिक खर्चों पर cashback प्रदान करता है।

• The cards are aimed at customers across different income and lifestyle segments in Tier-1 and Tier-2 cities.

• ये कार्ड Tier-1 और Tier-2 शहरों के विभिन्न income और lifestyle segments के ग्राहकों को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bank Name – AU Small Finance Bank
• बैंक का नाम – AU Small Finance Bank
• Established – 2017
• स्थापना – 2017
• Headquarters – Jaipur, Rajasthan
• मुख्यालय – जयपुर, राजस्थान
• CEO & MD – Sanjay Agarwal
• CEO एवं MD – संजय अग्रवाल
• Tagline – “Badlaav Humse Hai”
• टैगलाइन – “Badlaav Humse Hai”
• Credit Cards Launched – AU Ananta, AU Laksya, AU Tejas, AU Prathama
• लॉन्च किए गए क्रेडिट कार्ड – AU Ananta, AU Laksya, AU Tejas, AU Prathama
• Card for First-Time Users – AU Prathama
• पहली बार क्रेडिट उपयोगकर्ताओं के लिए कार्ड – AU Prathama

Ques: The Government recently increased customs duty on gold and silver imports from 5% to what percentage?

प्रश्न: सरकार ने हाल ही में सोना और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया?

A) 6%
B) 8%
C) 10%
D) 12%
E) 15%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government increased the customs duty on imports of gold and silver from 5% to 10%.

• केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया।

• The Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) was also increased from 1% to 5%.

• कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC) को भी 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया।

• With the hike, the total effective import duty on gold and silver has increased to around 18.4% including IGST.

• इस वृद्धि के बाद सोना और चांदी पर कुल प्रभावी आयात शुल्क IGST सहित लगभग 18.4% हो गया है।

• Earlier, the effective import tax was around 9.2%.

• इससे पहले प्रभावी आयात कर लगभग 9.2% था।

• The decision was taken to protect India's foreign exchange reserves amid rising global geopolitical tensions.

• यह निर्णय बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए लिया गया।

• The government cited concerns over the impact of the West Asia crisis on India's Current Account Deficit (CAD).

• सरकार ने भारत के चालू खाता घाटे (CAD) पर पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को

लेकर चिंता जताई।

• Prime Minister Narendra Modi had earlier appealed to citizens to reduce gold purchases to conserve foreign exchange.

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विदेशी मुद्रा बचाने के लिए नागरिकों से सोने की खरीद कम करने की अपील की थी।

• Experts believe the move may encourage gold smuggling and affect employment in related sectors.

• विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सोने की तस्करी को बढ़ावा दे सकता है और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार को प्रभावित कर सकता है।

• The revised duty structure came into effect through two separate government notifications.

• संशोधित शुल्क व्यवस्था दो अलग-अलग सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू हुई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• CAD Full Form – Current Account Deficit
• CAD का पूर्ण रूप – चालू खाता घाटा
• AIDC Full Form – Agriculture Infrastructure and Development Cess
• AIDC का पूर्ण रूप – कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर
• IGST Full Form – Integrated Goods and Services Tax
• IGST का पूर्ण रूप – एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
• Finance Minister – Nirmala Sitharaman
• वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण
• Ministry – Ministry of Finance
• मंत्रालय – वित्त मंत्रालय

Ques: Which foreign bank received approval for a proposed strategic investment in RBL Bank?

प्रश्न: किस विदेशी बैंक को RBL Bank में प्रस्तावित रणनीतिक निवेश के लिए मंजूरी मिली है?

A) HSBC / एचएसबीसी

B) DBS Bank / डीबीएस बैंक

C) Emirates NBD / एमिरेट्स NBD

D) Standard Chartered / स्टैंडर्ड चार्टर्ड

E) Barclays / बार्कलेज

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• RBL Bank received regulatory and government approvals for a proposed strategic investment by Emirates NBD.

• RBL Bank को Emirates NBD द्वारा प्रस्तावित रणनीतिक निवेश के लिए नियामकीय और सरकारी मंजूरी प्राप्त हुई है।

• The proposed investment is valued at nearly 3 billion US dollars.

• प्रस्तावित निवेश का मूल्य लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

• In Indian currency, the investment is estimated at around Rs. 26,850 crore.

• भारतीय मुद्रा में यह निवेश लगभग 26,850 करोड़ रुपये का है।

• Following the transaction, Emirates NBD's final shareholding is expected to range between 51% and 74%.

• इस लेनदेन के बाद Emirates NBD की अंतिम हिस्सेदारी 51% से 74% के बीच रहने की संभावना है।

• The deal reflects growing foreign investment interest in India's banking sector.

• यह सौदा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती विदेशी निवेश रुचि को दर्शाता है।

• Emirates NBD is one of the leading banking groups in the Middle East region.

• Emirates NBD मध्य पूर्व क्षेत्र के प्रमुख बैंकिंग समूहों में से एक है।

• RBL Bank is a prominent private sector bank in India offering retail and corporate banking services.

• RBL Bank भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है जो रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

Ques: Which institution issued a Master Direction on incentives for currency distribution and exchange, along with penalties for deficiencies in customer service and reporting?

प्रश्न: मुद्रा वितरण और विनिमय के लिए प्रोत्साहन तथा ग्राहक सेवा और रिपोर्टिंग में कमियों पर दंड संबंधी मास्टर निर्देश किस संस्था ने जारी किया?

A) SEBI / सेबी

B) NABARD / नाबार्ड

C) RBI / आरबीआई

D) SIDBI / सिडबी

E) IRDAI / इरडाई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) issued a Master Direction on incentives for currency distribution and exchange.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा वितरण और विनिमय के लिए प्रोत्साहन संबंधी मास्टर निर्देश जारी किया।

• The direction also includes penalties for deficiencies in customer service and reporting by bank branches and Currency Chests (CCs).

• इस निर्देश में बैंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट (CCs) द्वारा ग्राहक सेवा और रिपोर्टिंग में कमियों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है।

• A scheme of penal interest and penalties has been introduced to ensure accurate and timely reporting of Currency Chest transactions.

• करेंसी चेस्ट लेन-देन की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक ब्याज और जुर्माने की योजना शुरू की गई है।

• The scheme also aims to improve customer service delivery through banks, branches and ATMs.

• इस योजना का उद्देश्य बैंकों, शाखाओं और ATM के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार लाना भी है।

• These provisions apply to all banks, while Currency Chest-related penalties

apply to banks operating Currency Chests.

• ये प्रावधान सभी बैंकों पर लागू होते हैं, जबकि करेंसी चेस्ट से संबंधित दंड उन बैंकों पर लागू होंगे जो करेंसी चेस्ट संचालित करते हैं।

• Currency Chests are authorised facilities set up by selected scheduled banks to support the distribution of banknotes and coins.

• करेंसी चेस्ट चयनित अनुसूचित बैंकों द्वारा स्थापित अधिकृत सुविधाएँ हैं, जिनका उद्देश्य बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण में सहायता करना है।

• Banks opening Currency Chests in North-Eastern states and remote or hilly regions of Jammu & Kashmir and Ladakh are eligible for 100% capital expenditure reimbursement up to ₹50 lakh.

• पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में करेंसी चेस्ट खोलने वाले बैंक ₹50 लाख तक के 100% पूंजीगत व्यय प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

• Such Currency Chests are also eligible for 50% reimbursement of revenue expenditure for the first five years.

• ऐसे करेंसी चेस्ट पहले पाँच वर्षों तक राजस्व व्यय की 50% प्रतिपूर्ति के भी पात्र होंगे।

• RBI announced ₹2 per packet incentive for exchange of soiled notes of ₹50 and below denomination.

• RBI ने ₹50 और उससे कम मूल्यवर्ग के गंदे नोटों के विनिमय पर ₹2 प्रति पैकेट प्रोत्साहन घोषित किया है।

• An incentive of ₹2 per piece has been fixed for mutilated note adjudication.

• कटे-फटे नोटों के निपटान के लिए ₹2 प्रति नोट प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।

• Banks will receive ₹65 per coin bag for coin distribution.

• सिक्कों के वितरण के लिए बैंकों को ₹65 प्रति कॉइन बैग दिया जाएगा।

• An additional ₹10 per bag incentive is allowed in rural and semi-urban areas certified by auditors.

• ऑडिटर द्वारा प्रमाणित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹10 प्रति बैग अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

• Under the Linkage Scheme with Currency Chests, incentives are ₹11 per 100 pieces for large CCs and ₹8 per 100 pieces for other CCs.

• करेंसी चेस्ट लिंकज योजना के तहत बड़े CCs को ₹11 प्रति 100 पीस तथा अन्य CCs को ₹8 प्रति 100 पीस प्रोत्साहन मिलेगा।

• RBI imposed a penalty of ₹10,000 for any deficiency in exchange-related customer service.

• RBI ने विनिमय संबंधी ग्राहक सेवा में किसी भी कमी पर ₹10,000 का दंड निर्धारित

किया है।

• Examples of deficiency include non-issue of coins over the counter and refusal to accept lower denomination notes.

• कमियों के उदाहरणों में काउंटर पर सिक्के जारी न करना और छोटे मूल्यवर्ग के नोट स्वीकार करने से मना करना शामिल है।

• Refusal to exchange soiled, mutilated or imperfect notes also attracts penalties.

• गंदे, कटे-फटे या अपूर्ण नोटों के विनिमय से इंकार करने पर भी दंड लगाया जाएगा।

• A penalty of ₹5 lakh will be imposed if more than five service deficiencies are found in a branch during a calendar year.

• यदि किसी शाखा में एक कैलेंडर वर्ष में पाँच से अधिक सेवा कमियाँ पाई जाती हैं तो ₹5 लाख का दंड लगाया जाएगा।

• RBI also imposed a penalty of ₹10,000 per instance for counterfeit notes detected in ATM dispensations or over-the-counter disbursement.

• ATM या काउंटर से नकली नोट मिलने पर RBI ने प्रति घटना ₹10,000 का दंड निर्धारित किया है।

• Non-replenishment of ATMs leading to cash-out for more than ten hours in a month will attract a flat penalty of ₹10,000 per ATM.

• किसी ATM में महीने में 10 घंटे से अधिक कैश समाप्त रहने पर प्रति ATM ₹10,000 का दंड लगाया जाएगा।

• Currency Chests must report all transactions through the CyM-CC portal on the same day by 7 PM.

• करेंसी चेस्ट को सभी लेन-देन की रिपोर्ट उसी दिन शाम 7 बजे तक CyM-CC पोर्टल पर देनी होगी।

Ques: According to the latest Periodic Labour Force Survey (PLFS), what was India's overall unemployment rate for persons aged 15 years and above in April 2026?

प्रश्न: नवीनतम Periodic Labour Force Survey (PLFS) के अनुसार अप्रैल 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की कुल बेरोजगारी दर क्या थी?

A) 4.2%
B) 4.8%

C) 5.2%
D) 5.8%
E) 6.6%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's overall unemployment rate for persons aged 15 years and above remained broadly stable at 5.2% in April 2026.

• अप्रैल 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की कुल बेरोजगारी दर 5.2% पर लगभग स्थिर रही।

• The data was released through the Periodic Labour Force Survey (PLFS).

• यह आंकड़े Periodic Labour Force Survey (PLFS) के माध्यम से जारी किए गए।

• The survey data was published by the National Statistical Office (NSO).

• सर्वेक्षण के आंकड़े National Statistical Office (NSO) द्वारा जारी किए गए।

• NSO functions under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).

• NSO, Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।

• In rural areas, the unemployment rate increased to 4.6%.

• ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.6% हो गई।

• In urban areas, unemployment eased marginally to 6.6%.

• शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटकर 6.6% हो गई।

• The PLFS provides key labour market indicators such as employment and unemployment trends across India.

• PLFS भारत में रोजगार और बेरोजगारी की प्रवृत्तियों सहित श्रम बाजार के महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है।

Ques: What was the Foreign Portfolio Investors (FPIs) holding in Indian equities in June 2026, the lowest level in nearly 14 years?

प्रश्न: जून 2026 में भारतीय इक्विटी में Foreign Portfolio Investors (FPIs) की हिस्सेदारी कितनी रही, जो लगभग 14 वर्षों का सबसे निचला स्तर है?

A) 10%
B) 12.5%
C) 14%
D) 18.9%
E) 19.9%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Foreign Portfolio Investors (FPIs) holding in Indian equities declined to 14% in June 2026.

• जून 2026 में भारतीय इक्विटी में Foreign Portfolio Investors (FPIs) की हिस्सेदारी घटकर 14% रह गई।

• This marked the lowest level in nearly 14 years and reflected sustained foreign selling pressure in Indian markets.

• यह लगभग 14 वर्षों का सबसे निचला स्तर था और भारतीय बाजारों में लगातार विदेशी बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।

• Domestic Institutional Investors (DIIs) increased their stake to 18.9%, showing the growing strength of domestic capital.

• Domestic Institutional Investors (DIIs) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 18.9% कर ली, जो घरेलू पूंजी की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

• Under current Indian regulations, an FPI can hold up to 10% stake in a company without being classified as a Foreign Direct Investor (FDI).

• वर्तमान भारतीय नियमों के अनुसार, कोई FPI किसी कंपनी में 10% तक हिस्सेदारी रख सकता है बिना FDI के रूप में वर्गीकृत हुए।

• According to NSDL data for May 2026, FPIs were net sellers in 4 out of 5 trading sessions.

• मई 2026 के NSDL आंकड़ों के अनुसार, FPIs 5 में से 4 ट्रेडिंग सत्रों में शुद्ध विक्रेता रहे।

• The highest single-day FPI selling was recorded on 7 May 2026 with outflows

of ₹5,697.61 crore.

• 7 मई 2026 को FPIs द्वारा सबसे अधिक एकदिवसीय बिकवाली दर्ज की गई, जिसमें ₹5,697.61 करोड़ की निकासी हुई।

• Total weekly FPI outflows stood at ₹14,207.20 crore.

• साप्ताहिक कुल FPI निकासी ₹14,207.20 करोड़ रही।

• Only one trading session witnessed net inflows of ₹2,969.02 crore, indicating weak foreign investor sentiment overall.

• केवल एक ट्रेडिंग सत्र में ₹2,969.02 करोड़ की शुद्ध खरीद दर्ज हुई, जो विदेशी निवेशकों की कमजोर धारणा को दर्शाता है।

• According to JM Financials (April 2026), FPI ownership in Indian equities fell to 14.7%, the lowest since June 2012.

• JM Financials (अप्रैल 2026) के अनुसार, भारतीय इक्विटी में FPI स्वामित्व घटकर 14.7% रह गया, जो जून 2012 के बाद सबसे कम है।

• A decade ago, FPI ownership in Indian equities was around 19.9%.

• एक दशक पहले भारतीय इक्विटी में FPI स्वामित्व लगभग 19.9% था।

Ques: Why did RBI impose a penalty on IIFL Finance?

प्रश्न: RBI ने IIFL Finance पर जुर्माना क्यों लगाया?

A) Fraudulent transactions / धोखाधड़ी वाले लेनदेन

B) Cyber security breach / साइबर सुरक्षा उल्लंघन

C) Deficiencies in regulatory compliance / नियामकीय अनुपालन में कमियां

D) Tax evasion / कर चोरी

E) Loan default / ऋण चूक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India imposed a penalty of ₹3.1 lakh on IIFL Finance.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने IIFL Finance पर ₹3.1 लाख का जुर्माना लगाया।

• The penalty was imposed due to deficiencies in regulatory compliance.
• यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन (regulatory compliance) में कमियों के कारण लगाया गया।
• IIFL Finance failed to comply with certain provisions under the RBI Master Direction for NBFCs.
• IIFL Finance, NBFCs के लिए RBI Master Direction के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा।
• The action was related to the Scale Based Regulation (SBR) framework for Non-Banking Financial Companies.
• यह कार्रवाई Non-Banking Financial Companies के Scale Based Regulation (SBR) framework से संबंधित थी।
• RBI conducted a statutory inspection with reference to the company's financial position as of 31 March 2025.
• RBI ने कंपनी की 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में statutory inspection किया।
• RBI clarified that the penalty is based on regulatory deficiencies and does not question the validity of customer transactions.
• RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामकीय कमियों पर आधारित है और ग्राहकों के लेनदेन की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाता।
• NBFCs are financial institutions that provide banking services without holding a banking license.
• NBFCs ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंकिंग लाइसेंस के बिना वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Full Form – Reserve Bank of India
• RBI का पूर्ण रूप – भारतीय रिज़र्व बैंक
• RBI Headquarters – Mumbai
• RBI मुख्यालय – मुंबई
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• IIFL Full Form – India Infoline Finance Limited
• IIFL का पूर्ण रूप – इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड

• Type of Institution – NBFC
• संस्था का प्रकार – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)
• Penalty Amount – ₹3.1 lakh
• जुर्माना राशि – ₹3.1 लाख

Ques: Which bank became the first Taiwanese bank to establish a branch in GIFT City, Gujarat?

प्रश्न: GIFT City, गुजरात में शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन बना है?

A) CTBC Bank / CTBC बैंक

B) Taipei Fubon Bank / ताइपे फुबोन बैंक

C) Mega International Commercial Bank / मेगा इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक

D) Bank of Taiwan / बैंक ऑफ ताइवान

E) Taiwan Cooperative Bank / ताइवान कोऑपरेटिव बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• CTBC Bank announced the opening of its new branch at GIFT City, Gujarat.
• CTBC Bank ने गुजरात के GIFT City में अपनी नई शाखा खोलने की घोषणा की।
• The opening marks a significant milestone in the bank's three-decade commitment to the Indian market.
• यह भारत के बाजार के प्रति बैंक की तीन दशक पुरानी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
• CTBC Bank became the first Taiwanese bank to establish a presence in GIFT City.
• CTBC Bank, GIFT City में उपस्थिति स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक बन गया।
• It is also the only bank from Taiwan with a branch presence anywhere in

India.

• यह भारत में शाखा उपस्थिति रखने वाला ताइवान का एकमात्र बैंक भी है।

• The branch was established after obtaining approvals from the International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

• यह शाखा International Financial Services Centres Authority (IFSCA) से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद स्थापित की गई।

• GIFT City is emerging as a major international financial and fintech hub in India.

• GIFT City भारत में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और फिनटेक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

• The new branch is expected to strengthen financial cooperation between India and Taiwan.

• नई शाखा भारत और ताइवान के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी।

Ques : TVS Venu Group will acquire what percentage stake in Jana Small Finance Bank?

प्रश्न: TVS Venu Group, Jana Small Finance Bank में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा?

A) 4.9%
B) 5.6%
C) 9.9%
D) 12%
E) 15%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• TVS Venu Group will acquire a 9.9% stake in Jana Small Finance Bank for around ₹193 crore.

• TVS Venu Group लगभग ₹193 करोड़ में Jana Small Finance Bank की 9.9%

हिस्सेदारी खरीदेगा।

• The acquisition will be done through a mix of primary warrant subscription and secondary share purchase.

• यह अधिग्रहण primary warrant subscription और secondary share purchase के मिश्रण के माध्यम से किया जाएगा।

• Around 4.9% stake will be directly held by TVS Motor Company.

• लगभग 4.9% हिस्सेदारी सीधे TVS Motor Company के पास होगी।

• The transaction is expected to be completed within three months, subject to regulatory and customary approvals.

• यह सौदा आवश्यक अनुमतियों के बाद लगभग तीन महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

• The investment is part of TVS Group's strategy to expand its presence in the financial services sector.

• यह निवेश financial services sector में TVS Group की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।

• TVS Group had recently signed agreements to acquire 100% stake in PGIM India Asset Management.

• TVS Group ने हाल ही में PGIM India Asset Management में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है।

• Jana Small Finance Bank is among India's largest small finance banks in terms of assets and deposits.

• Jana Small Finance Bank, assets और deposits के आधार पर भारत के सबसे बड़े small finance banks में से एक है।

• Jana Small Finance Bank serves more than 12 million customers through 822 outlets across India.

• Jana Small Finance Bank भारत में 822 outlets के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है।

• The bank reported total income of ₹6,374.8 crore and net profit of ₹326.4 crore in FY26.

• बैंक ने FY26 में ₹6,374.8 करोड़ की कुल आय और ₹326.4 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Company – TVS Venu Group

- कंपनी – TVS Venu Group
- Bank – Jana Small Finance Bank
- बैंक – Jana Small Finance Bank
- Stake Acquired – 9.9%
- खरीदी गई हिस्सेदारी – 9.9%
- Deal Value – ₹193 Crore
- सौदे का मूल्य – ₹193 करोड़
- Sector – Financial Services / Banking
- क्षेत्र – वित्तीय सेवाएं / बैंकिंग
- Headquarters of Jana Small Finance Bank – Bengaluru
- Jana Small Finance Bank का मुख्यालय – Bengaluru
- Founded – 2006
- स्थापना वर्ष – 2006

Ques : Viyona Fintech received NPCI certification for which of the following payment systems?

प्रश्न: Viyona Fintech को निम्नलिखित में से किन payment systems के लिए NPCI certification प्राप्त हुआ?

A) UPI Acquirer / यूपीआई एक्वायरर

B) IMPS / आईएमपीएस

C) UPI Issuer / यूपीआई इश्यूअर

D) IBMB / आईबीएमबी

E) All of the Above / उपरोक्त सभी

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Hyderabad-based Viyona Fintech secured NPCI certification for multiple payment infrastructure layers.

• हैदराबाद स्थित Viyona Fintech ने कई payment infrastructure layers के लिए NPCI certification प्राप्त किया।

• The certifications include UPI Acquirer, UPI Issuer, IMPS, and Interoperable Banking Mobile Banking (IBMB).

• इन certifications में UPI Acquirer, UPI Issuer, IMPS और Interoperable Banking Mobile Banking (IBMB) शामिल हैं।

• These approvals allow the company to independently provide full-stack payment orchestration solutions.

• ये approvals कंपनी को स्वतंत्र रूप से full-stack payment orchestration solutions प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।

• The certification enables Viyona Fintech to manage payment services from merchant acceptance to customer-facing issuance infrastructure.

• यह certification Viyona Fintech को merchant acceptance से customer-facing issuance infrastructure तक payment services संचालित करने की क्षमता देता है।

• The company's technology framework is aligned with National Payments Corporation of India (NPCI) standards.

• कंपनी का technology framework National Payments Corporation of India (NPCI) के standards के अनुरूप है।

• The move strengthens Viyona Fintech's role in India's rapidly expanding digital payments ecosystem.

• यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते digital payments ecosystem में Viyona Fintech की भूमिका को मजबूत करता है।

• UPI and IMPS are among the most widely used digital payment systems in India.

• UPI और IMPS भारत की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली digital payment systems में शामिल हैं।

• The certification supports end-to-end payment orchestration capabilities for merchants and consumers.

• यह certification merchants और consumers के लिए end-to-end payment orchestration क्षमताओं को समर्थन देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Company – Viyona Fintech

- कंपनी – Viyona Fintech
- Certification Authority – NPCI
- Certification प्रदान करने वाली संस्था – NPCI
- Headquarters – Hyderabad
- मुख्यालय – Hyderabad
- Payment Systems Covered – UPI Acquirer, UPI Issuer, IMPS, IBMB
- शामिल Payment Systems – UPI Acquirer, UPI Issuer, IMPS, IBMB
- Sector – Fintech / Digital Payments
- क्षेत्र – Fintech / Digital Payments
- NPCI Full Form – National Payments Corporation of India
- NPCI का पूर्ण रूप – National Payments Corporation of India
- IMPS Full Form – Immediate Payment Service
- IMPS का पूर्ण रूप – Immediate Payment Service

Ques: Which foreign company agreed to acquire a 75% stake in Bharti Life Insurance Company?

प्रश्न: किस विदेशी कंपनी ने Bharti Life Insurance Company में 75% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति दी है?

A) Allianz SE / एलियांज SE

B) AXA Group / AXA ग्रुप

C) Aviva plc / अवीवा पीएलसी

D) MetLife Inc. / मेटलाइफ इंक.

E) Prudential plc / प्रूडेंशियल पीएलसी

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Prudential plc agreed to acquire a 75% stake in Bharti Life Insurance Company.

• Prudential plc ने Bharti Life Insurance Company में 75% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति दी है।

• The deal is considered the first major insurance sector transaction after the government allowed 100% Foreign Direct Investment (FDI) in insurance.

• सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% Foreign Direct Investment (FDI) की अनुमति देने के बाद यह पहला बड़ा बीमा क्षेत्र का सौदा माना जा रहा है।

• The stake will be acquired from Bharti Life Ventures Pvt Ltd and 360 ONE Asset Management.

• यह हिस्सेदारी Bharti Life Ventures Pvt Ltd और 360 ONE Asset Management से खरीदी जाएगी।

• The transaction involves an initial cash consideration of ₹3,500 crore.

• इस लेन-देन में प्रारंभिक नकद भुगतान ₹3,500 करोड़ का होगा।

• An additional amount of up to ₹700 crore may also be paid later.

• इसके अतिरिक्त बाद में ₹700 करोड़ तक का भुगतान और किया जा सकता है।

• After completion of the transaction, Bharti Life will become India's fifth insurance company with 75% foreign ownership.

• इस सौदे के बाद Bharti Life, 75% विदेशी स्वामित्व वाली भारत की पाँचवीं बीमा कंपनी बन जाएगी।

• The move reflects increasing foreign investor interest in India's insurance sector.

• यह कदम भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

Ques : Liberty Mutual increased its stake in Liberty General Insurance to what percentage?

प्रश्न: Liberty Mutual ने Liberty General Insurance में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी?

A) 49%
B) 55.4%
C) 60%
D) 74%
E) 100%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• US-based Liberty Mutual Insurance increased its stake in Liberty General Insurance to 74%.

• अमेरिका स्थित Liberty Mutual Insurance ने Liberty General Insurance में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74% कर दी।

• Earlier, Liberty Mutual had increased its stake from 49% to 55.4% in September 2025.

• इससे पहले सितंबर 2025 में Liberty Mutual ने अपनी हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 55.4% की थी।

• Liberty General Insurance is a joint venture between Liberty Mutual, Summit Asia Investments Holdings, and Enam Securities.

• Liberty General Insurance, Liberty Mutual, Summit Asia Investments Holdings और Enam Securities के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

• The increase in stake reflects Liberty Mutual's growing confidence in the Indian insurance market.

• हिस्सेदारी में वृद्धि भारतीय बीमा बाजार में Liberty Mutual के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

• The Government of India recently allowed 100% Foreign Direct Investment (FDI) in insurance companies under the automatic route.

• भारत सरकार ने हाल ही में बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को automatic route के तहत अनुमति दी है।

• Liberty General Insurance provides retail, commercial and industrial insurance solutions in India.

• Liberty General Insurance भारत में retail, commercial और industrial insurance solutions प्रदान करती है।

• The company operates across more than 95 locations in India.

• कंपनी भारत में 95 से अधिक स्थानों पर कार्यरत है।

• The move strengthens Liberty Mutual's long-term strategic presence in India's insurance sector.

• यह कदम भारत के बीमा क्षेत्र में Liberty Mutual की दीर्घकालिक रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Company – Liberty Mutual Insurance
- कंपनी – Liberty Mutual Insurance
- Country – United States of America (USA)
- देश – संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- Stake Increased To – 74%
- बढ़ाई गई हिस्सेदारी – 74%
- Sector – Insurance
- क्षेत्र – बीमा
- FDI Limit in Insurance Sector – 100%
- बीमा क्षेत्र में FDI सीमा – 100%
- Liberty General Insurance Operations Started – 2013
- Liberty General Insurance का संचालन प्रारंभ – 2013

Ques : What has RBI recently removed for banks to improve flexibility?
प्रश्न: RBI ने हाल ही में बैंकों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु क्या हटाया है?

A) CRR Requirement / CRR आवश्यकता

B) SLR Requirement / SLR आवश्यकता

C) Investment Fluctuation Reserve (IFR) / इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व (IFR)

D) Priority Sector Lending / प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

E) Repo Rate / रेपो रेट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- RBI has removed the requirement of Investment Fluctuation Reserve (IFR) for banks.

• RBI ने बैंकों के लिए IFR बनाए रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
• The decision is applicable to banks that already maintain capital for market risk.
• यह निर्णय उन बैंकों पर लागू होगा जो पहले से मार्केट रिस्क के लिए पूंजी बनाए रखते हैं।
• IFR acted as a buffer against losses due to interest rate fluctuations.
• IFR ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान के लिए बफर का काम करता था।
• The move aims to reduce operational rigidity and improve flexibility.
• इस कदम का उद्देश्य ऑपरेशनल कठोरता कम करना और लचीलापन बढ़ाना है।
• The revised norms will harmonise regulatory instructions across entities.
• संशोधित नियम नियामकीय निर्देशों में समानता लाएंगे।
• The new rules are applicable to commercial banks, small finance banks, payment banks, cooperative banks and RRBs.
• यह नए नियम वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक और RRBs पर लागू होंगे।
• Existing IFR balances will be transferred to reserves or P&L accounts.
• मौजूदा IFR राशि को रिजर्व या P&L खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
• IFR earlier served as a safety cushion against market volatility in investment portfolios.
• IFR पहले निवेश पोर्टफोलियो में बाजार अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता था।
• RBI aims to align prudential norms with modern risk-based frameworks while ensuring financial stability.
• RBI का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए प्रूडेंशियल मानकों को आधुनिक जोखिम-आधारित ढांचे के अनुरूप बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
• नियामक – Reserve Bank of India (RBI)
• Term – Investment Fluctuation Reserve (IFR)
• शब्द – Investment Fluctuation Reserve (IFR)
• Purpose – Buffer against investment/interest rate risks
• उद्देश्य – निवेश/ब्याज दर जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा बफर

• Effective – May 2026 (as per revised norms)
• प्रभावी – मई 2026 (संशोधित नियमों के अनुसार)
• Applicable Institutions – Commercial Banks, SFBs, Payment Banks, Cooperative Banks, RRBs
• लागू संस्थाएं – वाणिज्यिक बैंक, SFBs, पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक, RRBs

---

Ques : According to the RBI report, credit card transaction volumes in India reached how many crore in 2025?

प्रश्न: RBI रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में क्रेडिट कार्ड लेनदेन की संख्या कितनी करोड़ रही?

A) 216 crore / 216 करोड़
B) 350 crore / 350 करोड़
C) 480 crore / 480 करोड़
D) 570 crore / 570 करोड़
E) 700 crore / 700 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) reported that credit card transactions increased by 2.6 times between 2021 and 2025.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार 2021 से 2025 के बीच क्रेडिट कार्ड लेनदेन 2.6 गुना बढ़ गए।
• Credit card transaction volumes rose from 216 crore in 2021 to 570 crore in 2025.
• क्रेडिट कार्ड लेनदेन की संख्या 2021 में 216 करोड़ से बढ़कर 2025 में 570 करोड़ हो गई।
• The transaction value increased from ₹8.9 lakh crore to ₹23.2 lakh crore during the same period.

• इसी अवधि में लेनदेन का मूल्य ₹8.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹23.2 लाख करोड़ हो गया।

• RBI highlighted the rapid expansion of digital payments and electronic payment systems in India.

• RBI ने भारत में डिजिटल भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तेज विस्तार को रेखांकित किया।

• Digital payment transaction volumes increased 33 times between 2016 and 2025.

• 2016 से 2025 के बीच डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा 33 गुना बढ़ी।

• Private sector banks increased their market share in outstanding credit cards to 71.1% in 2025.

• निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2025 में outstanding credit cards में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 71.1% कर ली।

• Debit card transaction volumes declined due to growing competition from UPI and digital wallets.

• UPI और डिजिटल वॉलेट्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण डेबिट कार्ड लेनदेन में गिरावट दर्ज की गई।

• UPI QR codes increased significantly, reflecting wider merchant adoption of QR-based payments.

• UPI QR codes में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो QR आधारित भुगतान की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है।

• The report highlighted the increasing role of UPI infrastructure and private banks in India's digital economy.

• रिपोर्ट ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में UPI इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी बैंकों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Full Form – Reserve Bank of India

• RBI का पूर्ण रूप – भारतीय रिज़र्व बैंक

• RBI Headquarters – Mumbai

• RBI मुख्यालय – मुंबई

• RBI Governor – Sanjay Malhotra

• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

• Credit Card Transactions in 2025 – 570 crore
• 2025 में क्रेडिट कार्ड लेनदेन – 570 करोड़
• Transaction Value in 2025 – ₹23.2 lakh crore
• 2025 में लेनदेन मूल्य – ₹23.2 लाख करोड़
• Growth in Digital Payments (2016–2025) – 33 times
• डिजिटल भुगतान वृद्धि (2016–2025) – 33 गुना

Ques: What is the full form of UDGAM, the portal launched by RBI to help trace unclaimed deposits?

प्रश्न: RBI द्वारा शुरू किए गए UDGAM पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, जो बिना दावे वाली जमा राशि खोजने में मदद करता है?

A) Unified Deposit Gateway and Management / यूनिफाइड डिपॉजिट गेटवे एंड मैनेजमेंट

B) Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information / अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स – गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन

C) Universal Deposits and General Account Mechanism / यूनिवर्सल डिपॉजिट्स एंड जनरल अकाउंट मैकेनिज्म

D) Unified Digital Gateway for Account Monitoring / यूनिफाइड डिजिटल गेटवे फॉर अकाउंट मॉनिटरिंग

E) Unclaimed Deposit Grievance and Monitoring / अनक्लेम्ड डिपॉजिट ग्रीवांस एंड मॉनिटरिंग

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) informed the Supreme Court that 30 banks have been integrated into the UDGAM portal.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 बैंकों को UDGAM पोर्टल से

जोड़ा गया है।

• The portal helps legal heirs trace unclaimed funds of deceased account holders.

• यह पोर्टल मृत खाताधारकों की बिना दावे वाली जमा राशि खोजने में कानूनी उत्तराधिकारियों की सहायता करता है।

• UDGAM stands for "Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information."

• UDGAM का पूर्ण रूप "Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information" है।

• UDGAM is an online centralized portal developed by the RBI.

• UDGAM, RBI द्वारा विकसित एक ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल है।

• The platform was developed in collaboration with Reserve Bank Information Technology Pvt Ltd (ReBIT), Indian Financial Technology and Allied Services (IFTAS), and selected banks.

• यह प्लेटफॉर्म Reserve Bank Information Technology Pvt Ltd (ReBIT), Indian Financial Technology and Allied Services (IFTAS) तथा चुनिंदा बैंकों के सहयोग से विकसित किया गया।

• According to RBI, unclaimed deposits include savings or current accounts inactive for 10 years.

• RBI के अनुसार, बिना दावे वाली जमा राशि में वे बचत या चालू खाते शामिल हैं जो 10 वर्षों से निष्क्रिय हैं।

• Fixed deposits not claimed within 10 years from maturity are also treated as unclaimed deposits.

• परिपक्वता के 10 वर्षों तक दावा न किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट भी बिना दावे वाली जमा राशि माने जाते हैं।

• Such funds are transferred to the Depositor Education and Awareness (DEA) Fund maintained by RBI.

• ऐसी राशि RBI द्वारा संचालित Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में स्थानांतरित कर दी जाती है।

Ques : What is the withdrawal limit imposed by RBI on Nagar Sahakari Bank customers?

प्रश्न: RBI द्वारा नगर सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा कितनी तय की

गई है?

A) ₹5,000 / ₹5,000
B) ₹10,000 / ₹10,000
C) ₹20,000 / ₹20,000
D) ₹50,000 / ₹50,000
E) ₹1,00,000 / ₹1,00,000

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a 6-month moratorium on Nagar Sahakari Bank.
• RBI ने नगर सहकारी बैंक पर 6 महीने का मोरेटोरियम लगाया है।
• The bank is based in Etawah, Uttar Pradesh.
• यह बैंक इटावा, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
• Customers can withdraw a maximum of ₹10,000 during this period.
• इस अवधि में ग्राहक अधिकतम ₹10,000 ही निकाल सकते हैं।
• The action is due to supervisory and financial concerns.
• यह कदम नियामकीय और वित्तीय चिंताओं के कारण उठाया गया है।
• Restrictions came into effect from the close of business on Monday.
• ये प्रतिबंध सोमवार के कार्य समाप्ति के बाद लागू हुए।
• RBI imposed limits to protect depositors and ensure stability.
• RBI ने यह कदम जमाकर्ताओं की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया।
• The moratorium aims to control liquidity outflow and prevent panic withdrawals.
• यह मोरेटोरियम तरलता के बहिर्वाह को नियंत्रित करने और घबराहट में निकासी को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है।
• RBI generally takes such measures to maintain financial stability and support corrective actions in weak banks.
• RBI आमतौर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और कमजोर बैंकों में सुधारात्मक कदमों के समर्थन हेतु ऐसे उपाय करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
- नियामक – Reserve Bank of India (RBI)
- Bank – Nagar Sahakari Bank
- बैंक – Nagar Sahakari Bank
- Location – Etawah (Uttar Pradesh)
- स्थान – Etawah (Uttar Pradesh)
- Withdrawal Limit – ₹10,000
- निकासी सीमा – ₹10,000
- Duration – 6 months
- अवधि – 6 महीने

Ques: Who has been appointed as the Executive Director (ED) of the Reserve Bank of India (RBI)?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के Executive Director (ED) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर

B) Gunveer Singh / गुनवीर सिंह

C) M. Rajeshwar Rao / एम. राजेश्वर राव

D) Ajay Kumar Choudhary / अजय कुमार चौधरी

E) Swaminathan J / स्वामीनाथन जे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) appointed Gunveer Singh as Executive Director (ED).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुनवीर सिंह को Executive Director (ED) नियुक्त किया

है।

• Prior to his promotion, Gunveer Singh served as Chief General Manager-in-Charge of the Department of Payment and Settlement Systems.

• पदोन्नति से पहले गुनवीर सिंह RBI के Department of Payment and Settlement Systems के Chief General Manager-in-Charge के रूप में कार्यरत थे।

• The Department of Payment and Settlement Systems handles payment infrastructure and settlement mechanisms in India.

• Department of Payment and Settlement Systems भारत में भुगतान अवसंरचना और निपटान प्रणालियों का संचालन करता है।

• As Executive Director, Gunveer Singh will play an important role in RBI's policy implementation and financial regulation.

• Executive Director के रूप में गुनवीर सिंह RBI की नीतियों के कार्यान्वयन और वित्तीय विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• RBI is India's central banking institution responsible for monetary policy and regulation of the banking system.

• RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेदार है।

Ques : What is the new base year for GDP & GSVA as per NSO?

प्रश्न: NSO के अनुसार GDP और GSVA का नया आधार वर्ष क्या है?

A) 2010–11 / 2010–11
B) 2011–12 / 2011–12
C) 2015–16 / 2015–16
D) 2020–21 / 2020–21
E) 2022–23 / 2022–23

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The National Statistical Office (NSO) has revised the base year to 2022–23.

• नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने आधार वर्ष 2022–23 कर दिया है।
• It covers GDP and Gross State Value Added (GSVA) calculations.
• यह GDP और GSVA की गणना पर लागू होगा।
• The new series replaces the old base year 2011–12.
• यह नई श्रृंखला 2011–12 के पुराने आधार वर्ष को बदलती है।
• The aim is to improve accuracy, comparability and alignment with the current economy.
• इसका उद्देश्य सटीकता, तुलना और वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुरूपता को बढ़ाना है।
• The move seeks uniform adoption across all states and Union Territories.
• इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से अपनाना है।
• The new methodology includes double deflation and improved data sources.
• नई पद्धति में डबल डिफ्लेशन और बेहतर डेटा स्रोत शामिल हैं।
• It helps in better measurement of real economic output.
• यह वास्तविक आर्थिक उत्पादन के बेहतर मापन में मदद करता है।
• The updated framework increases the use of administrative and survey data for better economic estimates.
• अपडेटेड फ्रेमवर्क बेहतर आर्थिक अनुमान के लिए प्रशासनिक और सर्वे डेटा के उपयोग को बढ़ाता है।
• The revision reflects the changing structure of the Indian economy.
• यह संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Organization – National Statistical Office (NSO)
• संगठन – National Statistical Office (NSO)
• Ministry – Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI)
• मंत्रालय – Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI)
• New Base Year – 2022–23
• नया आधार वर्ष – 2022–23
• Old Base Year – 2011–12
• पुराना आधार वर्ष – 2011–12
• Economic Indicators Covered – GDP & GSVA
• शामिल आर्थिक संकेतक – GDP एवं GSVA

Ques : What is the minimum annual turnover required for FFMCs as per new RBI rules?

प्रश्न: RBI के नए नियमों के अनुसार FFMCs के लिए न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर कितना है?

A) ₹5 crore / ₹5 करोड़

B) ₹10 crore / ₹10 करोड़

C) ₹25 crore / ₹25 करोड़

D) ₹50 crore / ₹50 करोड़

E) ₹100 crore / ₹100 करोड़

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• RBI has introduced minimum turnover requirements for money changers.

• RBI ने मनी चेंजर्स के लिए न्यूनतम टर्नओवर आवश्यकताएं तय की हैं।

• FFMCs (Full-Fledged Money Changers) must maintain ₹10 crore annual forex turnover.

• FFMCs को ₹10 करोड़ वार्षिक फॉरेक्स टर्नओवर बनाए रखना होगा।

• AD Category-II entities must achieve ₹50 crore turnover within 2 years.

• AD Category-II संस्थाओं को 2 वर्षों में ₹50 करोड़ टर्नओवर हासिल करना होगा।

• RBI will not issue fresh FFMC licences going forward.

• RBI अब नए FFMC लाइसेंस जारी नहीं करेगा।

• Trade transactions for AD Category-II are capped at ₹25 lakh per deal.

• AD Category-II के लिए प्रति लेनदेन ₹25 लाख की सीमा तय की गई है।

• Minimum net worth requirement for AD Category-II is ₹10 crore.

• AD Category-II के लिए न्यूनतम नेटवर्थ ₹10 करोड़ तय है।

• These rules aim to strengthen compliance, customer protection and anti-money laundering (AML) measures.

• ये नियम अनुपालन, ग्राहक सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (AML) को मजबूत करेंगे।

• The RBI introduced these thresholds to ensure better regulation and transparency in the forex market.
• RBI ने फॉरेक्स बाजार में बेहतर विनियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये सीमाएं लागू की हैं।
• RBI has decided to stop issuing new FFMC licences and focus on strengthening existing players.
• RBI ने नए FFMC लाइसेंस जारी करना बंद करने और मौजूदा संस्थाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
• नियामक – Reserve Bank of India (RBI)
• Sector – Forex / Money Changing
• क्षेत्र – Forex / Money Changing
• Key Entity – FFMC (Full-Fledged Money Changer)
• प्रमुख संस्था – FFMC (Full-Fledged Money Changer)
• Effective – 2026
• प्रभावी वर्ष – 2026
• Minimum FFMC Annual Turnover – ₹10 crore
• FFMC न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर – ₹10 करोड़
• AD Category-II Minimum Net Worth – ₹10 crore
• AD Category-II न्यूनतम नेटवर्थ – ₹10 करोड़

Ques : According to the "State of Indian States: 2026" report, which state recorded the highest five-year nominal CAGR growth?
प्रश्न: "State of Indian States: 2026" रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक पाँच-वर्षीय नाममात्र CAGR वृद्धि दर्ज की?

A) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
B) Karnataka / कर्नाटक
C) Meghalaya / मेघालय

D) Assam / असम

E) Maharashtra / महाराष्ट्र

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• A report titled “State of Indian States: 2026” was released by wealth management firm Client Associates.

• वेल्थ मैनेजमेंट फर्म Client Associates द्वारा “State of Indian States: 2026” रिपोर्ट जारी की गई।

• Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka and Gujarat together contributed nearly 48% of India’s GDP in FY2025.

• महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात ने मिलकर FY2025 में भारत की GDP में लगभग 48% योगदान दिया।

• Assam emerged as the fastest-growing large state with a five-year nominal CAGR of 17.32%.

• असम 17.32% CAGR के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बड़ा राज्य बनकर उभरा।

• Uttar Pradesh recorded a nominal CAGR of 15.34% during FY20–FY25.

• उत्तर प्रदेश ने FY20–FY25 के दौरान 15.34% CAGR दर्ज किया।

• Meghalaya registered a growth rate of 15.27% CAGR in the same period.

• मेघालय ने इसी अवधि में 15.27% CAGR की वृद्धि दर्ज की।

• Karnataka and Manipur also recorded growth above 15% CAGR.

• कर्नाटक और मणिपुर ने भी 15% से अधिक CAGR दर्ज किया।

• The report highlighted that economic momentum is now spreading beyond traditional economic centres.

• रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक गति अब पारंपरिक आर्थिक केंद्रों से आगे फैल रही है।

• Uttar Pradesh’s growth was attributed to reforms like NIVESH MITRA, land digitisation and infrastructure development.

• उत्तर प्रदेश की वृद्धि का श्रेय NIVESH MITRA, भूमि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचा विकास जैसे सुधारों को दिया गया।

• The findings indicate a broader regional diversification of India’s economic growth pattern.

• यह निष्कर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि के व्यापक क्षेत्रीय विस्तार को दर्शाते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Largest State Economy in India – Maharashtra
- भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था – महाराष्ट्र
- Assam Capital – Dispur
- असम की राजधानी – दिसपुर
- Meghalaya Capital – Shillong
- मेघालय की राजधानी – शिलांग
- Uttar Pradesh Capital – Lucknow
- उत्तर प्रदेश की राजधानी – लखनऊ
- India's GDP Base Year – 2022–23
- भारत की GDP का आधार वर्ष – 2022–23

Ques : Why did RBI cancel the licence of The Yashwant Co-operative Bank Ltd.?

प्रश्न: RBI ने The Yashwant Co-operative Bank Ltd. का लाइसेंस क्यों रद्द किया?

A) Cybersecurity violations / साइबर सुरक्षा उल्लंघन

B) Merger with another bank / किसी अन्य बैंक के साथ विलय

C) Inadequate capital and poor financial condition / अपर्याप्त पूंजी और कमजोर वित्तीय स्थिति

D) Foreign investment issues / विदेशी निवेश संबंधी मुद्दे

E) Tax fraud allegations / कर धोखाधड़ी के आरोप

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) cancelled the banking licence of The Yashwant Co-operative Bank Ltd., Phaltan, Maharashtra.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के फलटन स्थित The Yashwant Co-operative Bank Ltd. का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।

• The cancellation became effective from the close of business on 19 May 2026.

• यह निर्णय 19 मई 2026 को बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद प्रभावी हुआ।

• RBI stated that the bank lacked adequate capital and earning prospects.

• RBI के अनुसार बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं थीं।

• The bank was also unable to pay its depositors in full.

• बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि लौटाने में असमर्थ था।

• RBI requested the Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra to initiate the process of winding up the bank and appoint a liquidator.

• RBI ने Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra को बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया।

• Eligible depositors can receive insurance claims up to ₹5 lakh under the DICGC scheme.

• पात्र जमाकर्ताओं को DICGC योजना के तहत ₹5 लाख तक का बीमा दावा प्राप्त होगा।

• Around 99.02% depositors are eligible to receive the full amount of their deposits.

• लगभग 99.02% जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त करने के पात्र हैं।

• As of 20 April 2026, DICGC had already paid ₹106.96 crore.

• 20 अप्रैल 2026 तक DICGC द्वारा ₹106.96 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

• The action was taken to protect depositors' interests and maintain financial stability in the cooperative banking sector.

• यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bank Name – The Yashwant Co-operative Bank Ltd.

• बैंक का नाम – The Yashwant Co-operative Bank Ltd.

• Location – Phaltan, Maharashtra

• स्थान – फलटन, महाराष्ट्र

• Regulator – Reserve Bank of India (RBI)

• नियामक संस्था – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

• Deposit Insurance Agency – DICGC
• जमा बीमा संस्था – DICGC
• Maximum Deposit Insurance – ₹5 Lakh
• अधिकतम जमा बीमा – ₹5 लाख
• Licence Cancellation Effective Date – 19 May 2026
• लाइसेंस रद्द होने की प्रभावी तिथि – 19 मई 2026

Ques : Where is Central Bank of India launching its IFSC Banking Unit (IBU)?
प्रश्न: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना IFSC Banking Unit (IBU) कहाँ शुरू कर रहा है?

A) Mumbai / मुंबई
B) Hyderabad / हैदराबाद
C) Bengaluru / बेंगलुरु
D) GIFT City, Gandhinagar / GIFT City, गांधीनगर
E) Chennai / चेन्नई

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Central Bank of India is set to operationalise an IFSC Banking Unit (IBU) at GIFT City, Gandhinagar.
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया GIFT City, गांधीनगर में IFSC Banking Unit (IBU) शुरू करने जा रहा है।
• The branch will function as an international banking branch.
• यह शाखा एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा के रूप में कार्य करेगी।
• The IBU will provide corporate clients access to global financial markets.
• यह IBU कॉर्पोरेट ग्राहकों को वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा।
• Customers will also get access to specialized foreign exchange (forex) services.
• ग्राहकों को विशेष विदेशी मुद्रा (Forex) सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

• The bank received regulatory approvals from the Reserve Bank of India (RBI) and the International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

• बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और International Financial Services Centres Authority (IFSCA) से नियामकीय मंजूरी प्राप्त हुई है।

• The announcement was made by the bank's MD & CEO Kalyan Kumar.

• यह घोषणा बैंक के MD एवं CEO कल्याण कुमार द्वारा की गई।

• GIFT City is emerging as India's major hub for international financial services and offshore banking.

• GIFT City भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं और ऑफशोर बैंकिंग का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।

• The move will strengthen the bank's international banking operations and forex-related business activities.

• यह कदम बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संचालन और फॉरेक्स संबंधी व्यवसाय को मजबूत करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bank Name – Central Bank of India
• बैंक का नाम – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
• New Unit – IFSC Banking Unit (IBU)
• नई इकाई – IFSC Banking Unit (IBU)
• Location – GIFT City, Gandhinagar
• स्थान – GIFT City, गांधीनगर
• Regulatory Authorities – RBI & IFSCA
• नियामक संस्थाएं – RBI एवं IFSCA
• Bank MD & CEO – Kalyan Kumar
• बैंक के MD एवं CEO – कल्याण कुमार
• Main Services – Global Banking & Forex Services
• मुख्य सेवाएं – वैश्विक बैंकिंग एवं फॉरेक्स सेवाएं

Ques: Which platform will EPFO use to provide services such as PF balance check and claim status to subscribers?

प्रश्न: EPFO अपने सदस्यों को PF बैलेंस और क्लेम स्टेटस जैसी सेवाएं किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराएगा?

A) Telegram / टेलीग्राम

B) Signal / सिग्नल

C) WhatsApp / व्हाट्सएप

D) Facebook / फेसबुक

E) Instagram / इंस्टाग्राम

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) will soon provide various services through WhatsApp.

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

• Subscribers will be able to check their PF balance, last five transactions and claim status using WhatsApp services.

• सदस्य व्हाट्सएप सेवा के जरिए अपना PF बैलेंस, अंतिम पांच लेनदेन और क्लेम स्टेटस देख सकेंगे।

• The service is expected to be available to all EPFO subscribers within one month.

• यह सेवा सभी EPFO सदस्यों के लिए एक महीने के भीतर उपलब्ध होने की संभावना है।

• Union Labour Minister Mansukh Mandaviya announced that testing of the system has already been completed.

• केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है।

• EPFO is also planning to allow UPI-based withdrawal and direct bank transfer of provident funds.

• EPFO भविष्य निधि की UPI आधारित निकासी और सीधे bank account में transfer की सुविधा भी शुरू करने की योजना बना रहा है।

• Members sending WhatsApp messages will be verified through their registered mobile number linked with UAN.

• व्हाट्सएप संदेश भेजने वाले सदस्यों का सत्यापन उनके UAN से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाएगा।

• EPFO stated that initiatives like “Nidhi Aapke Nikat (NAN)” helped reduce pending consumer court cases.

• EPFO ने बताया कि “निधि आपके निकट (NAN)” जैसी पहलों से उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों में कमी आई है।

• The initiative aims to improve accessibility and digital delivery of EPFO services.

• इस पहल का उद्देश्य EPFO सेवाओं की पहुंच और डिजिटल वितरण को बेहतर बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Organisation – Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)
• संगठन – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
• EPFO Established – 1952
• EPFO की स्थापना – 1952
• EPFO Headquarters – New Delhi
• EPFO मुख्यालय – नई दिल्ली
• Parent Ministry – Ministry of Labour & Employment
• मूल मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
• Union Labour Minister – Mansukh Mandaviya
• केंद्रीय श्रम मंत्री – मनसुख मंडाविया
• UAN Full Form – Universal Account Number
• UAN का पूर्ण रूप – Universal Account Number
• Proposed Services – PF Balance, Last Five Transactions, Claim Status
• प्रस्तावित सेवाएं – PF बैलेंस, अंतिम पाँच लेनदेन, क्लेम स्टेटस
• Verification Method – Registered Mobile Number linked with UAN
• सत्यापन विधि – UAN से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल नंबर
• Additional Planned Feature – UPI-based PF Withdrawal

• अतिरिक्त प्रस्तावित सुविधा – UPI आधारित PF निकासी

Ques: Under RBI's revised draft norms, lenders can restrict a borrower's mobile phone functions only if which condition is fulfilled?

प्रश्न: RBI के संशोधित मसौदा नियमों के अनुसार, ऋणदाता उधारकर्ता के मोबाइल फोन की सुविधाओं को केवल किस स्थिति में सीमित कर सकते हैं?

A) If the borrower misses one EMI / यदि उधारकर्ता एक ईएमआई चूक जाए

B) If the borrower changes SIM card / यदि उधारकर्ता सिम कार्ड बदल दे

C) If the mobile device itself was financed through a loan / यदि मोबाइल डिवाइस स्वयं ऋण पर खरीदा गया हो

D) If the borrower has multiple loans / यदि उधारकर्ता के पास कई ऋण हों

E) If the bank issues a single notice / यदि बैंक एक नोटिस जारी करे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) issued revised draft norms on loan recovery practices.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण वसूली प्रक्रियाओं से जुड़े संशोधित मसौदा नियम जारी किए।

• Lenders will not be allowed to disable or restrict a borrower's mobile phone as a recovery tool.

• ऋणदाता अब ऋण वसूली के लिए उधारकर्ता के मोबाइल फोन को बंद या सीमित नहीं कर सकेंगे।

• An exception is allowed only when the mobile device itself was purchased through a loan.

• केवल उसी स्थिति में अनुमति होगी जब मोबाइल डिवाइस स्वयं ऋण पर खरीदा गया हो।

• In such cases, the restriction can be applied only after the loan account

becomes 90 days overdue.

• ऐसे मामलों में यह प्रतिबंध तभी लगाया जा सकेगा जब ऋण खाता 90 दिनों तक बकाया हो जाए।

• Lenders must first issue multiple notices, including a 21-day cure period and an additional 7-day notice.

• ऋणदाताओं को पहले कई नोटिस जारी करने होंगे, जिनमें 21 दिन की सुधार अवधि और अतिरिक्त 7 दिन का नोटिस शामिल होगा।

• Banks and lenders must restore mobile functions within one hour after the borrower clears dues.

• उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि चुकाने के बाद बैंकों और ऋणदाताओं को एक घंटे के भीतर मोबाइल की सुविधाएँ बहाल करनी होंगी।

• If the delay continues, lenders will have to pay compensation of ₹250 per hour to the borrower.

• यदि देरी होती है, तो ऋणदाताओं को उधारकर्ता को ₹250 प्रति घंटा मुआवजा देना होगा।

• RBI also proposed stricter governance standards for recovery agents and borrower protection measures.

• RBI ने रिकवरी एजेंटों के लिए सख्त प्रशासनिक मानदंड और उधारकर्ता सुरक्षा उपाय भी प्रस्तावित किए हैं।

• Recovery agents will be allowed to contact borrowers only between 8 AM and 7 PM unless authorised otherwise.

• रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही उधारकर्ताओं से संपर्क कर सकेंगे, जब तक कि अन्यथा अनुमति न हो।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Full Form – Reserve Bank of India

• RBI का पूर्ण रूप – भारतीय रिजर्व बैंक

• RBI Nationalised – 1 January 1949

• RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

Ques: Greece's Eurobank inaugurated its representative office in which Indian city?

प्रश्न: ग्रीस के Eurobank ने अपना प्रतिनिधि कार्यालय भारत के किस शहर में खोला है?

A) New Delhi / नई दिल्ली

B) Bengaluru / बेंगलुरु

C) Mumbai / मुंबई

D) Chennai / चेन्नई

E) Hyderabad / हैदराबाद

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Greece's Eurobank has established a representative office in India.

• ग्रीस के Eurobank ने भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया है।

• This is the bank's first expansion outside Europe.

• यह बैंक का यूरोप के बाहर पहला विस्तार है।

• The office has been opened to tap trade and investment opportunities in India.

• यह कार्यालय भारत में व्यापार और निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए खोला गया है।

• The office will be inaugurated in Mumbai by Cyprus President Nikos Christodoulides.

• इस कार्यालय का उद्घाटन मुंबई में साइप्रस के राष्ट्रपति Nikos Christodoulides द्वारा किया जाएगा।

• Eurobank has total assets of around €110 billion.

• Eurobank की कुल परिसंपत्तियाँ लगभग €110 बिलियन हैं।

• The bank already operates in countries such as Cyprus, Bulgaria and Luxembourg.

• बैंक पहले से Cyprus, Bulgaria और Luxembourg जैसे देशों में कार्यरत है।

• Eurobank has started offering cross-border remittance services through UPI for Indians in Greece.

• Eurobank ने ग्रीस में रहने वाले भारतीयों के लिए UPI के माध्यम से सीमा-पार प्रेषण सेवाएँ शुरू की हैं।
• Initially, the India office will provide advisory services and financing options for trade and investments.
• प्रारंभिक चरण में भारत कार्यालय व्यापार और निवेश के लिए सलाहकार सेवाएँ और वित्तीय विकल्प प्रदान करेगा।
• The move is significant in the context of the proposed India-EU Free Trade Agreement (FTA).
• यह कदम प्रस्तावित India-EU Free Trade Agreement (FTA) के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bank Name – Eurobank
• बैंक का नाम – Eurobank
• Eurobank Country – Greece
• Eurobank का देश – Greece
• Headquarters – Athens, Greece
• मुख्यालय – एथेंस, ग्रीस
• India Office Location – Mumbai
• भारत कार्यालय का स्थान – Mumbai
• Cyprus President – Nikos Christodoulides
• साइप्रस के राष्ट्रपति – Nikos Christodoulides
• Cyprus Capital – Nicosia
• साइप्रस की राजधानी – निकोसिया
• Currency of Greece – Euro (€)
• ग्रीस की मुद्रा – यूरो (€)
• India Financial Capital – Mumbai
• भारत की वित्तीय राजधानी – मुंबई

Ques: What is the value of the USD/INR Buy/Sell swap auction announced by the Reserve Bank of India (RBI)?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा घोषित USD/INR Buy/Sell swap auction का मूल्य कितना है?

A) USD 1 Billion / 1 अरब अमेरिकी डॉलर

B) USD 3 Billion / 3 अरब अमेरिकी डॉलर

C) USD 5 Billion / 5 अरब अमेरिकी डॉलर

D) USD 7 Billion / 7 अरब अमेरिकी डॉलर

E) USD 10 Billion / 10 अरब अमेरिकी डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) announced a USD/INR Buy/Sell swap auction worth USD 5 billion.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने USD 5 बिलियन मूल्य के USD/INR Buy/Sell swap auction की घोषणा की।

• The swap auction will have a tenor of three years.

• यह swap auction तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

• The auction is scheduled to be held on May 26.

• यह नीलामी 26 मई को आयोजित की जाएगी।

• The move comes amid significant depreciation of the Indian rupee against the US dollar due to global uncertainties.

• यह कदम वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई गिरावट के बीच उठाया गया है।

• Authorized Dealers Category-I (AD Category-I) banks are eligible to participate in the auction.

• Authorized Dealers Category-I (AD Category-I) बैंक इस नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे।

• Under the arrangement, RBI will buy US dollars from banks and simultaneously agree to sell the same amount back at the end of the swap period.

• इस व्यवस्था के तहत RBI बैंकों से अमेरिकी डॉलर खरीदेगा और swap अवधि समाप्त

होने पर उतनी ही राशि वापस बेचने पर सहमत होगा।

• The minimum bid size for the auction is USD 10 million, and bids can thereafter be placed in multiples of USD 1 million.

• नीलामी के लिए न्यूनतम बोली राशि USD 10 मिलियन होगी और इसके बाद USD 1 मिलियन के गुणकों में बोली लगाई जा सकेगी।

Ques: Which Indian FinTech company launched "Atlas", an AI-native lending infrastructure platform aimed at reducing loan processing timelines?

प्रश्न: किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने "Atlas" नामक AI-आधारित लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ऋण प्रसंस्करण समय को कम करना है?

A) FinBox / फिनबॉक्स

B) Razorpay / रेज़रपे

C) Paytm / पेटीएम

D) CRED / क्रेड

E) PhonePe / फोनपे

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Indian FinTech company FinBox launched "Atlas", an AI-native lending infrastructure platform.

• भारतीय फिनटेक कंपनी FinBox ने "Atlas" नामक AI-आधारित लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

• The platform is designed to significantly reduce loan processing timelines and improve borrower completion rates.

• यह प्लेटफॉर्म ऋण प्रसंस्करण समय को काफी कम करने और उधारकर्ताओं की आवेदन पूर्णता दर को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

• According to the company, Atlas can reduce loan processing timelines from

nearly three weeks to just 24 hours.

• कंपनी के अनुसार, Atlas ऋण प्रसंस्करण समय को लगभग तीन सप्ताह से घटाकर केवल 24 घंटे कर सकता है।

• FinBox stated that nearly 70% of loan applications drop off before completion in many cases.

• FinBox के अनुसार, कई मामलों में लगभग 70% ऋण आवेदन पूरे होने से पहले ही रुक जाते हैं।

• The AI-driven system aims to streamline digital lending and enhance customer experience in the financial sector.

• यह AI-आधारित प्रणाली डिजिटल लेंडिंग को सरल बनाने और वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक अनुभव को बेहतर करने का लक्ष्य रखती है।

Ques: Which payments app recorded a 301% growth in transaction volumes during Financial Year 2025–26?

प्रश्न: वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान किस भुगतान ऐप ने लेनदेन की मात्रा में 301% वृद्धि दर्ज की?

A) PhonePe / फोनपे

B) Google Pay / गूगल पे

C) Paytm / पेटीएम

D) BHIM / भीम

E) Amazon Pay / अमेज़न पे

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The BHIM Payments App recorded a massive 301% growth in transaction volumes during Financial Year 2025–26.

• BHIM Payments App ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में लेनदेन की मात्रा में 301% की बड़ी वृद्धि दर्ज की।

• The data was released by NPCI BHIM Services Limited (NBSL).
• यह आंकड़े NPCI BHIM Services Limited (NBSL) द्वारा जारी किए गए।
• Monthly transactions on the BHIM app increased from 5.93 crore in April 2025 to 21.6 crore in March 2026.
• BHIM ऐप पर मासिक लेनदेन अप्रैल 2025 के 5.93 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में 21.6 करोड़ हो गए।
• In April 2026 alone, the app recorded 22.49 crore transactions worth ₹26,040 crore.
• केवल अप्रैल 2026 में ही ऐप पर 22.49 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल राशि ₹26,040 करोड़ थी।
• BHIM stands for Bharat Interface for Money and is a UPI-based digital payment application.
• BHIM का पूर्ण रूप Bharat Interface for Money है और यह UPI आधारित डिजिटल भुगतान ऐप है।
• The app is managed by NPCI BHIM Services Limited (NBSL), a wholly owned subsidiary of NPCI.
• इस ऐप का संचालन NPCI BHIM Services Limited (NBSL) द्वारा किया जाता है, जो NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• BHIM Full Form – Bharat Interface for Money
• BHIM का पूर्ण रूप – भारत इंटरफेस फॉर मनी
• NPCI Full Form – National Payments Corporation of India
• NPCI का पूर्ण रूप – नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
• NPCI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• NPCI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• NPCI BHIM Services Limited (NBSL) Established – 2024
• NPCI BHIM Services Limited (NBSL) की स्थापना – 2024
• NBSL Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• NBSL मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• UPI Full Form – Unified Payments Interface
• UPI का पूर्ण रूप – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस

Ques: Emirates NBD launched an open offer to acquire what percentage stake in RBL Bank?

प्रश्न: एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया है?

A) 15%
B) 20%
C) 26%
D) 30%
E) 49%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Emirates NBD Bank announced an open offer to acquire up to 26% stake in RBL Bank.
• एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने आरबीएल बैंक में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की।
• The bank plans to acquire 415.59 million equity shares of RBL Bank.
• बैंक आरबीएल बैंक के 415.59 मिलियन इक्विटी शेयर खरीदने की योजना बना रहा है।
• The offer price has been fixed at ₹282.38 per equity share.
• प्रति इक्विटी शेयर ऑफर मूल्य ₹282.38 निर्धारित किया गया है।
• The total acquisition value is estimated at around ₹11,735 crore.
• इस अधिग्रहण का कुल मूल्य लगभग ₹11,735 करोड़ आंका गया है।
• The acquisition will be completed entirely through cash payment.
• यह अधिग्रहण पूरी तरह नकद भुगतान के माध्यम से किया जाएगा।
• Emirates NBD has received all necessary regulatory and government approvals for the deal.
• एमिरेट्स एनबीडी को इस सौदे के लिए सभी आवश्यक नियामकीय और सरकारी मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं।
• The investment of around $3 billion is considered one of the largest equity fund raises in the Indian banking sector.

• लगभग 3 बिलियन डॉलर का यह निवेश भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े इक्विटी फंड जुटाव में से एक माना जा रहा है।
• It is also the first acquisition of a majority stake in a profitable Indian bank by a foreign banking institution.
• यह किसी विदेशी बैंकिंग संस्था द्वारा लाभकारी भारतीय बैंक में बहुमत हिस्सेदारी का पहला अधिग्रहण है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Emirates NBD Foundation Year – 1963
• एमिरेट्स एनबीडी की स्थापना – 1963
• Headquarters – Dubai, UAE
• मुख्यालय – दुबई, यूएई
• CEO – Shayne Nelson
• सीईओ – Shayne Nelson
• RBL Bank Foundation Year – 1943
• आरबीएल बैंक की स्थापना – 1943
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• MD & CEO – R. Subramaniakumar
• एमडी एवं सीईओ – आर. सुब्रमणियाकुमार
• Tagline – Apno Ka Bank
• टैगलाइन – Apno Ka Bank

Ques: RAINMUMBAI, India's first exchange-traded weather derivatives contract, has been launched by which organization?
प्रश्न: भारत का पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट RAINMUMBAI किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?

A) NSE / एनएसई
B) BSE / बीएसई
C) NCDEX / एनसीडीईएक्स

D) RBI / आरबीआई

E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) will launch RAINMUMBAI on May 29, 2026.

• नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) 29 मई 2026 को RAINMUMBAI लॉन्च करेगा।

• RAINMUMBAI is India's first exchange-traded weather derivatives contract.

• RAINMUMBAI भारत का पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है।

• The contract has received approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

• इस कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी प्राप्त हुई है।

• The product has been developed in collaboration with IIT Bombay.

• इस उत्पाद को IIT बॉम्बे के सहयोग से विकसित किया गया है।

• Rainfall data from the India Meteorological Department (IMD) will be used for the contract.

• इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वर्षा आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

• The instrument aims to help businesses and farmers hedge against monsoon variability and weather-related losses.

• यह साधन व्यवसायों और किसानों को मानसून की अनिश्चितता एवं मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा।

• IMD weather stations at Santacruz and Colaba in Mumbai will provide rainfall observations.

• मुंबई के सांताक्रूज़ और कोलाबा स्थित IMD मौसम केंद्र वर्षा संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराएंगे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Organization – NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange)

• संगठन – NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज)
• NCDEX Established – 2003
• NCDEX की स्थापना – 2003
• NCDEX Headquarters – Mumbai
• NCDEX मुख्यालय – Mumbai
• Managing Director & CEO – Arun Raste
• प्रबंध निदेशक एवं CEO – Arun Raste

Ques: The Government of India increased stake dilution in which bank up to 8% through OFS?

प्रश्न: भारत सरकार ने किस बैंक में OFS के माध्यम से हिस्सेदारी बिक्री को 8% तक बढ़ाया है?

A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

C) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

D) Indian Bank / इंडियन बैंक

E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India increased stake dilution in Central Bank of India up to 8% through Offer for Sale (OFS).
• भारत सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बिक्री को 8% तक बढ़ाया।
• The OFS received strong institutional investor demand and was oversubscribed 2.35 times on Day 1.
• OFS को संस्थागत निवेशकों से मजबूत मांग मिली और पहले दिन यह 2.35 गुना सब्सक्राइब हुआ।

• The Centre exercised the entire greenshoe option due to high investor response.

• निवेशकों की अधिक रुचि के कारण केंद्र सरकार ने पूरा ग्रीनशू विकल्प लागू किया।

• The government aims to raise around ₹2,456 crore through the stake sale.

• सरकार का लक्ष्य इस हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से लगभग ₹2,456 करोड़ जुटाना है।

• The OFS is intended to help the bank comply with SEBI's minimum public shareholding norm of 25%.

• यह OFS बैंक को सेबी के 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम का पालन कराने के उद्देश्य से किया गया है।

• After the stake sale, the government's holding in Central Bank of India will reduce from 89.27% to around 81.27%.

• हिस्सेदारी बिक्री के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 89.27% से घटकर लगभग 81.27% रह जाएगी।

• The floor price for the OFS was fixed at ₹31 per share.

• OFS के लिए न्यूनतम मूल्य ₹31 प्रति शेयर निर्धारित किया गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Central Bank of India Foundation Year – 1911

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष – 1911

• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• MD & CEO – Shri Kalyan Kumar

• एमडी एवं सीईओ – श्री कल्याण कुमार

• Tagline – Central to you since 1911

• टैगलाइन – Central to you since 1911

Ques: What was the growth rate recorded by India's eight core infrastructure sectors in April 2026?

प्रश्न: अप्रैल 2026 में भारत के आठ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों ने कितनी वृद्धि दर्ज की?

A) 1.7%

B) 2.5%

C) 3.2%
D) 4.1%
E) 5.0%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• India's eight core infrastructure sectors recorded 1.7% growth in April 2026.
• भारत के आठ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों ने अप्रैल 2026 में 1.7% की वृद्धि दर्ज की।
• The data was released by the Ministry of Commerce and Industry.
• यह आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
• Among the core sectors, Cement, Steel, and Electricity registered positive growth.
• प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
• The eight core industries include Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement, and Electricity.
• आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं।
• These industries are considered crucial indicators of industrial and economic activity in India.
• इन उद्योगों को भारत की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।
• The eight core industries together account for 40.27% weight in the Index of Industrial Production (IIP).
• ये आठ प्रमुख उद्योग मिलकर Index of Industrial Production (IIP) में 40.27% भार रखते हैं।

Ques: For which financial year did RBI approve a record surplus transfer of Rs. 2.87 lakh crore to the Central Government?
प्रश्न: RBI ने केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को किस वित्त वर्ष के लिए मंजूरी दी?

A) FY 2023-24 / वित्त वर्ष 2023-24

B) FY 2024-25 / वित्त वर्ष 2024-25

C) FY 2025-26 / वित्त वर्ष 2025-26

D) FY 2026-27 / वित्त वर्ष 2026-27

E) FY 2022-23 / वित्त वर्ष 2022-23

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) approved a surplus transfer of Rs. 2.87 lakh crore to the Central Government for FY 2025-26.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी।

• The total surplus transferred amounts to Rs. 2,86,588.46 crore.

• कुल अधिशेष हस्तांतरण राशि 2,86,588.46 करोड़ रुपये है।

• The dividend amount is around 6.7% higher than the Rs. 2.69 lakh crore transferred in FY25.

• यह लाभांश राशि FY25 में हस्तांतरित 2.69 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 6.7% अधिक है।

• RBI's gross income increased by 26.42% year-on-year to Rs. 3.96 lakh crore.

• RBI की सकल आय वर्ष-दर-वर्ष 26.42% बढ़कर 3.96 लाख करोड़ रुपये हो गई।

• The balance sheet of RBI expanded by 20.61% to Rs. 91.97 lakh crore.

• RBI की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये हो गई।

• The surplus transfer strengthens the government's fiscal position and supports public expenditure.

• यह अधिशेष हस्तांतरण सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करता है और सार्वजनिक व्यय को समर्थन देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Established – 1 April 1935

• RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Nationalised – 1 January 1949
• राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

Ques: According to the latest UN report, India's revised GDP growth forecast for 2026 is what percentage?

प्रश्न: नवीनतम संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2026 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि rate कितनी है?

A) 5.8%
B) 6.0%
C) 6.4%
D) 6.6%
E) 7.0%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The United Nations revised India's 2026 economic growth forecast downward to 6.4% from 6.6%.
• संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2026 आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है।
• The downgrade was announced in a report released by UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).
• यह कटौती UN DESA (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग) की रिपोर्ट में की गई है।
• The revision was due to global uncertainties and economic shocks arising from the ongoing West Asia crisis.

• यह संशोधन वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न आर्थिक झटकों के कारण किया गया है।

• Despite the cut, India remains one of the fastest-growing major economies in the world.

• कटौती के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है।

• The report stated that the West Asia crisis has slowed global growth and increased inflationary pressures.

• रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक विकास को धीमा किया है और मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• UN Full Form – United Nations
• UN का पूर्ण रूप – संयुक्त राष्ट्र
• UN Founded Day – 24 October 1945
• संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस – 24 अक्टूबर 1945
• UN Headquarters – New York, USA
• संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय – न्यूयॉर्क, अमेरिका
• UN Secretary-General – António Guterres
• संयुक्त राष्ट्र महासचिव – António Guterres

Ques: Which two institutions signed an MoU to strengthen corporate governance, ESG, and capital market development in India?

प्रश्न: भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG और पूंजी बाजार विकास को मजबूत करने हेतु किन दो संस्थानों ने MoU पर हस्ताक्षर किए?

A) RBI and SEBI / RBI और SEBI

B) NISM and IICA / NISM और IICA

C) NABARD and SIDBI / NABARD और SIDBI

D) NSE and BSE / NSE और BSE

E) IIM Ahmedabad and NITI Aayog / IIM अहमदाबाद और नीति आयोग

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• National Institute of Securities Markets (NISM) and Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) signed a Memorandum of Understanding (MoU).

• National Institute of Securities Markets (NISM) और Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) ने एक Memorandum of Understanding (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• The partnership aims to strengthen corporate governance, ESG, and capital market development in India.

• इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG और पूंजी बाजार विकास को मजबूत करना है।

• NISM was established by SEBI, while IICA functions under the Ministry of Corporate Affairs.

• NISM की स्थापना SEBI द्वारा की गई थी, जबकि IICA, Ministry of Corporate Affairs के अंतर्गत कार्य करता है।

• Under the collaboration, both institutions will jointly conduct capacity building programmes and certification courses.

• इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रमाणन पाठ्यक्रम संचालित करेंगे।

• They will also develop executive education modules and training programmes.

• वे कार्यकारी शिक्षा मॉड्यूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित करेंगे।

• The programmes are aimed at SEBI officers, regulatory officials, and financial sector professionals.

• ये कार्यक्रम SEBI अधिकारियों, नियामक अधिकारियों और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों के लिए होंगे।

• ESG refers to Environmental, Social, and Governance standards used to evaluate sustainable business practices.

• ESG का अर्थ Environmental, Social, and Governance है, जिसका उपयोग सतत

व्यावसायिक प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NISM Full Form – National Institute of Securities Markets
- NISM का पूर्ण रूप – National Institute of Securities Markets
- NISM Established – 2006
- NISM की स्थापना – 2006
- NISM Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- NISM मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- IICA Full Form – Indian Institute of Corporate Affairs
- IICA का पूर्ण रूप – Indian Institute of Corporate Affairs
- IICA Formed – 2008
- IICA की स्थापना – 2008
- IICA Headquarters – Gurugram, Haryana
- IICA मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा

Ques: Net FDI into India increased to how much in FY26 according to RBI data?

प्रश्न: RBI के अनुसार FY26 में भारत में शुद्ध FDI बढ़कर कितना हो गया?

A) $3.40 billion / 3.40 बिलियन डॉलर

B) $5.20 billion / 5.20 बिलियन डॉलर

C) $7.65 billion / 7.65 बिलियन डॉलर

D) $10.12 billion / 10.12 बिलियन डॉलर

E) $40.95 billion / 40.95 बिलियन डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Net foreign direct investment (FDI) into India rose sharply to $7.65 billion in FY26.

• भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) FY26 में बढ़कर 7.65 बिलियन डॉलर हो गया।

• Net FDI had stood at $959 million in FY25.

• FY25 में शुद्ध FDI 959 मिलियन डॉलर था।

• March marked the second consecutive month of positive net inflows at $1.57 billion.

• मार्च लगातार दूसरा महीना रहा जब शुद्ध प्रवाह सकारात्मक रहा और यह 1.57 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया।

• Net FDI had turned positive in February after remaining negative for six consecutive months.

• लगातार छह महीनों तक नकारात्मक रहने के after फरवरी में शुद्ध FDI सकारात्मक हुआ।

• Net inflows stood at $4.44 billion in February.

• फरवरी में शुद्ध निवेश प्रवाह 4.44 बिलियन डॉलर रहा।

• Gross inward FDI into India increased to $40.95 billion in FY26.

• FY26 में भारत में सकल inward FDI बढ़कर 40.95 बिलियन डॉलर हो गया।

• Equity inflows rose to $62.28 billion during the year.

• वर्ष के दौरान इक्विटी निवेश बढ़कर 62.28 बिलियन डॉलर हो गया।

• Reinvested earnings increased to $25.56 billion.

• पुनर्निवेशित आय बढ़कर 25.56 बिलियन डॉलर हो गई।

• Direct investment abroad by Indian firms rose to $33.29 billion.

• भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश बढ़कर 33.29 बिलियन डॉलर हो गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• FDI Full Form – Foreign Direct Investment

• FDI का पूर्ण रूप – Foreign Direct Investment

• RBI Headquarters – Mumbai

• RBI मुख्यालय – मुंबई

• RBI Governor – Sanjay Malhotra

• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

• Finance Minister – Nirmala Sitharaman
• वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण

Ques: Why did the Reserve Bank of India (RBI) impose a monetary penalty on City Union Bank?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने City Union Bank पर मौद्रिक जुर्माना क्यों लगाया?

A) Failure to maintain CRR / CRR बनाए रखने में विफलता

B) Violation of foreign exchange rules / विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

C) Levying charges on certain agricultural loans and failure to report SHG data / कुछ कृषि ऋणों पर शुल्क लगाने और SHG डेटा रिपोर्ट न करने के कारण

D) Cybersecurity breach / साइबर सुरक्षा उल्लंघन

E) Delay in ATM services / एटीएम सेवाओं में देरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties on City Union Bank, Mintifi Finserve, and Newa Investments for regulatory violations.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय उल्लंघनों के कारण City Union Bank, Mintifi Finserve और Newa Investments पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।

• City Union Bank was fined ₹10.10 lakh.

• City Union Bank पर ₹10.10 लाख का जुर्माना लगाया गया।

• The bank levied loan-related charges on certain agricultural loans up to ₹25,000 that qualified under Priority Sector Lending (PSL).

• बैंक ने Priority Sector Lending (PSL) के अंतर्गत आने वाले ₹25,000 तक के कुछ कृषि ऋणों पर ऋण-संबंधी शुल्क लगाया।

• The bank also failed to report Self-Help Group (SHG) member-level data to credit information companies.

• बैंक SHG सदस्यों के स्तर का डेटा क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने में भी विफल

रहा।

• RBI imposed a penalty of ₹3.10 lakh on Mintifi Finserve for not uploading KYC records to the Central KYC Records Registry within the prescribed timeline.

• RBI ने Mintifi Finserve पर निर्धारित समयसीमा के भीतर Central KYC Records Registry में KYC रिकॉर्ड अपलोड न करने के कारण ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया।

• Newa Investments was fined ₹2.70 lakh for appointing directors without prior written approval from RBI.

• Newa Investments पर RBI की पूर्व लिखित अनुमति के बिना निदेशकों की नियुक्ति करने के कारण ₹2.70 लाख का जुर्माना लगाया गया।

• RBI imposes penalties to ensure compliance with banking and financial regulations.

• RBI बैंकिंग और वित्तीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लगाता है।

Ques: How much final dividend per equity share was declared by LIC for FY26?

प्रश्न: FY26 के लिए LIC ने प्रति इक्विटी शेयर कितना अंतिम लाभांश घोषित किया?

A) ₹5
B) ₹8
C) ₹10
D) ₹12
E) ₹15

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) reported over 23% year-on-year growth in Q4 net profit.

• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने चौथी तिमाही के शुद्ध लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 23% से अधिक वृद्धि दर्ज की।

• LIC's consolidated net profit rose to ₹23,467 crore in Q4 FY26.

• Q4 FY26 में LIC का समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर ₹23,467 करोड़ हो गया।
• The net profit stood at ₹19,039 crore in the same quarter of the previous year.
• पिछले वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ ₹19,039 करोड़ था।
• LIC's standalone net profit climbed to ₹23,420.43 crore in the March-ended quarter.
• मार्च तिमाही में LIC का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ बढ़कर ₹23,420.43 करोड़ हो गया।
• Total income increased by over 14% to ₹2,76,827.17 crore.
• कुल आय 14% से अधिक बढ़कर ₹2,76,827.17 करोड़ हो गई।
• Net premium income stood at ₹1,64,691.21 crore during the quarter.
• तिमाही के दौरान शुद्ध प्रीमियम आय ₹1,64,691.21 करोड़ रही।
• Income from investments increased to ₹1,09,022.04 crore.
• निवेश से आय बढ़कर ₹1,09,022.04 करोड़ हो गई।
• LIC declared a final dividend of ₹10 per equity share.
• LIC ने प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अंतिम लाभांश की घोषणा की।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• LIC Established – 1 September 1956
• LIC की स्थापना – 1 सितंबर 1956
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Chairperson & MD – R. Doraiswamy
• चेयरपर्सन एवं एमडी – आर. डोराइस्वामी
• Tagline – "Yogakshemam Vahamyaham"
• टैगलाइन – "योगक्षेमं वहाम्यहम्"

Ques: Which organisation has been selected as the fund manager for the ₹20,000-crore Maritime Investment Fund (MIF)?

प्रश्न: ₹20,000 करोड़ के Maritime Investment Fund (MIF) के फंड मैनेजर के रूप में किस संगठन का चयन किया गया है?

A) LIC Housing Finance / एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस

B) SBI Ventures / एसबीआई वेंचर्स

C) NABARD / नाबार्ड

D) SIDBI / सिडबी

E) IFCI / आईएफसीआई

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India selected SBI Ventures as the fund manager for the ₹20,000-crore Maritime Investment Fund (MIF).

• भारत सरकार ने ₹20,000 करोड़ के Maritime Investment Fund (MIF) के फंड मैनेजर के रूप में SBI Ventures का चयन किया।

• The fund aims to promote investment in India's maritime sector.

• इस फंड का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।

• The Maritime Investment Fund is a major component of the ₹25,000-crore Maritime Development Fund approved by the Union Cabinet.

• Maritime Investment Fund, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹25,000 करोड़ के Maritime Development Fund का प्रमुख हिस्सा है।

• The Central Government will contribute ₹9,800 crore, which is 49% of the total corpus.

• केंद्र सरकार कुल कोष का 49% यानी ₹9,800 करोड़ का योगदान देगी।

• The remaining 51% will be mobilised from private investors, sovereign wealth funds, institutional investors, CPSEs, PSUs, and major port authorities.

• शेष 51% राशि निजी निवेशकों, sovereign wealth funds, institutional investors, CPSEs, PSUs और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों से जुटाई जाएगी।

• The fund will follow a blended finance model.

• यह फंड blended finance model के आधार पर संचालित होगा।

• The fund will be registered as a closed-end Category I/II Alternative Investment Fund (AIF) under SEBI.

• यह फंड SEBI के अंतर्गत closed-end Category I/II Alternative Investment Fund (AIF) के रूप में पंजीकृत होगा।

Ques: Who has been appointed as Executive Director for Vertical 2 at CDSL?
प्रश्न: CDSL में वर्टिकल 2 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है?

A) Amit Mahajan / अमित महाजन

B) Nehal Vora / नेहल वोरा

C) Nayana Ovalekar / नयना ओवलेकर

D) Tuhin Kanta Pandey / तुहिन कांत पांडेय

E) Ajay Tyagi / अजय त्यागी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) approved the appointment of two new Executive Directors at CDSL.

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने CDSL में दो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति को मंजूरी दी।

• Amit Mahajan was appointed as Executive Director for Vertical 1.

• अमित महाजन को वर्टिकल 1 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया।

• He will oversee critical operations under Vertical 1.

• वे वर्टिकल 1 के अंतर्गत महत्वपूर्ण संचालन कार्यों की देखरेख करेंगे।

• Nayana Ovalekar was appointed as Executive Director for Vertical 2.

• नयना ओवलेकर को वर्टिकल 2 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया।

• She will handle regulatory, compliance, risk management and investor grievances.

• वे रेगुलेटरी, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट तथा निवेशक शिकायतों की जिम्मेदारी संभालेंगी।

• The appointments will become effective after shareholder ratification and joining formalities.

• ये नियुक्तियाँ शेयरधारकों की मंजूरी और जॉइनिंग प्रक्रिया के बाद प्रभावी होंगी।

• CDSL shares closed at ₹1,217.40 on NSE, up by 1.10%.

• NSE पर CDSL का शेयर ₹1,217.40 पर बंद हुआ, जिसमें 1.10% की बढ़त दर्ज की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SEBI Established – 12 April 1992
- SEBI की स्थापना – 12 अप्रैल 1992
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय
- CDSL Founded – 1999
- CDSL की स्थापना – 1999
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – Nehal Vora
- MD एवं CEO – नेहल वोरा
- CDSL Full Form – Central Depository Services (India) Limited
- CDSL का पूर्ण रूप – सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

Ques: Under whose chairmanship was the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (RBI) held?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई?

A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास

B) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

C) Ajay Seth / अजय सेठ

D) T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर

E) M. Rajeshwar Rao / एम. राजेश्वर राव

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The 623rd meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (RBI) was held in Mumbai.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक मुंबई में आयोजित हुई।

• The meeting was held under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra.

• यह बैठक RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

• RBI's gross income increased by 26.42% during Financial Year 2025–26.

• वित्त वर्ष 2025–26 में RBI की सकल आय में 26.42% की वृद्धि हुई।

• Expenditure before risk provisions rose by 27.60% during the same period.

• इसी अवधि में जोखिम प्रावधानों से पूर्व व्यय में 27.60% की वृद्धि हुई।

• Net income before risk provisions and transfer to statutory funds stood at ₹3.95 lakh crore in FY 2025–26.

• जोखिम प्रावधानों और वैधानिक निधियों में हस्तांतरण से पूर्व शुद्ध आय FY 2025–26 में ₹3.95 लाख करोड़ रही।

• In FY 2024–25, the corresponding figure was ₹3.13 lakh crore.

• FY 2024–25 में यह आंकड़ा ₹3.13 लाख करोड़ था।

• RBI's balance sheet expanded by 20.61% to ₹91.97 lakh crore as of March 31, 2026.

• 31 मार्च 2026 तक RBI की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर ₹91.97 लाख करोड़ हो गई।

Ques : What is the new base year for the revised Index of Industrial Production (IIP) series launched by MoSPI?

प्रश्न: MoSPI द्वारा शुरू की गई संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या है?

A) 2015-16
B) 2018-19
C) 2020-21
D) 2022-23
E) 2023-24

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) will launch a revamped Index of Industrial Production (IIP) series from June 1.

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 1 जून से संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) श्रृंखला शुरू करेगा।

• The new IIP series uses 2022-23 as the base year, replacing the old 2011-12 base year.

• नई IIP श्रृंखला में 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया है, जो पुराने 2011-12 आधार वर्ष का स्थान लेगा।

• For the first time, the index will include rare earth minerals and expanded gas supply coverage.

• पहली बार इस सूचकांक में रेयर अर्थ मिनरल्स और विस्तारित गैस आपूर्ति को शामिल किया गया है।

• The revised series aims to better reflect India's modern industrial and green-energy economy.

• संशोधित श्रृंखला का उद्देश्य भारत की आधुनिक औद्योगिक एवं हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना है।

• The updated item basket includes 1,042 products mapped into 463 item groups.

• अद्यतन आइटम बास्केट में 1,042 उत्पादों को 463 आइटम समूहों में शामिल किया गया है।

• Electricity generation has been divided into renewable and non-renewable categories in the new series.

• नई श्रृंखला में बिजली उत्पादन को नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

• The revised IIP series aligns with the National Industrial Classification (NIC-2025).

• संशोधित IIP श्रृंखला को राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC-2025) के अनुरूप बनाया गया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry – Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)
- मंत्रालय – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- Current Union Minister – Rao Inderjit Singh (MoS Independent Charge)
- वर्तमान केंद्रीय मंत्री – राव इंद्रजीत सिंह (स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री)
- Base Year of Old IIP Series – 2011-12
- पुरानी IIP श्रृंखला का आधार वर्ष – 2011-12
- New Base Year of IIP Series – 2022-23
- नई IIP श्रृंखला का आधार वर्ष – 2022-23

Ques: Which FinTech company received approval to operate as a Payment Service Provider (PSP) at GIFT City?

प्रश्न: किस फिनटेक कंपनी को GIFT City में Payment Service Provider (PSP) के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है?

A) Razorpay / रेजरपे

B) Paytm / पेटीएम

C) Skydo / स्काइडो

D) Pine Labs / पाइन लैब्स

E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- FinTech company Skydo received approval to operate as a Payment Service Provider (PSP) at GIFT City.
- फिनटेक कंपनी Skydo को GIFT City में Payment Service Provider (PSP) के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है।
- GIFT City is India's international financial services hub.

• GIFT City भारत का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।

• Skydo will now offer services such as multi-currency payments, international money transfers, global payment collections, and e-money accounts.

• Skydo अब multi-currency payments, international money transfers, global payment collections और e-money accounts जैसी सेवाएँ प्रदान करेगा।

• The company also received RBI approval under the Payment Aggregator-Cross Border (PA-CB) framework for outward international payments.

• कंपनी को outward international payments के लिए RBI से Payment Aggregator-Cross Border (PA-CB) framework के तहत भी मंजूरी मिली है।

• Earlier, Skydo had already received approval for collecting export payments from foreign customers.

• इससे पहले Skydo को विदेशी ग्राहकों से export payments एकत्र करने की अनुमति मिल चुकी थी।

• The approvals strengthen India's digital cross-border payment ecosystem.

• ये मंजूरियाँ भारत के डिजिटल cross-border payment ecosystem को मजबूत करती हैं।

Ques : West Bengal Gramin Bank signed a bancassurance deal with which insurance company?

प्रश्न: पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ बैंकएश्योरेंस समझौता किया?

A) LIC Housing Finance / एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस

B) SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस

C) HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस

D) Canara HSBC Life Insurance / कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस

E) ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• West Bengal Gramin Bank (WBGB) signed a bancassurance partnership with Canara HSBC Life Insurance.

• पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक (WBGB) ने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकएश्योरेंस साझेदारी की।

• The partnership aims to provide life, term, and investment insurance products to customers.

• इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों को जीवन, टर्म और निवेश बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना है।

• Canara HSBC Life Insurance products will be distributed through WBGB's network of 960 branches.

• कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के उत्पाद WBGB की 960 शाखाओं के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

• The initiative focuses on expanding insurance coverage in rural and semi-urban areas of West Bengal.

• यह पहल पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बीमा कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है।

• The agreement will improve financial inclusion and insurance accessibility for customers.

• यह समझौता ग्राहकों के लिए वित्तीय समावेशन और बीमा सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• West Bengal Gramin Bank Headquarters – Murshidabad, West Bengal

• पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक मुख्यालय – मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

• Canara HSBC Life Insurance Founded – 2008

• कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस स्थापना – 2008

• Headquarters of Canara HSBC Life Insurance – Gurugram, Haryana

• कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा

• Tagline of Canara Bank – "Together We Can"

• कैनरा बैंक की टैगलाइन – "Together We Can"

Ques: Which mutual fund house increased its stake in Bandhan Bank to more than 5% of the bank's paid-up share capital?

प्रश्न: किस म्यूचुअल फंड हाउस ने Bandhan Bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर बैंक की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) का 5% से अधिक कर लिया?

A) HDFC Mutual Fund / एचडीएफसी म्यूचुअल फंड

B) ICICI Prudential Mutual Fund / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड

C) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड

D) Nippon India Mutual Fund / निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड

E) Axis Mutual Fund / एक्सिस म्यूचुअल फंड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SBI Mutual Fund increased its stake in Bandhan Bank and now holds more than 5% of the bank's paid-up share capital.

• SBI Mutual Fund ने Bandhan Bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और अब उसके पास बैंक की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) का 5% से अधिक हिस्सा है।

• Before the purchase, SBI Mutual Fund held a 4.9378% stake in the bank.

• खरीद से पहले SBI Mutual Fund के पास बैंक में 4.9378% हिस्सेदारी थी।

• SBI Mutual Fund is India's largest mutual fund house by Assets Under Management (AUM).

• SBI Mutual Fund, Assets Under Management (AUM) के आधार पर भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है।

• Paid-up share capital refers to the total value of shares issued by a company and fully paid by shareholders.

• Paid-up share capital का अर्थ कंपनी द्वारा जारी किए गए और शेयरधारकों द्वारा पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों के कुल मूल्य से है।

• Assets Under Management (AUM) refers to the total cumulative investment managed by a mutual fund.

• Assets Under Management (AUM) का अर्थ किसी म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित कुल निवेश राशि से है।

• Increasing stake in a bank reflects investor confidence in the institution's future growth potential.

• किसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाना उस संस्था की भविष्य की विकास क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

Ques: What was the total inflow into NRI deposit schemes in FY26?
प्रश्न: FY26 में NRI जमा योजनाओं में कुल प्रवाह कितना था?

A) $10.41 billion / $10.41 बिलियन

B) $12.75 billion / $12.75 बिलियन

C) $14.41 billion / $14.41 बिलियन

D) $16.16 billion / $16.16 बिलियन

E) $18.25 billion / $18.25 बिलियन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Inflows into Non-Resident Indian (NRI) deposit schemes moderated to $14.41 billion in FY26.

• FY26 में अनिवासी भारतीय (NRI) जमा योजनाओं में प्रवाह घटकर $14.41 बिलियन रह गया।

• In FY25, NRI deposit inflows were $16.16 billion.

• FY25 में NRI जमा प्रवाह $16.16 बिलियन था।

• Outstanding NRI deposits stood at $165.65 billion at the end of March 2026.

• मार्च 2026 के अंत तक कुल NRI जमा $165.65 बिलियन रहा।

• FCNR(B) deposits recorded inflows of only $946 million in FY26.

• FY26 में FCNR(B) जमा में केवल $946 मिलियन का प्रवाह दर्ज किया गया।

• NR(E)RA deposits saw inflows of $7.94 billion during FY26.

• FY26 के दौरान NR(E)RA जमा में $7.94 बिलियन का प्रवाह हुआ।

• NRO deposits recorded inflows of $5.53 billion in FY26.

• FY26 में NRO जमा में $5.53 बिलियन का प्रवाह दर्ज किया गया।
• The data was released by the Reserve Bank of India (RBI).
• यह आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए।
• The moderation in inflows was mainly due to weaker demand for FCNR(B) deposits.
• प्रवाह में कमी मुख्य रूप से FCNR(B) जमा की मांग कमजोर होने के कारण हुई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Establishment – 1 April 1935
• RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• Headquarter – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• RBI Nationalisation – 1 January 1949
• RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
• NRI Full Form – Non-Resident Indian
• NRI का पूर्ण रूप – अनिवासी भारतीय
• FCNR(B) Full Form – Foreign Currency Non-Resident (Bank)
• FCNR(B) का पूर्ण रूप – फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक)
• NRO Full Form – Non-Resident Ordinary Account
• NRO का पूर्ण रूप – नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट

Ques: According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, what do the "3Fs" refer to?

प्रश्न: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार "3Fs" का क्या अर्थ है?

A) Food, Farming, Finance / फूड, फार्मिंग, फाइनेंस

B) Fuel, Fertiliser, Foreign Exchange / ईंधन, उर्वरक, विदेशी मुद्रा

C) Fuel, Farming, Forex / ईंधन, कृषि, फॉरेक्स

D) Finance, Fertiliser, Freight / वित्त, उर्वरक, माल परिवहन

E) Food, Fuel, Freight / भोजन, ईंधन, माल परिवहन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Union Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted "3Fs" — Fuel, Fertiliser and Foreign Exchange — as major external challenges for India's economy.

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "3Fs" — ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा — को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख बाहरी चुनौतियाँ बताया।

• She said the ongoing West Asia crisis is creating uncertainties for businesses and common people.

• उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट व्यवसायों और आम लोगों के for अनिश्चितताएँ पैदा कर रहा है।

• Rising crude oil, fertiliser and gold prices are putting pressure on India's foreign exchange reserves.

• कच्चे तेल, उर्वरक और सोने की बढ़ती कीमतें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रही हैं।

• Sitharaman stated that delayed cargo movement and higher shipping costs are affecting businesses.

• सीतारमण ने कहा कि कार्गो में देरी और बढ़ती शिपिंग लागत व्यवसायों को प्रभावित कर रही है।

• She emphasized that India's economic fundamentals remain strong and resilient.

• उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत और लचीली बनी हुई है।

• Petrol prices increased by ₹2.61 per litre and diesel prices by ₹2.71 per litre recently.

• हाल ही में पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ी।

• The Finance Minister appealed against "fear-mongering" and stressed maintaining public confidence.

• वित्त मंत्री ने "भय फैलाने" से बचने की अपील की और जनता का विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry of Finance Established – 29 October 1946
- वित्त मंत्रालय की स्थापना – 29 अक्टूबर 1946
- Headquarter – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Union Finance Minister – Nirmala Sitharaman
- केंद्रीय वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण
- Foreign Exchange Reserves managed by – RBI
- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन – RBI द्वारा
- RBI Headquarter – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: For how many years has RBI approved the re-appointment of Sandeep Bakshi as MD & CEO of ICICI Bank?

प्रश्न: RBI ने संदीप बख्शी की ICICI बैंक के MD एवं CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति कितने वर्षों के लिए मंजूर की है?

A) 1 year / 1 वर्ष

B) 2 years / 2 वर्ष

C) 3 years / 3 वर्ष

D) 4 years / 4 वर्ष

E) 5 years / 5 वर्ष

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) approved the re-appointment of Sandeep Bakshi as MD & CEO of ICICI Bank.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संदीप बख्शी की ICICI बैंक के MD एवं CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी।

• Sandeep Bakshi has been re-appointed for another two years from October 4, 2026.

• संदीप बख्शी को 4 अक्टूबर 2026 से अगले दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है।

• Following the announcement, ICICI Bank shares rose over 2% on the BSE.

• इस घोषणा के बाद BSE में ICICI बैंक के शेयर 2% से अधिक बढ़ गए।

• ICICI Bank is India's second-largest private sector lender.

• ICICI बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है।

• The bank's board had approved Bakshi's re-appointment in January 2026.

• बैंक के बोर्ड ने जनवरी 2026 में बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

• Under RBI norms, a private sector bank CEO can continue till the age of 70 years.

• RBI के नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंक का CEO 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है।

• Sandeep Bakshi joined the ICICI Group in 1986.

• संदीप बख्शी 1986 में ICICI समूह में शामिल हुए थे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• ICICI Bank Founded – 1994

• ICICI बैंक की स्थापना – 1994

• Headquarter – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• MD & CEO – Sandeep Bakshi

• एमडी एवं सीईओ – संदीप बख्शी

• Tagline – Hum Hai Na, Khayal Apka

• टैगलाइन – Hum Hai Na, Khayal Apka

Ques: Under which initiative is India Post investing ₹5,800 crore to create fully digital end-to-end postal services?

प्रश्न: पूर्णतः डिजिटल एंड-टू-एंड डाक सेवाएँ विकसित करने के लिए India Post किस पहल के तहत ₹5,800 करोड़ का निवेश कर रहा है?

A) Digital Bharat Mission / डिजिटल भारत मिशन

B) Postal Connect Scheme / पोस्टल कनेक्ट योजना

C) IT 2.0 Initiative / आईटी 2.0 पहल

D) Smart Communication Programme / स्मार्ट कम्युनिकेशन प्रोग्राम

E) India Mail Digital Project / इंडिया मेल डिजिटल प्रोजेक्ट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India Post is investing ₹5,800 crore under the IT 2.0 initiative to create fully digital end-to-end postal services.

• India Post पूर्णतः डिजिटल एंड-टू-एंड डाक सेवाएँ विकसित करने के लिए IT 2.0 पहल के तहत ₹5,800 करोड़ का निवेश कर रहा है।

• India Post recorded a revenue of ₹15,373 crore during Financial Year 2025-26.

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में India Post ने ₹15,373 करोड़ का राजस्व दर्ज किया।

• This marked one of the strongest financial performances in its 170-year history.

• यह इसके 170 वर्षों के इतिहास में सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शनों में से एक रहा।

• India Post witnessed a record annual revenue increase of ₹2,100 crore during the financial year.

• इस वित्तीय वर्ष में India Post ने ₹2,100 करोड़ की रिकॉर्ड वार्षिक राजस्व वृद्धि दर्ज की।

• The IT 2.0 initiative aims to modernise postal operations through digital transformation and improved customer services.

• IT 2.0 पहल का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन और बेहतर ग्राहक सेवाओं के माध्यम से डाक संचालन का आधुनिकीकरण करना है।

• India Post plays an important role in delivering postal, financial, and logistics services across the country.

• India Post देशभर में डाक, वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• India Post Formed – 1 October 1854

• India Post की स्थापना – 1 अक्टूबर 1854

• India Post comes under the Ministry of Communications.

• India Post, संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

• India Post Headquarters – New Delhi

• India Post मुख्यालय – नई दिल्ली

• PIN Code System was introduced in India in 1972.

• भारत में PIN Code प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी।

• Full Form of PIN – Postal Index Number

• PIN का पूर्ण रूप – पोस्टल इंडेक्स नंबर

Ques : Under which initiative did RBI establish an expert committee on quantum technology?

प्रश्न: आरबीआई ने क्वांटम तकनीक पर विशेषज्ञ समिति किस पहल के तहत गठित की है?

A) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन

B) Cyber Suraksha Initiative / साइबर सुरक्षा पहल

C) Q-SAFE Initiative / Q-SAFE पहल

D) Quantum Bharat Mission / क्वांटम भारत मिशन

E) FinSecure India / फिनसिक्योर इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has constituted an eight-member expert committee under the Q-SAFE initiative.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Q-SAFE पहल के तहत आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

• Q-SAFE stands for Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem.

• Q-SAFE का पूर्ण रूप Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem है।

• The committee will study the impact of quantum technology on the financial sector and cyber security systems.

• यह समिति वित्तीय क्षेत्र एवं साइबर सुरक्षा प्रणालियों पर क्वांटम तकनीक के प्रभाव का अध्ययन करेगी।

• Dr. Anil Prabhakar, Professor at IIT Madras, has been appointed as the convener of the committee.

• IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉ. अनिल प्रभाकर को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है।

• The committee includes representatives from RBI, SBI, NPCI, MeitY, DST and cybersecurity experts.

• समिति में RBI, SBI, NPCI, MeitY, DST तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

• The initiative aims to prepare India's financial ecosystem against future quantum-related cyber threats.

• इस पहल का उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली को भविष्य के क्वांटम आधारित साइबर खतरों से सुरक्षित बनाना है।

• RBI's FinTech Department will provide secretarial support to the committee.

• आरबीआई का फिनटेक विभाग समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Established – 1 April 1935

• RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935

• Headquarter – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• Governor – Sanjay Malhotra

• गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: Who has been appointed as the chairman of the committee formed by PFRDA to explore the long-term inclusion of new asset classes in pension investments?

प्रश्न: पेंशन निवेश में नए एसेट क्लास के दीर्घकालिक समावेशन की जांच हेतु PFRDA द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?

A) Sivasubramanian Ramann / शिवसुब्रमणियन रमण

B) Narayan Ramachandran / नारायण रामचंद्रन

C) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

D) Deepak Mohanty / दीपक मोहंती

E) Amitabh Kant / अमिताभ कांत

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) formed a committee to explore the long-term inclusion of new asset classes in pension investments.

• पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशन निवेश में नए एसेट क्लास के दीर्घकालिक समावेशन की जांच के लिए एक समिति गठित की।

• The committee will be chaired by Narayan Ramachandran.

• इस समिति के अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन होंगे।

• The objective of the committee is to improve returns for subscribers under the National Pension System (NPS).

• समिति का उद्देश्य National Pension System (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना है।

• According to the data, the total number of subscribers under NPS reached 2.17 crore in FY26.

• उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार FY26 में NPS के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.17 करोड़ तक पहुँच गई।
• The total pension corpus under NPS increased to around ₹15.95 lakh crore.
• NPS के अंतर्गत कुल पेंशन कॉर्पस बढ़कर लगभग ₹15.95 लाख करोड़ हो गया।
• PFRDA regulates and supervises pension-related activities in India.
• PFRDA भारत में पेंशन संबंधी गतिविधियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• PFRDA Full Form – Pension Fund Regulatory and Development Authority
• PFRDA का पूर्ण रूप – पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण
• PFRDA Established – 2003
• PFRDA की स्थापना – 2003
• PFRDA Headquarters – New Delhi
• PFRDA मुख्यालय – नई दिल्ली
• Chairman of PFRDA – Sivasubramanian Ramann
• PFRDA के अध्यक्ष – शिवसुब्रमणियन रमण

Ques : LIC has increased its stake in which public sector bank to 6.06%?
प्रश्न: एलआईसी ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.06% की है?

A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
C) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
D) Indian Bank / इंडियन बैंक
E) UCO Bank / यूको बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• LIC has increased its stake in Central Bank of India from 3.16% to 6.06%.
• एलआईसी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 3.16% से बढ़ाकर 6.06% कर दी है।
• LIC purchased 26.26 crore shares through market purchase on May 22.
• एलआईसी ने 22 मई को बाजार से 26.26 करोड़ शेयर खरीदे।
• The additional acquisition accounts for 2.901% stake in the bank.
• यह अतिरिक्त खरीद बैंक में 2.901% हिस्सेदारी के बराबर है।
• Central Bank of India informed the stock exchanges about the stake increase.
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजों को इस हिस्सेदारी वृद्धि की जानकारी दी।
• Shares of Central Bank of India closed at ₹31.29 on BSE.
• बीएसई पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ₹31.29 पर बंद हुआ।
• LIC shares closed 2.93% higher at ₹837.20.
• एलआईसी के शेयर 2.93% बढ़कर ₹837.20 पर बंद हुए।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• LIC Foundation Year – 1956
• एलआईसी स्थापना वर्ष – 1956
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• CEO and MD of LIC : Shri R. Doraiswamy
• एलआईसी के सीईओ और एमडी: श्री आर. दोरैस्वामी
• Tagline – Yogakshemam Vahamyaham
• टैगलाइन – योगक्षेमं वहाम्यहम्
• Central Bank of India Foundation Year – 1911
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष – 1911
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• MD & CEO – Shri Kalyan Kumar
• एमडी एवं सीईओ – श्री कल्याण कुमार
• Tagline – Central to you since 1911
• टैगलाइन – Central to you since 1911

Ques: Who has been approved by the Reserve Bank of India (RBI) as the part-time Chairman of Federal Bank for a period of three years?

प्रश्न: Reserve Bank of India (RBI) ने Federal Bank के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में तीन वर्षों के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है?

A) KVS Manian / केवीएस मणियन

B) Elias George / एलियास जॉर्ज

C) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन

D) Rajesh Gopinathan / राजेश गोपीनाथन

E) Sandeep Bakhshi / संदीप बख्शी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India (RBI) approved the appointment of Elias George as the part-time Chairman of Federal Bank for a period of three years.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एलियास जॉर्ज की Federal Bank के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में तीन वर्षों के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी।

• Elias George has been serving as an independent director on the board of the bank.

• एलियास जॉर्ज बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

• Federal Bank is one of India's leading private sector banks.

• Federal Bank भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है।

• The appointment reflects RBI's role in regulating and approving key positions in the banking sector.

• यह नियुक्ति बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख पदों की निगरानी और अनुमोदन में RBI की भूमिका को दर्शाती है।

• Federal Bank continues to expand its banking and digital financial services across India.

• Federal Bank भारतभर में अपनी बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Federal Bank Founded – 23 April 1931
- Federal Bank की स्थापना – 23 अप्रैल 1931
- Federal Bank Headquarters – Kochi, Kerala
- Federal Bank मुख्यालय – कोच्चि, केरल
- MD & CEO of Federal Bank – KVS Manian
- Federal Bank के MD एवं CEO – केवीएस मणियन
- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- RBI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Kerala Capital – Thiruvananthapuram
- केरल की राजधानी – तिरुवनंतपुरम

Ques : RBI and NPCI are considering linking ATM interchange fees with which index?

प्रश्न: RBI और NPCI एटीएम इंटरचेंज शुल्क को किस सूचकांक से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं?

A) Consumer Price Index (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)

B) Sensex Index (सेंसेक्स सूचकांक)

C) Wholesale Price Index (थोक मूल्य सूचकांक)

D) Repo Rate Index (रेपो रेट सूचकांक)

E) Industrial Growth Index (औद्योगिक वृद्धि सूचकांक)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) and National Payments Corporation of India (NPCI) are considering linking ATM interchange fees with the Wholesale Price Index (WPI).

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एटीएम इंटरचेंज शुल्क को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं।

• ATM operators are facing rising operational costs due to higher lease rentals, electricity bills and fuel prices.

• एटीएम ऑपरेटर बढ़े हुए किराये, बिजली बिल और ईंधन कीमतों के कारण बढ़ती परिचालन लागत का सामना कर रहे हैं।

• The ATM interchange fee was fixed at ₹17 in 2021 and later increased to ₹19 in 2025.

• एटीएम इंटरचेंज शुल्क वर्ष 2021 में ₹17 निर्धारित किया गया था, जिसे 2025 में बढ़ाकर ₹19 कर दिया गया।

• RBI and NPCI are also reviewing customer charges of ₹21–₹22 after the free monthly transaction limit is exhausted.

• आरबीआई और NPCI मुफ्त मासिक लेनदेन सीमा समाप्त होने के बाद ₹21–₹22 के ग्राहक शुल्क की भी समीक्षा कर रहे हैं।

• Linking interchange fees with WPI may allow automatic periodic revisions based on inflation trends.

• इंटरचेंज शुल्क को WPI से जोड़ने से मुद्रास्फीति के आधार पर समय-समय पर स्वतः संशोधन संभव हो सकेगा।

• The move aims to ensure sustainability and smooth functioning of ATM networks across the country.

• इस कदम का उद्देश्य देशभर में एटीएम नेटवर्क की स्थिरता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• NPCI Established – 2008
• NPCI की स्थापना – 2008
• Headquarter – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• MD & CEO – Dilip Asbe
• MD एवं CEO – दिलीप अस्बे

Ques: The Government of India plans to sell up to 2% stake in which company through OFS?

प्रश्न: भारत सरकार OFS के माध्यम से किस कंपनी में 2% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है?

A) SBI / एसबीआई

B) GIC / जीआईसी

C) LIC / एलआईसी

D) New India Assurance / न्यू इंडिया एश्योरेंस

E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India plans to divest around 2% stake in Life Insurance Corporation of India (LIC) through an Offer for Sale (OFS).

• भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) में लगभग 2% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है।

• The proposed stake sale may take place in late June or early July.

• प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में हो सकती है।

• The OFS is mainly aimed at institutional investors.

• यह OFS मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए लक्षित है।

• The government expects to raise nearly ₹10,000 crore through this divestment.

• सरकार को इस विनिवेश के माध्यम से लगभग ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद है।

• The government currently holds around 96.5% stake in LIC.

• वर्तमान में सरकार की LIC में लगभग 96.5% हिस्सेदारी है।

• LIC has been given time till May 2032 to meet SEBI's 25% minimum public shareholding norms.

• LIC को SEBI के 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए मई 2032 तक का समय दिया गया है।

• The proposed OFS is part of the government's broader disinvestment and

market compliance strategy.

• प्रस्तावित OFS सरकार की व्यापक विनिवेश और बाजार अनुपालन रणनीति का हिस्सा है।

Ques: What is the name of the new USD 10 billion financing facility launched by the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)?

प्रश्न: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा शुरू की गई नई 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सुविधा का नाम क्या है?

A) Energy, Food Security and Economic Resilience Facility (EFSERF) / एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलिएंस फैसिलिटी

B) Economic Stability Initiative / इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनिशिएटिव

C) Global Recovery Fund / ग्लोबल रिकवरी फंड

D) Sustainable Growth Facility / सस्टेनेबल ग्रोथ फैसिलिटी

E) Crisis Support Mechanism / क्राइसिस सपोर्ट मैकेनिज्म

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) launched a new USD 10 billion financing facility named the “Energy, Food Security and Economic Resilience Facility (EFSERF).”

• एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने “Energy, Food Security and Economic Resilience Facility (EFSERF)” नामक नई 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सुविधा शुरू की।

• The facility aims to help member countries tackle the economic impact arising from the ongoing Middle East conflict.

• इस सुविधा का उद्देश्य सदस्य देशों को जारी मध्य-पूर्व संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों से निपटने में सहायता करना है।

• AIIB will provide USD 10 billion in financial support over a period of two years.

• AIIB अगले दो वर्षों में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

• The initiative focuses on strengthening energy security, food security, and economic resilience among member countries.

• यह पहल सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

• AIIB is a multilateral development bank that supports infrastructure and sustainable development projects.

• AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो आधारभूत संरचना और सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• AIIB Full Form – Asian Infrastructure Investment Bank
• AIIB का पूर्ण रूप – एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
• AIIB Established – 2016
• AIIB की स्थापना – 2016
• AIIB Headquarters – Beijing, China
• AIIB मुख्यालय – बीजिंग, चीन
• AIIB Members – 111 member states
• AIIB के सदस्य – 111 सदस्य देश
• President of AIIB – Zou Jiayi
• AIIB के अध्यक्ष – Zou Jiayi

Ques: MobiKwik recently received RBI's in-principle approval for which licence?

प्रश्न: मोबिक्विक को हाल ही में RBI से किस लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है?

A) Small Finance Bank Licence / स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस

B) Insurance Broker Licence / इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस

C) Payment Aggregator-Physical (PA-P) Licence / पेमेंट एग्रीगेटर-फिजिकल लाइसेंस

D) NBFC Licence / एनबीएफसी लाइसेंस

E) Digital Banking Licence / डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Fintech company MobiKwik received the Reserve Bank of India's in-principle approval for a Payment Aggregator-Physical (PA-P) licence.

• फिनटेक कंपनी मोबिक्विक को भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर-फिजिकल (PA-P) लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।

• The licence will help MobiKwik expand its offline merchant payment infrastructure across India.

• यह लाइसेंस मोबिक्विक को भारतभर में ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने में मदद करेगा।

• The company identified small businesses, oil & gas outlets, and organised retail as key focus sectors.

• कंपनी ने छोटे व्यवसायों, तेल एवं गैस आउटलेट्स तथा संगठित रिटेल को प्रमुख फोकस क्षेत्र बताया है।

• MobiKwik aims to achieve 10x growth in its merchant business by FY28.

• मोबिक्विक का लक्ष्य FY28 तक अपने मर्चेंट बिजनेस में 10 गुना वृद्धि हासिल करना है।

• Co-founder & CEO Bipin Preet Singh stated that the approval strengthens the company's ability to scale merchant payments nationwide.

• सह-संस्थापक एवं CEO बिपिन प्रीत सिंह ने कहा कि यह मंजूरी कंपनी की देशभर में मर्चेंट पेमेंट सेवाओं को बढ़ाने की क्षमता को मजबूत करेगी।

• The approval is expected to strengthen digital payment infrastructure and offline payment acceptance in India.

• यह मंजूरी भारत में डिजिटल भुगतान अवसंरचना और ऑफलाइन भुगतान स्वीकृति प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- MobiKwik Founded – 2009
- मोबिक्विक की स्थापना – 2009
- Headquarters – Gurugram, Haryana
- मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा
- Co-founder & CEO – Bipin Preet Singh
- सह-संस्थापक एवं CEO – बिपिन प्रीत सिंह
- Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
- नियामक संस्था – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

Ques: Which programme launched by SIDBI aims to modernise 10,000 rural micro and artisan enterprises over the next three years?

प्रश्न: SIDBI द्वारा शुरू किया गया कौन-सा कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में 10,000 ग्रामीण सूक्ष्म एवं कारीगर उद्यमों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखता है?

A) Rural Growth Mission / ग्रामीण विकास मिशन

B) MSME Udaan Programme / एमएसएमई उड़ान कार्यक्रम

C) Gram Udyam Scheme / ग्राम उद्यम योजना

D) Digital MSME Initiative / डिजिटल एमएसएमई पहल

E) Modernisation of Rural Enterprises (MORE) Programme / मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेज (MORE) कार्यक्रम

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Modernisation of Rural Enterprises (MORE) Programme was launched by SIDBI to modernise 10,000 rural micro and artisan enterprises over the next three years.
- SIDBI द्वारा शुरू किया गया Modernisation of Rural Enterprises (MORE)

Programme अगले तीन वर्षों में 10,000 ग्रामीण सूक्ष्म एवं कारीगर उद्यमों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखता है।

• SIDBI also launched "SIDBI MachFin Mart," a digital platform for MSMEs.

• SIDBI ने MSMEs के लिए "SIDBI MachFin Mart" नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया।

• The platform will help MSMEs access machinery and modern technology through a structured marketplace.

• यह प्लेटफॉर्म MSMEs को संरचित मार्केटप्लेस के माध्यम से मशीनरी और आधुनिक तकनीक तक पहुँच प्रदान करेगा।

• SIDBI introduced the RRB Co-Lending Portal to support joint lending by SIDBI and Regional Rural Banks (RRBs).

• SIDBI ने SIDBI और Regional Rural Banks (RRBs) द्वारा संयुक्त ऋण सुविधा के लिए RRB Co-Lending Portal भी शुरू किया।

• The portal will help provide loans to MSMEs in rural and underserved areas.

• यह पोर्टल ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के MSMEs को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करेगा।

• These initiatives were announced during SIDBI's 37th Foundation Day celebration held in Mumbai.

• इन पहलों की घोषणा मुंबई में आयोजित SIDBI के 37वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SIDBI Full Form – Small Industries Development Bank of India

• SIDBI का पूर्ण रूप – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

• SIDBI Established – 2 April 1990

• SIDBI की स्थापना – 2 अप्रैल 1990

• SIDBI Headquarters – Lucknow, Uttar Pradesh

• SIDBI मुख्यालय – लखनऊ, उत्तर प्रदेश

• Chairman & Managing Director of SIDBI – Manoj Mittal

• SIDBI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – मनोज मित्तल

Ques: The newly launched LIC plans "New Jeevan Sathi" are mainly designed for whom?

प्रश्न: LIC द्वारा लॉन्च की गई "New Jeevan Sathi" योजनाएँ मुख्य रूप से किनके लिए बनाई गई हैं?

A) Senior Citizens / वरिष्ठ नागरिक

B) Students / छात्र

C) Married Couples / विवाहित दंपत्ति

D) Farmers / किसान

E) Government Employees / सरकारी कर्मचारी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) launched two new joint life insurance plans.

• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने दो नई संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ शुरू कीं।

• The two plans are New Jeevan Sathi Single Premium (Plan 888) and New Jeevan Sathi Limited Premium (Plan 889).

• ये दो योजनाएँ New Jeevan Sathi Single Premium (Plan 888) और New Jeevan Sathi Limited Premium (Plan 889) हैं।

• Both plans are joint life savings and protection products designed for married couples.

• दोनों योजनाएँ विवाहित दंपत्तियों के लिए संयुक्त जीवन बचत और सुरक्षा उत्पाद हैं।

• The policies cover a married individual and his/her spouse under a single policy.

• ये योजनाएँ एक ही पॉलिसी के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को कवर करती हैं।

• The minimum basic sum assured under both plans is ₹3 lakh.

• दोनों योजनाओं में न्यूनतम मूल बीमित राशि ₹3 लाख है।

• The minimum entry age for purchasing the plans is 18 years.

• इन योजनाओं को खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

• Both policies provide guaranteed additions that increase maturity or death benefits.

• दोनों योजनाएँ गारंटीड एडिशन प्रदान करती हैं, जिससे मैच्योरिटी या मृत्यु लाभ बढ़ता है।
• The plans became available for purchase from 1 June 2026.
• ये योजनाएँ 1 जून 2026 से खरीद के लिए उपलब्ध हो गईं।
• LIC CEO & MD Siddhartha Mohanty launched the new policies.
• LIC के CEO एवं MD सिद्धार्थ मोहंती ने नई योजनाओं को लॉन्च किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• LIC Established – 1 September 1956
• एलआईसी की स्थापना – 1 सितंबर 1956
• LIC Headquarters – Mumbai
• एलआईसी मुख्यालय – मुंबई
• LIC Motto – "Yogakshemam Vahamyaham"
• एलआईसी का आदर्श वाक्य – "योगक्षेमं वहाम्यहम्"
• Insurance Regulatory Body – IRDAI
• बीमा नियामक संस्था – IRDAI

Ques: According to the RBI's new clarification, after completing 10 years of continuous service, a director of a co-operative bank can be reappointed to the same board only after what period?
प्रश्न: RBI के नए स्पष्टीकरण के अनुसार, सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, उसी बोर्ड में पुनर्नियुक्ति कितने समय बाद हो सकती है?

A) 1 year / 1 वर्ष
B) 2 years / 2 वर्ष
C) 3 years / 3 वर्ष
D) 5 years / 5 वर्ष
E) 10 years / 10 वर्ष

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) stated that a director on the board of co-operative banks who has served continuously for 10 years can be reappointed only after a three-year cooling-off period.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि सहकारी बैंक के बोर्ड में लगातार 10 वर्ष तक सेवा देने वाला निदेशक केवल तीन वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद ही पुनर्नियुक्त हो सकता है।

• During the cooling-off period, the individual cannot be associated with the same bank in any capacity except as a regular member or customer.

• कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति उसी बैंक से किसी भी रूप में जुड़ा नहीं रह सकता, सिवाय सामान्य सदस्य या ग्राहक के रूप में।

• However, such individuals can become directors on the board of another co-operative bank during this period.

• हालांकि, इस अवधि में वे किसी अन्य सहकारी बैंक के बोर्ड में निदेशक बन सकते हैं।

• RBI clarified that while calculating continuous tenure, service in Urban Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative Banks, and Central Co-operative Banks will be counted together.

• RBI ने स्पष्ट किया कि निरंतर कार्यकाल की गणना करते समय Urban Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative Banks तथा Central Co-operative Banks में दी गई सेवा को एक साथ जोड़ा जाएगा।

• Periods of service separated by breaks of less than three years will also be counted together.

• तीन वर्ष से कम के अंतराल से अलग हुई सेवाओं को भी एक साथ गिना जाएगा।

• The proposal is in line with the Banking Regulation (Amendment) Act.

• यह प्रस्ताव Banking Regulation (Amendment) Act के अनुरूप है।

• The Act increased the maximum continuous tenure for directors of co-operative banks from eight years to ten years.

• इस अधिनियम के तहत सहकारी बैंकों के निदेशकों की अधिकतम निरंतर सेवा अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है।

Ques: Under the CGSMFI 2.0 scheme, the NCGTC has raised the individual loan limit for large Microfinance Institutions (MFIs) to how much amount?
प्रश्न: CGSMFI 2.0 योजना के तहत, NCGTC ने बड़े माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के लिए व्यक्तिगत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि कर दिया है?

A) ₹500 crore / ₹500 करोड़
B) ₹750 crore / ₹750 करोड़
C) ₹1,000 crore / ₹1,000 करोड़
D) ₹1,500 crore / ₹1,500 करोड़
E) ₹2,000 crore / ₹2,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC) has revised the loan limit for large Microfinance Institutions (MFIs) from ₹300 crore to ₹1,000 crore under CGSMFI 2.0.
• नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ने CGSMFI 2.0 के तहत बड़े माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के लिए ऋण सीमा को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया है।
• Large MFIs are defined as institutions having Assets Under Management (AUM) of ₹2,000 crore and above.
• बड़े एमएफआई वे संस्थान हैं जिनकी प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) ₹2,000 करोड़ या उससे अधिक है।
• The revised loan amount is subject to a ceiling of 20% of the institution's AUM.
• संशोधित ऋण राशि संबंधित संस्थान के AUM के अधिकतम 20% तक सीमित रहेगी।
• The Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions 2.0 (CGSMFI 2.0) came into effect on 20 March 2026.
• माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 (CGSMFI 2.0) 20 मार्च 2026 से लागू हुई।
• The overall guarantee issuance under the scheme has been capped at

₹20,000 crore.

• इस योजना के तहत कुल गारंटी जारी करने की सीमा ₹20,000 करोड़ निर्धारित की गई है।

• Lenders are required to allocate at least 5% of the total loan amount to small MFIs and 10% to medium-sized MFIs.

• ऋणदाताओं को कुल ऋण राशि का कम से कम 5% छोटे एमएफआई और 10% मध्यम आकार के एमएफआई को देना अनिवार्य है।

• The maximum tenure of loans under the scheme is 3 years, including a 1-year moratorium and 2 years repayment period.

• योजना के तहत ऋण की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष का मोराटोरियम और 2 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि शामिल है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• NCGTC Ownership – Wholly owned by Government of India
• NCGTC स्वामित्व – पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में
• CGSMFI Full Form – Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions
• CGSMFI का पूर्ण रूप – Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions
• MFI Full Form – Microfinance Institution
• MFI का पूर्ण रूप – माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन
• AUM Full Form – Assets Under Management
• AUM का पूर्ण रूप – एसेट्स अंडर मैनेजमेंट